R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2024-26

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 22 । अंक : 24
16 से 30 सितंबर 2024
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

कानून सख्त अपराधी मस्त

भारत में महिलाओं के विरुद्ध बढ़े अपराध, नाकाफी साबित हो रहे हैं उपाय

तीन नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद भी अपराधियों में खौफ नहीं

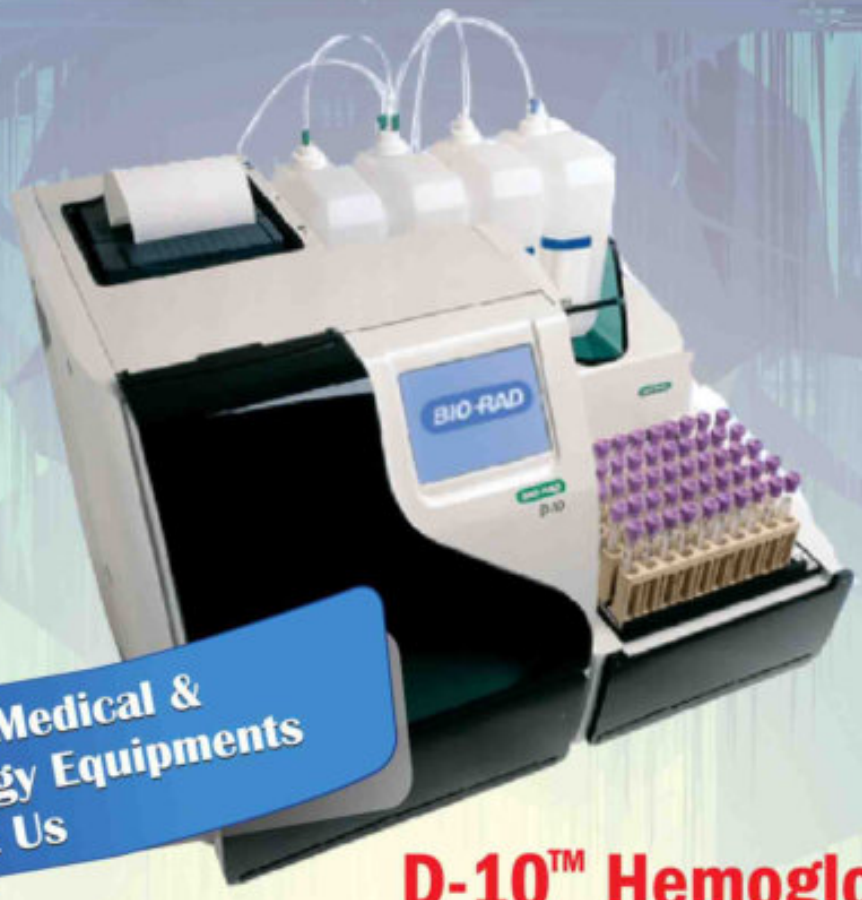

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

इस अंक में

उपलब्धि

8 | आयुष सुविधा देने में मप्र...

शहरी क्षेत्र के सभी 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सुविधाएं देने वाला मप्र देश का पहला राज्य बन गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के 1440 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 695 में आयुष सुविधाएं उपलब्ध हैं और शेष में बढ़ाई जा...

डायरी

10-11 | सुलेमान बाहर, जैन-राजौरा...

मुख्य सचिव वीरा राणा का छह माह का एक्सटेंशन इसी महीने की 30 तारीख को खत्म हो जाएगा। सरकार ने उनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए केंद्र को प्रस्ताव नहीं भेजा है। ऐसे में प्रदेश के अगले मुख्य सचिव के लिए कयासों का दौर...

चौसर

14 | परिसीमन से सारे समीकरण साधे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परिसीमन आयोग का एक ऐसा दांव चल दिया है जिससे वे कई समीकरणों को साधकर अपनी साख को मजबूत बनाएंगे। गौरतलब है कि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से उठ रही नए जिलों की मांग के बाद अब मप्र...

कर्मचारीनामा

18 | मप्र के कर्मचारियों को कैशलेस इलाज

मप्र के 7.5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों, साढ़े चार लाख पेंशनर्स और करीब 3 लाख निगम-मंडलों के कर्मचारियों को अब कैशलेस इलाज मिलेगा। इसके लिए मप्र सरकार उप्र, हरियाणा और राजस्थान सरकार की तर्ज पर सरकारी कर्मचारियों के लिए इलाज की आयुष्मान...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। 1 जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारत साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। जिनके आधार पर देश और प्रदेश में शासन-प्रशासन सुशासन का दम भर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में कमी नहीं आ रही है। आलम यह है कि सख्त कानून के बाद भी देश में अब भी हर दिन 86 बलात्कार हो रहे हैं।

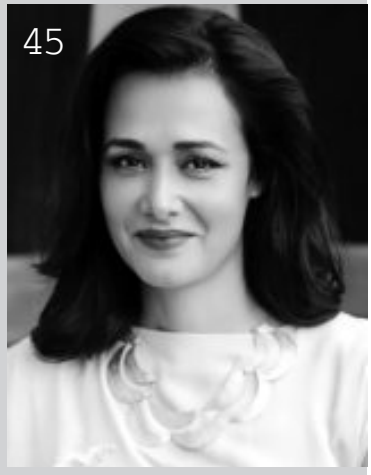

राजनीति

30-31 | संघ के बिना कुछ नहीं...

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की केरल के पलक्कड़ में आयोजित 3 दिवसीय बैठक के दौरान कई ऐसे मुद्दे रहे जिन पर विस्तार से चर्चा हुई। देश में जाति जनगणना कराना, डीलिमिटेशन और महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण, केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की अखिल भारतीय...

महाराष्ट्र

35 | अजित ने बढ़ाई महायुति में टेंशन

महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राज्य में विधानसभा की 288 सीटें हैं। सूबे के दो बड़े गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर मंथन चल रहा है। कहां से कौन लड़ेगा, किसे टिकट दिया जाए, ये सवाल एमवीए और महायुति के सामने...

झारखंड

38 | कितना चटकेगा चंपाई रंग...

छह महीने के भीतर तस्वीर इस कदर बदल जाएगी, शायद इसका एहसास खुद पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को भी नहीं रहा होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के सुप्रीमो शिबू सोरेन के खासमखास और पार्टी के पुराने सिपाही रहे चंपाई की राहें अब जुदा हो गई हैं।

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

पाक्षिक अक्स

वर्ष 22, अंक 24, पृष्ठ-48
16 से 30 सितंबर, 2024

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com
W ebsite : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

प्रमुख संवाददाता

भावना सक्सेना-भोपाल, जय मतानी-भोपाल,
हर्ष सक्सेना-भोपाल,
दक्ष दवे-इंदौर, संदीप वर्मा-इंदौर,
विपिन कंधारी-इंदौर, गौरव तिवारी-विदिशा,
ज्योत्सना यादव-गंजबासौदा, राजेश तिवारी-उज्जैन,
टोनी छाबड़ा-धार, आशीष नेमा-नरसिंहपुर,
अनिल सोडानी-नई दिल्ली, हसमुख जैन-मुंबई,
इंद्र कुमार बिन्नानी-पुणे।

प्रदेश संवाददाता

पारस सरावगी (इंदौर)
09329586555
नवीन रघुवंशी (इंदौर)
09827227000 (इंदौर)
धर्मेन्द्र कथूरिया (जबलपुर)
098276 18400
श्यामसिंह सिकरवार (उज्जैन)
094259 85070
सुभाष सोमानी (रतलाम)
089823 27267
मोहित बंसल (विदिशा)
075666 71111

क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी, फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

अपनी बात

आप गड्ढों के शहर भोपाल में हैं...संभलिए

सोशल मीडिया पर भोपाल की सड़कों को लेकर तरह-तरह के मीम्स वायरल हो रहे हैं... इनमें से एक है...

पग-पग पर गड्ढे, गड्ढों में भरा पानी
स्मार्ट सिटी भोपाल की यही कहानी...

उपरोक्त पंक्तियां देश के हृदय प्रदेश की बदहाल सड़क पर सटीक बैठ रही हैं। आलम यह है कि यहां की सड़क में गड्ढे नहीं हैं, बल्कि गड्ढों में थोड़ी-थोड़ी सड़क नजर आ रही है। दरअसल, देश के सबसे खूबसूरत शहर भोपाल को हमारे माननीयों ने पेरिस बनाने का सपना दिखाकर विकास की आधी-अधूरी योजनाओं-परियोजनाओं का मकड़जाल इस कदर बुन डाला है कि अब शहर बूचड़खाने से भी बदतर नजर आने लगा है। अब तो लोग कहने लगे हैं कि जरा संभलकर चलिए जनाब, हर राह में सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। हालांकि जिन क्षेत्रों में माननीय और अधिकारी रहते हैं यानी 4 इमली, 74 बंगला, लिंक रोड नं.-2, ये ऐसे क्षेत्र हैं, जहां की सड़कें चकाचक हैं, बाकी शहर की सड़कों का हाल बदहाल है। शहर की सड़कों का हाल कैसा है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर इस तरह बयां किया जा रहा है... कहीं टूटी, कहीं फूटी, कहीं गड्ढे हैं दिखते, नागिन सी रोडों पर हैं हिचके बड़े मिलते... कौन कहता है हमसे, रहा भोपाल है पीछे, सड़के ऐसी बनाई हैं समुद्र ऊपर सड़क नीचे... होंगी सड़कें तुम्हारी उड़न छू मतवाली, मगर यहां दौड़ती हैं दरियाओं में गाड़ी... कहीं पेंदा, कहीं गिट्टी, कहीं डामर को हैं भरते, भारी कर जेब अपनी, वादा चुनावी हैं करते। आलम यह है कि नगर निगम, पीडब्ल्यूडी लगातार दावे कर रहे हैं कि सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन स्थिति यह है कि एक-एक फीट गड्ढों वाली सड़कों पर चलना तो दूर उन्हें देखकर ही डर लगता है। सड़कों पर चलने वाला हर व्यक्ति पीड़ित है। सड़कों पर गड्ढे नहीं, बल्कि गड्ढों में सड़कें समा गई हैं। लोक निर्माण विभाग की बनाई गई शहर की प्रमुख सड़कों में से 70 फीसदी तो गारंटी पीरियड में ही खराब हो गई। यही हाल नगर निगम की सड़कों के हैं। भोपाल में नगर निगम और लोक निर्माण विभाग की 2593 किमी से ज्यादा लंबी सड़कें हैं। 240 से ज्यादा सड़कें टूटी-फूटी हालत में हैं। कोई 10 प्रतिशत तो कोई 80 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त। 45 किमी सड़कें तो ऐसी हैं, जिनमें गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। 35 किमी से ज्यादा लंबी एप्रोच रोड भी उखड़ चुकी है। नर्मदापुरम रोड पर रहने वाले 2.5 लाख से ज्यादा लोगों के लिए शहर की तरफ आने के लिए यह एकमात्र रोड है। इन लोगों के लिए ये गड्ढे रोज की मुसीबत हो गए हैं। मिस्रोद से रानी कमलापति स्टेशन तक 5000 से ज्यादा गड्ढे हैं। इस सड़क की मरम्मत गर्मी में की गई थी। जिसमें गिट्टी की एक लेयर डाली गई। अफसरों व ठेकेदारों ने महज दो दिनों में काम निपटा दिया। अब सड़क पर बारीक गिट्टियां निकल गई हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाओं का अंदेशा बना हुआ है। निर्माण एजेंसियों के अफसरों और ठेकेदारों ने वल्लभ भवन के आसपास की सड़कों तक को नहीं छोड़ा। पीएफ कार्यालय चौराहे से वल्लभ भवन तक की मुख्य सड़क उखड़ गई। रॉयल मार्केट से मॉडल स्कूल की सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। इसके अलावा मंदिर से होटल पैलेस मार्ग, भोपाल टॉकीज से रेलवे क्रॉसिंग मार्ग, अग्रसेन चौराहा से शाहजहांनाबाद मार्ग, स्टेट बैंक चौराहा से करबला, मनीषा मार्केट से हबीबगंज थाना सुभाष स्कूल, कलियासोत मुख्य नहर से आकृति ईको सिटी, जेके अस्पताल तिराहे से दानिश नगर चौराहा और आरआरएल से साकेत नगर तक सड़कों की हालत बदहाल है। यह हाल तब है जब हर साल करोड़ों रुपए राजधानी की सड़कों की मरम्मत पर खर्च किए जाते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जिन सड़कों से शहर की बड़ी आबादी गुजरती है, उन पर न तो माननीय और न ही अधिकारी ध्यान देते हैं।

- राजेन्द्र आगाल

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

लोगों को मिलेगा रोजगार

मप्र ने पिछले वर्षों में प्रगति और विकास के मार्ग पर तेजी से कदम बढ़ाए हैं। सरकार अब मप्र में निवेश के लिए उद्योगपतियों को बुला रही है। यह एक अच्छा प्रयास है। प्रदेश में आने वाले निवेश और उद्योगों से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिससे वे आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होंगे।

● **पारुल सिरोदिया,** बैतूल (म.प्र.)

बुंदेलखंड राज्य कब बनेगा

यूं तो बुंदेलखंड राज्य बनाने को लेकर कई बार बयानबाजी हुई, लेकिन चुनाव में कभी यह मुद्दा हावी नहीं हो पाया। अब तक हुए 17 लोकसभा चुनावों में पृथक बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा कभी जोर-शोर से नहीं उठ पाया। यहां तक कि बड़े सियासी दलों के घोषणा पत्रों में भी इसे कभी जगह नहीं मिली।

● **सुरेश मीना,** सागर (म.प्र.)

मजबूत हो कांग्रेस

लोकसभा चुनाव में मप्र में कांग्रेस अच्छा नहीं कर पाई, इस कारण सभी सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा। मप्र में कांग्रेस नेता बीते कई महीनों से पीसीसी के गठन का दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश पदाधिकारियों के नामों पर ही आम सहमति नहीं बन पा रही है। अब कांग्रेस को मजबूत होना होगा।

● **परशुराम शर्मा,** भोपाल (म.प्र.)

सदस्य जोड़ रही भाजपा

मप्र भाजपा ने अपने सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान के तहत पार्टी का लक्ष्य 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का है। इस बार, अभियान की सफलता से न केवल संगठन को मजबूती मिलेगी, बल्कि इससे जिलों के नेताओं का कद भी तय होगा। जो नेता ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने में सफल होंगे, उन्हें संगठन में बड़ा पद मिल सकता है। वहीं, निष्क्रिय नेताओं की सूची भी तैयार की जाएगी। भाजपा हर छह साल में नए सिरे से सदस्य बनाती है। पिछली बार भाजपा के 95 लाख सदस्य थे। इस बार 55 लाख अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया है। वहीं कांग्रेस भी अपने स्तर पर लोगों को जोड़ने का कार्य कर रही है।

● **फुलबीर सिंह,** मंदसौर (म.प्र.)

अब केंद्र की निगरानी में रहेंगे राज्य

हाल ही में वित्त मंत्रालय को फंड इस्तेमाल में राज्यों की तरफ से की जा रही गड़बड़ियों की सूचना दी गई है। एसएनए-स्पर्श व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग को भी आरबीआई में एक विशेष खाता (एसएनए) खोलना होगा जिसके जरिए फंड का वितरण किया जाएगा। इस नई व्यवस्था से केंद्र राज्यों के वित्त प्रबंधन पर इस हिसाब से नजर रख सकेगा कि कहीं किसी खास उद्देश्य से भेजे गए फंड का इस्तेमाल चुनावी वादों को पूरा करने के लिए तो नहीं किया जा रहा। यह सरकार का एक अच्छा कदम है।

● **प्रफुल्ल पांडे,** इंदौर (म.प्र.)

बाघों की सुरक्षा जरूरी

मप्र को पिछले कई सालों से टाइगर स्टेट का तमगा मिलता आ रहा है, लेकिन टाइगर की मौतों के मामले में भी मप्र पीछे नहीं है। प्रदेश में बीते कुछ महीनों से बाघों की मौत का सिलसिला जारी है। वर्ष 2024 में अब तक देश में कुल 75 टाइगर की मौत हुई है। मप्र के बाद दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र में 14 और तीसरे स्थान पर कर्नाटक में 12 टाइगर की मौत हुई है। सरकार को बाघों की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए।

● **मोहन उपाध्याय,** सीहोर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

गडकरी होंगे मुख्यमंत्री चेहरा!

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की गिनती उन भाजपा नेताओं में होती है जिनके संबंध प्रधानमंत्री मोदी से कभी सहज नहीं रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अतिविश्वस्त गडकरी की बतौर केंद्रीय मंत्री कार्य क्षमता का लोहा विपक्षी दल भी स्वीकारते हैं। वे उन पुराने भाजपा नेताओं में शुमार हैं जिन्हें पार्टी का वर्तमान नेतृत्व संदेह की दृष्टि से देखता है। दिल्ली के सत्ता गलियारों में हमेशा चर्चा रहती है कि बीते दस वर्षों के दौरान अकेले गडकरी ही ऐसे मंत्री रहे हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों में मोदी की नीतियों का खुला विरोध करते रहे हैं। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद 2022 में उन्हें भाजपा संसदीय बोर्ड से हटाने के पीछे एक बड़ा कारण उनका मोदी-शाह विरोधी होना बताया गया था। अब लेकिन इन्हीं गडकरी को महाराष्ट्र भेजे जाने की चर्चा जोरों पर है। कहा-सुना जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में केवल और केवल गडकरी ही भाजपा का बेड़ा पार करवाने की क्षमता रखते हैं इसलिए उन्हें सीएम फेस बनाकर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। गौरतलब है कि जोड़-जुगत कर बनी राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल होती नजर आ रही है और कांग्रेस नेतृत्व वाला गठबंधन लगातार महाराष्ट्र में अपनी जमीन मजबूत कर रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मोदी-शाह गडकरी के नाम पर सहमत होते हैं या नहीं।

अब क्या करेंगे जगन

लोकसभा और विधानसभा चुनावों में वाईएसआर कांग्रेस के बुरी तरह से हारने के बाद भी जगनमोहन रेड्डी ने केंद्र सरकार और भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा था कि चंद्रबाबू नायडू की तेलुगू देशम पार्टी के पास 16 लोकसभा सांसद हैं तो वाईएसआर कांग्रेस के पास भी 11 राज्यसभा और चार लोकसभा के यानी 15 सांसद हैं। संसद में उनकी ताकत नायडू से कम नहीं है। अब उनकी ताकत में बड़ी सेंध लग गई है। उनके दो राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। यही नहीं चर्चा है कि जगन के पांच और सांसद पार्टी छोड़ सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि अगर जगन के पांच सांसद टीडीपी के संपर्क में हैं तो उन्हें रोकने के लिए उनके पास क्या रास्ता है? अगर सांसदों ने सोच लिया है कि उनको सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ जाना है तो उन्हें रोकना मुश्किल होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जगनमोहन रेड्डी के पास एक रास्ता है। जिस तरह सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने 2019 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद टूट की आशंका को देखते हुए अपने विधायकों को भाजपा में शामिल करा दिया था इसी तरह जगन अपने सांसदों के अपनी चिर प्रतिद्वंद्वी टीडीपी में जाने से रोकने के लिए उन्हें खुद ही भाजपा में शामिल करा सकते हैं।

हरियाणा भाजपा में घमासान

हरियाणा में पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है। लेकिन इस बार एक ओर जहां भाजपा फिर सत्ता को बरकरार रखने का दावा कर रही है वहीं जमीन पर उसके खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी सहित तमाम मुद्दों और सर्वेक्षणों में पार्टी पिछड़ती दिख रही है। ऊपर से पार्टी के भीतर घमासान छिड़ा हुआ है। जिसने पार्टी की बेचैनी बढ़ाने का काम किया है। इसका अंदाजा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की सावधानी बरतने और टिकटों पर सहमति बन जाने के बाद दोबारा विचार करने के फैसले से लगाया जा सकता है। असल में बीते दिनों जींद में हुए पार्टी के कार्यक्रम में अमित शाह शामिल नहीं हुए और कहा जा रहा है कि जननायक जनता पार्टी के नेताओं को थोक में पार्टी में शामिल करने के भी वे पक्ष में नहीं हैं। फिर भी दो दिन में भाजपा ने जजपा के छह नेताओं, विधायकों और पूर्व मंत्रियों को भाजपा में शामिल कराया है। इसमें सबसे हैरानी वाला मामला देवेंदर सिंह बबली का है। वे भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। जजपा से बगावत करने के बाद से वे इधर-उधर भाग रहे थे। पहले वे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले और कुछ अन्य नेताओं को खट्टर से मिलवाया। लेकिन बाद में उनको लगा कि भाजपा पिछड़ रही है तो वे कांग्रेस की ओर दौड़ने लगे।

पवन का अगला कदम?

भोजपुरी सिनेमा और राजनीति में अपना दम दिखा चुके पवन सिंह ने हाल ही में जब से उत्तर प्रदेश के जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह से मुलाकात की है तब राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि पवन सिंह का अगला कदम क्या होगा? क्या राजनीति में लंबी पारी खेलने पर पवन विचार कर रहे है? असल में भोजपुरी सिनेमा के स्टार पवन सिंह साल 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ा। हालांकि वे चुनाव हार गए लेकिन दूसरे नंबर पर रहे। इसी से पवन सिंह की सियासी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार धनंजय सिंह राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं और पवन सिंह को बिहार में पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। माना जा रहा है कि इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए पवन सिंह और धनंजय सिंह की मुलाकात हुई थी। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब पवन सिंह पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं।

खतरे में दिग्गजों का भविष्य

लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद भाजपा के कई दिग्गज नेताओं का राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ता हुआ दिख रहा है। खासकर राजस्थान में पार्टी आलाकमान ने इन्हीं दिग्गज नेताओं के कहने पर टिकट बांटे थे, लेकिन उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं आया। हालांकि इनमें से कुछ नेताओं को फिर भी उम्मीद थी कि पार्टी में इतने सालों की निष्ठा का प्रतिफल राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में इन्हें मिलेगा, लेकिन वो भी रही-सही कसर बाहरी उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू के नाम की घोषणा के साथ खत्म हो गई। अब सवाल उठ रहे हैं कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर सहित कई दिग्गजों का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राजस्थान भाजपा के दिग्गज नेता राजेंद्र सिंह राठौड़, सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर आदि के राजनीतिक करियर को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है।

जाऊंगा तो नर्मदा माई के पास

हर अधिकारी की मंशा होती है कि उसकी इच्छानुसार उसे पोस्टिंग मिले। लेकिन अधिकांश अधिकारी शासन की मंशा के आगे मजबूर होते हैं और उन्हें जहां पदस्थ किया जाता है, वहां जाकर कार्यभार संभाल लेते हैं। लेकिन प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में एक प्रमोटी आईपीएस अधिकारी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। इसकी वजह यह है कि साहब ने अपनी पदस्थापना के लिए इच्छा जाहिर कर दी है और साफ-साफ शब्दों में कह दिया है कि मैं जाऊंगा तो वहीं जाऊंगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य पुलिस सेवा से प्रमोट होकर भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी बनने वाले इन साहब ने तबादले को लेकर अपनी मंशा जाहिर करते हुए कहा है कि मैं जाऊंगा तो नर्मदा माई के पास ही जाऊंगा। यही नहीं साहब ने इसके लिए साफ-साफ शब्दों में कह दिया है कि जो भी करना होगा, वह मैं करने को तैयार हूं। यानि साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई उन्हें उनकी पसंद के जिले में पदस्थ करवा दे और इसके लिए जो भी चढ़ावा लगेगा वे देने को तैयार हैं। वहीं साहब की नर्मदा माई के पास जाने की मंशा को लेकर उनके साथियों में इस बात का मंथन शुरू हो गया है कि आखिर उन्होंने ऐसी शर्त क्यों रखी। अब लोग अपने-अपने अंदाज से मप्र की जीवन रेखा नर्मदा किनारे के जिलों का आंकलन करने लगे हैं कि आखिर इन जिलों में ऐसी कौन-सी अनोखी बात है जिसके लिए साहब कुछ भी करने को तैयार हैं।

डीएफओ को सौंपा कामकाज

मंत्री पद मिलते ही माननीय उन अधिकारियों-कर्मचारियों को अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश में जुट जाते हैं, जो जुगाड़ू होते हैं। दरअसल, ये वे लोग होते हैं जो मंत्रीजी की हर मनोकामना को पूरा करने का मंत्र जानते हैं। प्रदेश सरकार में एक मंत्रीजी ने ऐसे ही अधिकारी को साधकर अपना कामकाज सौंप दिया है। जब इसकी पड़ताल की गई तो पता लगा कि कांग्रेस से हाल ही में भाजपा में शामिल हुए इन माननीय को उस विभाग की कमान सौंपी गई है, जिसमें जंगल का कानून चलता है। सूत्र बताते हैं कि विभाग की कमान संभालते ही मंत्रीजी ने सबसे पहले विभाग के कमाऊ पुत्र की खोज शुरू की। इस दौरान उन्हें किसी ने एक आदिवासी जिले में पदस्थ एक डीएफओ का नाम सुझाया। मंत्रीजी ने उन्हें बुलाकर उनसे सबसे पहले विभाग के बारे में जानकारी प्राप्त की, फिर उनकी विश्वसनीयता का आंकलन कर उन्हें विभाग में होने वाले ट्रांसफर-पोस्टिंग के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण फाइलों का काम सौंप दिया। बताया जाता है कि साहब मंत्रीजी की मंशानुसार पूरी ईमानदारी से कामकाज संभाले हुए हैं। जबकि ऑफिशियली ये मंत्री के स्टाफ में पदस्थ नहीं हैं। मंत्रीजी भी उनके कामकाज से काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी मंशा पूरी हो रही है। यहां बता दें कि ये अधिकारी पूर्व मंत्री के भी खास रहे हैं।

आखिर क्यों हटाए गए कप्तान

प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों यह चर्चा खूब चल रही है कि राजस्थान की सीमा को छू रहे एक जिले में पदस्थ पुलिस कप्तान को आखिरकार सरकार ने क्यों हटा दिया। जानकारों का कहना है कि मालवा के इस जिले के कप्तान को हटाने की कहानी फिल्मों वाली है। यानि कई तरह की कहानियां बुनी जा रही हैं। लोगों द्वारा लगाए जा रहे कयासों के अनुसार साहब को हिंदू विरोधी मानसिकता के कारण हटाया गया है। जब इसकी पड़ताल की गई तो यह तथ्य सामने आया कि एक मूर्ति में की गई तोड़फोड़ के कारण साहब को हटाया गया। जबकि सीसीटीवी के वीडियो में यह साफ दिख रहा है कि मूर्ति में कोई तोड़फोड़ नहीं की गई है। वहीं दूसरी कहा यह कही जा रही है कि जिले में एक गंभीर अपराध के मामले में कप्तान साहब ने 14-15 लोगों को आरोपी बनाया था, जबकि दो लोग उसमें पाक साफ थे। सूत्र बताते हैं कि उन दो लोगों के लिए हायर अथॉरिटी का भी फोन साहब के पास पहुंचा था, लेकिन साहब ने न जांच की और न ही पड़ताल। उन्होंने उन दो लोगों को भी मामले में फंसा दिया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर साहब के खिलाफ आक्रोश का माहौल था ही कि इसी दौरान जिले में धार्मिक उन्माद इस कदर फैला कि उसे शांत करने के लिए साहब की बलि दे दी गई। आज स्थिति यह है कि साहब अघोषित तौर पर हिंदुत्व के सबसे बड़े विरोधी बना दिए गए हैं। यही कारण है कि नई पदस्थापना के दौरान भी उनका विरोध किया गया।

खुद तोड़ रहे नियम

पहली बार सरकार में मंत्री बने एक माननीय पर सत्ता का रसूख इस कदर हावी है कि वे कायदे-कानून तोड़ने में तनिक भी हिचक नहीं करते हैं। ये वही माननीय हैं जो मंचों से लोगों को नैतिकता और अनुशासन का पाठ पढ़ाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ते हैं। अभी गत दिनों परिवहन व्यवस्था पर माननीय ने एक सांसद को अनुशासन का पाठ पढ़ाया था। लेकिन गत दिनों उन्होंने खुद ही अनुशासन तार-तार कर दिया। सूत्रों का कहना है कि माननीय सरकार के मुखिया के पिताश्री को श्रद्धांजलि देकर राजधानी आ रहे थे, इस दौरान वे सत्ता के रसूख पर इस कदर सवार थे कि रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल के रेड होने के बाद भी रुके नहीं और नियमों को ताक पर रखकर दनदनाते हुए गाड़ी लेकर निकल गए। जिन लोगों ने इस दृश्य को देखा वे हतप्रभ रह गए। बता दें कि ये माननीय सरकार में वैसे तो राज्यमंत्री हैं, लेकिन ये अपने आपको सबसे रसूखदार मानते हैं। ऐसे ही कुछ किस्से इनकी विधानसभा क्षेत्र के भी हैं। ये कई बार विवादों में फंस चुके हैं। अपने पद की प्रतिष्ठा को दरकिनार कर ये अपने परिजनों के समर्थन में थानों में भी हो आए हैं।

धूम मचा ले... धूम

फिल्म धूम तो आपने देखी ही होगी। उसके गाने धूम मचा ले... धूम की तर्ज पर विंध्य क्षेत्र के एक जिले में पदस्थ कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक लूट मचाए हुए हैं। यह हमारा नहीं बल्कि खुद उक्त जिले के तीन विधायकों का दावा है। इन विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि जिले में ये दोनों अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और खुलेआम दोनों हाथों से काली कमाई कर रहे हैं। गौरतलब है कि जिस जिले की हम बात कर रहे हैं, वह जिला विंध्य क्षेत्र का सबसे बड़ा खनिज संपदा वाला जिला है। इस जिले में काले सोने यानि कोयले का कारोबार सबसे अधिक होता है। इसके अलावा यहां बड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं। यानि औद्योगिक कारोबार वाले इस जिले में काला धंधा चरम पर होता है और काली कमाई भी खूब होती है। विधायकों का दर्द इस बात को लेकर है कि उपरोक्त दोनों अधिकारी उनकी कमाई पर कुंडली मारे हुए हैं। अब देखना यह है कि सरकार विधायकों की शिकायत पर कलेक्टर और एसपी के खिलाफ कोई कदम उठाती है या उनकी ऐसी ही चलती रहेगी।

आयुष सुविधा देने में मप्र अव्वल

शहरी क्षेत्र के सभी 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सुविधाएं देने वाला मप्र देश का पहला राज्य बन गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के 1440 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 695 में आयुष सुविधाएं उपलब्ध हैं और शेष में बढ़ाई जा रही हैं। आदिवासी क्षेत्रों में 228 प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष डॉक्टर उपलब्ध हैं। इसके आधार पर मप्र देश में तीसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर 296 की संख्या के साथ उड़ीसा और 279 की संख्या के साथ छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है।

मप्र वर्ष 2005 से ग्रामीण क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी करने वाले देश के पहले छह राज्यों में शामिल हो गया है। इसके अलावा सबसे ज्यादा संख्या में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों वाले दस राज्यों में सातवें स्थान पर आ गया है। यह तथ्य हाल ही में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया-इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्ट में सामने आया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में भी मप्र पहले छह राज्यों में शामिल है। देश में कुल 5491 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। मप्र में इनकी संख्या 332 है। रिपोर्ट के अनुसार सब डिविजनल स्तर पर संचालित अस्पतालों और जिला अस्पतालों की संख्या के हिसाब से मप्र देश के प्रथम तीन राज्यों में शामिल है। यहां सब डिविजनल अस्पतालों की संख्या 144 है। तमिलनाडु 281 की संख्या के साथ पहले और कर्नाटक 147 की संख्या के साथ दूसरे नंबर पर है। प्रदेश में जिला अस्पतालों की संख्या 52 है। इन मामले में मप्र देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि 125 स्वास्थ्य केंद्रों के साथ उप्र पहले और दिल्ली 40 के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

रिपोर्ट में सभी प्रदेशों में उप स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य, संभाग स्तरीय अस्पतालों और जिला अस्पतालों में आधारभूत स्वास्थ्य अधोसंरचना, तकनीकी रूप से दक्ष स्टाफ एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की पदस्थापना का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी राज्यों में आधारभूत अधोसंरचनाओं में बढ़ोतरी का तथ्यात्मक विश्लेषण किया गया है। विशेषज्ञ चिकित्सकों, सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, शिशु रोग विशेषज्ञ, फार्मासिस्ट लैब टेक्निशियन नर्सिंग स्टाफ और रेडियोग्राफर की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में गांवों में सबसे ज्यादा 68 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छिंदवाड़ा में है। इसके बाद खरगोन में 58 और रीवा में 46 हैं। शहरों में भोपाल में सबसे ज्यादा 54 केंद्र है। दूसरे नंबर पर इंदौर-40 और तीसरे नंबर पर जबलपुर-36 है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़वानी में 14, मंडला में 12 और सतना में 11 हैं। कुल 21 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सबसे ज्यादा तीन भोपाल में है।

रिपोर्ट के अनुसार मप्र के 55,885 गांवों में 10,258 उप स्वास्थ्य केंद्र सेवाएं दे रहे हैं। गांवों में 1440 और शहरी क्षेत्र में 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। गांवों में 332 और शहरों में 21 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। सब डिविजन स्तर पर 144 और जिला स्तर पर 52 अस्पताल संचालित हैं। रिपोर्ट के अनुसार 13 मेडिकल कॉलेज कार्यरत हैं। धार जिले में सबसे ज्यादा 479 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। दूसरे नंबर पर बड़वानी (329), तीसरे स्थान पर रीवा (326) और चौथे पर सतना (302) हैं। रिपोर्ट में गांवों और शहरों में स्वास्थ्य अधोसंरचना में मप्र में वर्ष 2005 से 2023 तक हुई प्रगति का आंकलन किया गया है।

वर्ष 2005 में गांवों में उप स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 8874 थी जो अब 10258 हो गई है। इनमें से 3996 उप स्वास्थ्य केंद्र सरकारी भवनों में लग रहे थे, अब 8626 सरकारी भवन में है। किराये के भवनों में लग रहे उप स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 4878 थी जो अब कम होकर 667 हो गई है। आज 965 केंद्र किराया-मुक्त पंचायत भवनों में संचालित हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 2005 में 1192 से बढ़कर 1440 हो गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या वर्ष 2005 में 229 से बढ़कर 332 हो गई है और इनमें से 328 सरकारी भवनों में संचालित हैं। शेष तीन के लिए भवन निर्माण का काम जारी है।

● **प्रवीण सक्सेना**

ऐसे काम करता है स्वास्थ्य सेवा तंत्र

उप स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था और समुदाय के बीच पहली संपर्क संस्था है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पोषण, टीकाकरण, दस्त नियंत्रण, संचारी और गैर-संचारी रोगों के नियंत्रण के संबंध में निचले स्तर पर सेवाएं दी जाती है। आदर्श स्थिति में एक उपकेंद्र में कम से कम एक सहायक नर्स मिडवाइफ, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपलब्ध रहते हैं। यह कम से कम चार गांव को सेवाएं देता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समुदाय और चिकित्सा अधिकारी के बीच की संपर्क संस्था के रूप में काम करता है। यह 6 उप केंद्रों के लिए एक रेफरल इकाई है। इसमें 4 से 6 बिस्तर की सुविधा होती है और यह 26 गांव को कवर करता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 चिकित्सा विशेषज्ञ, पैरामेडिकल स्टाफ, फिजिशियन, प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं। इसमें एक ऑपरेशन थिएटर, एक्स-रे, लेबर रूम और प्रयोगशाला सुविधाओं के साथ 30 बिस्तर की क्षमता रहती है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कम से कम चार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए एक रेफरल इकाई के रूप में संचालित होता है। यह 121 गांव को सेवाएं दे सकता है। उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिलकर प्रदेश में 308252.00 वर्ग किलोमीटर में सेवाएं दे रहे हैं। इसमें 93 हजार वर्ग किलोमीटर जनजाति क्षेत्र है।

अब बनेगी मंडी की सरकार!

मप्र की कृषि उपज मंडियों के संचालन मंडल का कार्यकाल समाप्त हुए 7 साल हो गए हैं। अब जाकर प्रदेश में कृषि उपज मंडी समितियों के चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। इनसे जुड़े लाखों किसान और वर्तमान में अधिकारी प्रशासक के तौर पर काम कर रहे हैं। किसी भी स्थिति में इनकी अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं रखी जा सकती है। इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी लग चुकी है। यही स्थिति सहकारी समितियों की भी है। पहले अधिकारियों के स्थान पर किसानों के प्रतिनिधियों को प्रशासक मनोनीत किया जाएगा। समितियों के प्रमुख काम किसानों को कृषि कार्य के लिए ऋण प्रदान करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न वितरण, खाद-बीज की दुकानों का संचालन और समर्थन मूल्य पर उपज का उपार्जन करना होता है।

कृषि उपज मंडी समितियों को जनवरी 2019 में भंग कर दिया गया था, तब से प्रशासनिक अधिकारी मंडियों के प्रशासक बने हुए हैं। जबकि स्पष्ट प्रावधान है कि समिति का कार्यकाल छह-छह माह कर दो बार बढ़ाया जा सकता है लेकिन चुनाव लगातार टाले जाते रहे। यही स्थिति सहकारी समितियों की भी है। यहां भी अधिकारी ही प्रशासक बने हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि पहले प्रशासक सहकारिता से जुड़े व्यक्तियों को बनाया जाएगा। इनकी अगुवाई में ही चुनाव कराए जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंशा है कि समितियों के चुनाव हों, ताकि निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्थाओं का संचालन कर सकें, वे ही स्थानीय आवश्यकताओं को देखकर नीतियां भी बनाएं। इसे ध्यान में रखते हुए सहकारिता और कृषि विभाग ने चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। मानसून समाप्त होने के बाद 259 कृषि उपज मंडी समितियों के चुनाव कराए जाएंगे। ये चुनाव 2017 में हो जाने चाहिए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए इन्हें टाल दिया गया था। उल्लेखनीय है कि 2012 में प्रदेश की मंडियों में मंडी समिति के चुनाव हुए थे। जिसके बाद 2017 में चुनाव होने थे, लेकिन मंडी समिति का कार्यकाल दो बार छह-छह माह के लिए बढ़ा दिया गया था। कार्यकाल एक साल बढ़ने के बाद वर्ष 2018 में मंडी चुनाव होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन तय समय से अधिक समय बीतने के बाद भी चुनाव नहीं होने के कारण 6 जनवरी 2019 को मंडियों में बनी समितियां भंग हो गई थीं। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया का कार्य 1 जनवरी 2017 से शुरू हुआ था। जिसके तहत मतदान क्षेत्र का निर्वाचन, आरक्षण का निर्धारण तथा मतदाता सूची तक तैयार कर दी गई थी। लेकिन अब वर्तमान में यदि चुनाव होते हैं तो एक बार फिर से नई मतदाता सूची तैयार करवाने की प्रक्रिया होगी। जिसमें दो से तीन माह तक का समय लगेगा।

कंपनियों की तरह काम करेंगी सहकारी समितियां

अब प्राथमिक सहकारी समितियां भी कंपनियों की तरह बड़े स्तर पर कार्य कर सकेंगी। इसमें समितियां गैस एजेंसी से लेकर पेट्रोल पंप और डिपार्टमेंटल स्टोर का संचालन कर सकेंगी। इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना भी होगी। सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय की सहकार से समृद्धि योजना के अंतर्गत समितियों को दक्ष बनाया जाएगा। जानकारी के अनुसार, प्रदेश की 23 हजार पंचायतों में से हर पंचायत में एक सोसायटी होगी। सोसायटी अब सिर्फ खेती-किसानी तक सीमित नहीं रहेंगी। सहकारिता आंदोलन जल्द ही बेहद मजबूत स्वरूप ले सकता है।

मंडियों के चुनाव नहीं होने की स्थिति में इसका भार प्रशासनिक अधिकारियों के जिम्मे हो गया। जानकारी के अनुसार मंडी चुनाव के समय से अधिक होने के चलते कृषि उपज मंडियों में बनी समितियां 6 जनवरी 2019 को भंग हो गई हैं। वहीं 7 जनवरी 2019 से मंडियों का कार्यभार प्रशासनिक अधिकारियों के पास आ गया है। 2012 में मंडी चुनाव हुए थे। इस हिसाब से देखा जाए तो पांच साल बाद 2017 में चुनाव होने थे। इसमें मंडी समिति का कार्यकाल 6-6 माह की अवधि के लिए दो बार बढ़ा दिया गया था। कार्यकाल के एक साल बढ़ने के बाद 2018 में मंडी चुनाव होने के कयास लगाए जा रहे थे। तय समय से अधिक होने के चलते 6 जनवरी 2019 को मंडियों में बनी समितियां भंग हो गईं। वहीं मंडी का कार्यभार जब तक चुनाव नहीं होते, तब तक प्रशासनिक अधिकारियों के पास आ गया। अब उनकी निगरानी और देखरेख में ही मंडी से जुड़े निर्णय और कामकाज हो रहे हैं।

जानकारी के अनुसार मंडियों में वर्ष 2019 में अध्यक्ष की जगह प्रशासक की नियुक्ति की गई, तब से अभी तक अलग-अलग प्रशासक मंडी की कमान संभाल रहे हैं। लंबा वक्त होने के कारण प्रशासक भी इन संस्थाओं को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। इससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। 12 सदस्यीय कार्यकारिणी मंडी चुनाव भी अन्य निकाय चुनावों की तरह होते हैं। इनकी अपनी मतदाता सूची होती है। परिसीमन भी होता है। एक मंडी में 10 वार्ड होते हैं। इन्हीं वार्डों से किसान प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ते हैं। दो प्रत्याशियों का चुनाव हम्माल और व्यापारी करते हैं। कार्यकारिणी से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है। सहकारिता विभाग और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत प्राथमिक सहकारी समितियों में भी आखिरी बार वर्ष 2013 में चुनाव हुए थे। समितियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यहां भी प्रशासक पदस्थ कर दिए गए। इन समितियों का संचालन 11 सदस्यीय संचालक मंडल करता है। इन्हीं सदस्यों में से अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। पिछले साल समितियों की मतदाता सूची भोपाल से मांगी गई थी। जिला स्तरीय कमेटी से अनुमोदित होकर सूची प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक को भेजी गई, लेकिन चुनाव संबंधी कार्यक्रम की घोषणा का इंतजार आज भी समितियों को है। इनका निर्वाचन नहीं होने से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष व संचालक मंडल का चुनाव भी रुका हुआ है।

अभी प्राथमिक स्वास्थ्य समिति, दुग्ध संघ समेत किसी भी सोसायटी में चुनाव ही नहीं हुए हैं। प्रदेश में 4500 पंजीकृत प्राथमिक साख सहकारी समितियां हैं। इसके अलावा दुग्ध संघ की 2500 समितियां हैं। लघु वनोपज संघ के तहत भी डेढ़ हजार समितियां काम कर रही हैं। इसके अलावा मार्केटिंग फेडरेशन की भी अपनी अलग समितियां हैं पर इनमें लंबे समय से चुनाव नहीं हुए और सरकारी अधिकारी-कर्मचारी इन पर काबिज हैं। सहकारी नेता इनमें चुनाव की मांग कर रहे हैं।

● **जितेंद्र तिवारी**

सुलेमान बाहर, जैन-राजौरा-मिश्रा दौड़ में

मुख्य सचिव वीरा राणा का छह माह का एक्सटेंशन इसी महीने की 30 तारीख को खत्म हो जाएगा। सरकार ने उनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए केंद्र को प्रस्ताव नहीं भेजा है। ऐसे में प्रदेश के अगले मुख्य सचिव के लिए कयासों का दौर शुरू हो गया है। इस बीच नए मुख्य सचिव के लिए नाम सामने आने के कयासों के बीच मोहन यादव सरकार ने 1989 बैच के आईएएस अधिकारी अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान को मंत्रालय के बाहर पदस्थ कर दिया है। अब वे कर्मचारी चयन मंडल के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। हालांकि मोहम्मद सुलेमान मुख्य सचिव के लिए डिजर्व करते थे। लेकिन सरकार ने उन्हें मंत्रालय से बाहर कर अनुराग जैन, राजेश राजौरा और एसएन मिश्रा का रास्ता साफ कर दिया है।

वर्तमान स्थिति में मुख्य सचिव की दौड़ में सबसे आगे केंद्र में पदस्थ अनुराग जैन और मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा का नाम है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार शायद ही अनुराग जैन को मप्र भेजे। ऐसे में राजौरा और एसएन मिश्रा मुख्य सचिव के लिए सबसे बड़े दावेदार हैं। वैसे तो अन्य दावेदारों में विनोद कुमार, जेएन कंसोटिया हैं। सोशल मीडिया के हवाले से एसएन मिश्रा का नाम भी लिया जा रहा है, परंतु श्री मिश्रा 30 जनवरी 2025 को रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में सरकार इतने अल्प समय के लिए मुख्य सचिव बनाना पसंद करेगी।

जैन गुड बुक में

मप्र में अगले मुख्य सचिव के लिए कवायद शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार अनुराग जैन और राजेश राजौरा का नाम केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय दिल्ली भेज दिया गया है। इनमें अनुराग जैन की बात की जाए तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड बुक में भी शामिल हैं। वहीं अपनी तेज तर्रार कार्यप्रणाली के कारण वे अच्छे अफसरों में गिने जाते हैं। अगर उन्हें मप्र का अगला मुख्य सचिव बनाया जाता है तो मुख्यमंत्री सचिवालय पर भी आंच नहीं आएगी, परंतु रोडे जरूर आड़े आएंगे, क्योंकि कमलनाथ की सरकार में श्री जैन अपर मुख्य सचिव थे। जब किसानों के ऋण माफी की बात आई थी, तो उन्होंने वित्तीय स्थिति का सहारा लेकर मना कर दिया था। जबकि किसानों की ऋण माफी में 35 हजार करोड़ खर्च होना था। सरकार चाहती तो 20 हजार करोड़ लोन ले लेती, परंतु श्री जैन ने अपना पच्चर मार दिया था। जबकि उसके बाद अभी तक सरकार डेढ़ लाख करोड़ का लोन ले चुकी है। अगर अनुराग जैन को केंद्र से थोपा जाता है तो वह केंद्र के खासमखास होंगे। ऐसे में सरकार को अपनी खुफियागिरी की भी चिंता रहेगी।

मुख्य सचिव के लिए राजौरा पहली पसंद

मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि डॉ. राजौरा को अगले दो महीने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ किया गया है, ताकि वे सरकार की प्राथमिकताओं से जुड़े फैसलों को लेकर सभी विभागों से समन्वय बना सकें। सूत्र ये भी कहते हैं कि छह महीने में डॉ. राजौरा का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ प्रशासनिक तालमेल बेहतर बना है। मुख्यमंत्री ने जब अपर मुख्य सचिवों के बीच संभागों का बंटवारा किया था, तब डॉ. राजौरा को उज्जैन संभाग की जिम्मेदारी सौंपी थी। उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ का आयोजन होना है। जिसकी तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। 2004 में हुए सिंहस्थ के दौरान डॉ. राजौरा उज्जैन कलेक्टर थे। बता दें कि मुख्य सचिव के रिटायरमेंट से पहले नए मुख्य सचिव को मंत्रालय में ओएसडी बनाया जाता रहा है।

22-23 को तय हो जाएगा नाम

प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि प्रदेश का अगला मुख्य सचिव कौन होगा, यह तस्वीर 22 या 23 सितंबर को साफ हो जाएगी। वर्तमान मुख्य सचिव वीरा राणा की चिट्ठी तो दिल्ली नहीं जाएगी। उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इसी के साथ प्रदेश को नया मुख्य सचिव भी मिल जाएगा।

कमिश्नर की मनमानी से भूलभुलैया में मंत्रीजी...

प्रदेश सरकार के एक मंत्री दिनों अजब सी भूलभुलैया में पड़े हुए हैं। मंत्रीजी के पास प्रदेश की कुंजी और मालदार विभाग की जिम्मेदारी है। लेकिन मंत्रीजी के आसपास अफसरों का एक ऐसा कॉकस बन गया है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। मंत्रीजी के पास प्रदेश के कमाऊ विभागों में से एक विभाग भी है। यह विभाग अपनी भर्राशाही, लापरवाही, लालफीताशाही और भ्रष्टाचार के कारण हमेशा चर्चा में रहता है। इस कारण मंत्रीजी अपने अधिकारियों के कारण इस कदर चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वे करें तो क्या करें। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री सचिवालय उनके ओएसडी से नाराज हैं। वहीं मंत्रीजी अपने कमाऊ विभाग के कमिश्नर से नाराज हैं। सूत्र बताते हैं कि कमिश्नर मंत्रीजी को तनिक भी भाव नहीं दे रहे। आलम यह है कि विभाग में वे अपनी मनमानी कर रहे हैं। कमिश्नर की मनमानी से मंत्रीजी इस कदर तंग आ गए हैं कि उन्होंने प्रमुख सचिव से ताल ठोक कर कह दिया है कि अगर तबादले का कोई भी प्रस्ताव आता है तो उसे मना कर देना। लेकिन मंत्रीजी शायद यह भूल गए हैं कि तबादले का प्रशासनिक अनुमोदन उन्हीं को करना होता है। दरअसल, मंत्रीजी के विभाग के कमिश्नर तरह-तरह से पैसा कमाने की जुगत में लगे हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि चुनाव से पहले उन्होंने जो तबादले किए थे, उन तबादलों को फिर से हेरफेर रहे हैं। इसके लिए वे जिलों में पदस्थ उपायुक्त, सहायक उपायुक्त और उपनिरीक्षकों को बुलाकर उनकी पसंद की जगह भेजने की जुगत में लगे हुए हैं। इसके लिए वे उन अफसरों से मोटी कमाई कर रहे हैं। इससे मंत्री तो हैरान-परेशान हैं ही, लेकिन अब यह बात मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है। बताया जाता है कि कमिश्नर की मनमानी से पहले के मंत्री भी परेशान और नाराज थे। वर्तमान मंत्री तो इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने सरकार से साफ-साफ शब्दों में कह दिया है कि इन्हें यहां से हटाओ। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री मंत्री की बात को कितनी गंभीरता से लेते हैं और कमिश्नर के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। बताया जाता है कि कमिश्नर नियम-कायदों को ताक पर रखकर विभाग में अपनी मनमानी कर रहे हैं, इससे ठेकेदार भी परेशान हैं।

मंत्रीजी के तीन बंदर

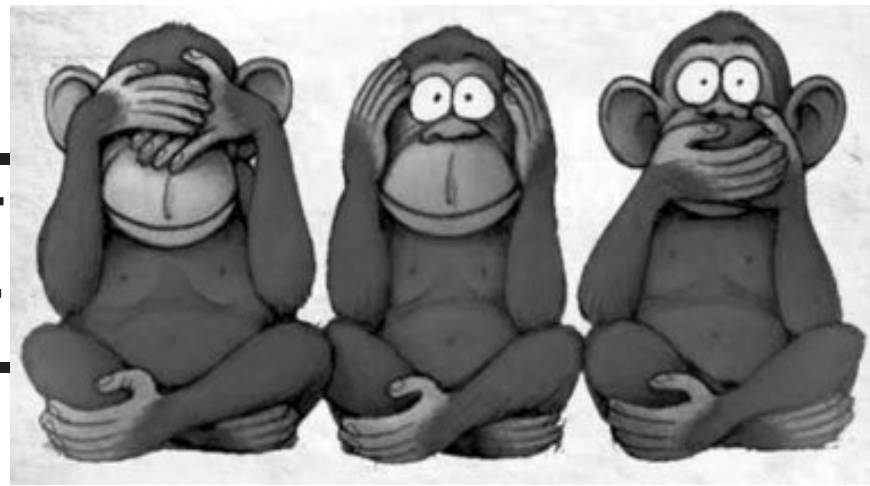

अभी तक आप लोगों ने गांधीजी के तीन बंदरों के बारे में सुना और पढ़ा है, लेकिन अब हम यहां आपको मप्र सरकार के एक मंत्रीजी के तीन बंदरों (मंत्री स्टाफ) से अवगत कराते हैं। गांधी जी के बंदर जहां बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो का संदेश देते हैं, वहीं मंत्रीजी के तीनों बंदर के अंदर बुराईयों का पिटारा भरा हुआ है। ये तीनों मंत्रीजी के स्टाफ में पदस्थ हैं। मंत्री पदस्थापना के रसूख में ये तीनों किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। यही नहीं ये आपस में भी एक-दूसरे को आंख दिखाने से बाज नहीं आते हैं। इनमें से एक महाशय मंत्री प्रभार में कार्यपालन यंत्री का काम देख रहे हैं। वे लोगों को चमकाकर मंत्री से मिलने बंगले पर बुला रहे हैं। वे मंत्रीजी की आड़ में उन लोगों से लक्ष्मीजी की उगाही कर रहे हैं। एक महाशय शिक्षाविद् हैं और अभी तक जहां-जहां मंत्री पदस्थापना में रहे हैं, वहां-वहां बंटाधार किया है। उनका मूल काम शिक्षा देने का है, पर वे अधिकतर समय मंत्रियों के यहां ही अटैच रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि माल पीटने में उनका कोई सानी नहीं है। यही नहीं उन्होंने मंत्री को भी विश्वास दिला दिया है कि उनके रहते उन पर लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तीसरे बाबू हैं। ये भी उपरोक्त दोनों से कम नहीं हैं। ये दोनों का काम देखकर अपना काम दिखा देते हैं। इन तीनों से मंत्री के विभाग के अन्य अधिकारी-कर्मचारी परेशान हैं।

असली भारत की पहचान

अभी हाल ही में सरकार ने 2020, 2021 और 2022 बैच के आईएएस अधिकारियों की पदस्थापना की है। इन सभी की पदस्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में की गई है। बताया जाता है कि इसके पीछे मुख्यमंत्री की मंशा है कि नवागत अधिकारी असली भारत को पहचानें। इसलिए इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ किया गया है। दरअसल, मुख्यमंत्री नवागत अधिकारियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि वे सबसे पहले ग्रामीण भारत को अच्छी तरह से समझें। अगर उन्होंने ग्रामीण भारत और वहां की समस्याओं का ठीक ढंग से अध्ययन और परीक्षण कर लिया तो सरकार को योजनाएं-परियोजनाएं बनाने में परेशानी नहीं होगी। सूत्र बताते हैं कि अफसरों को ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ करने के बाद मुख्यमंत्री ने साफ-साफ शब्दों में कह दिया कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोई भी मेरे पास ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए न आए।

काम कर रहे, भुगतान नहीं

जल विकास निगम की योजनाओं और परियोजनाओं को साकार करने वाले ठेकेदार इन दिनों परेशान हैं। परेशानी की वजह यह है कि उनसे काम तो खूब लिया जा रहा है, लेकिन भुगतान नहीं किया जा रहा है। ठेकेदार अपने काम का भुगतान पाने के लिए चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं। ठेकेदारों की परेशानी और अधिकारियों की भर्राशाही की खबर मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुंच गई है। जब इस मामले की पड़ताल की गई तो चौंकाने वाली असलियत सामने आई। दरअसल, निगम में फंड की कमी नहीं है। ठेकेदारों का भुगतान कमीशनखोरी के चक्कर में नहीं हो रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री सचिवालय में बात पहुंचने के बाद ठेकेदारों को उम्मीद है कि उनकी राह में खड़ी बाधा जल्द खत्म हो सकती है और उनका भुगतान जरूर हो जाएगा।

अच्छी पोस्टिंग की तलाश

प्रदेश में इस समय दो आईपीएस अधिकारी चर्चा में हैं। इसकी वजह यह है कि इन दनों अफसरों की चिंता खुद पीएचक्यू कर रहा है। ये दोनों अफसरों एक ही संभाग में पुलिस की दो बड़ी कुर्सियों पर पदस्थ हैं। ये जिस संभाग में पदस्थ हैं, वह कभी डकैतों के कारण कुख्यात रहा है। अब ये दोनों अफसर यहां की जगह दूसरी जगह पदस्थापना चाह रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। ये दोनों आईपीएस अधिकारी स्वजातीय हैं। इसलिए इन दोनों में तो अच्छी खासी पट रही है। साथ ही इन दोनों की चिंता उच्च स्तर पर की जा रही है। सूत्र बताते हैं कि दोनों ने अपनी नई पदस्थापना की मंशा जाहिर की तो खुद पीएचक्यू ने उनके लिए अच्छी पोस्टिंग की तलाश शुरू कर दी है। बताया जाता है कि इसके लिए उनकी जाति की बड़ी भूमिका है। अब देखना है, जाति का गणित उन्हें किस कुर्सी पर बैठाता है।

● **राजेंद्र आगाल**

दो अफसरों में पावर की जंग

प्रदेश के कमाऊ विभागों में से एक परिवहन विभाग में इन दिनों दो अफसरों के बीच पावर की लड़ाई छिड़ी हुई है। एक अफसर कमिश्नर हैं तो दूसरे एडिशनल कमिश्नर। दोनों एडीजी स्तर के अधिकारी हैं, इसलिए ये एक-दूसरे को भाव नहीं देते हैं। सूत्रों का कहना है कि इनकी लड़ाई की मूल वजह है पावर की कमी और उपयोग। दरअसल, दोनों अफसर विभाग में अपनी-अपनी चलाना चाहते हैं। इस कारण आए दिन अधिकारों को लेकर उनके बीच टकराव की स्थिति बन जाती है। एक तो प्रदेश का सबसे कमाऊ विभाग होने के कारण हमेशा इस विभाग के अधिकारी शासन-प्रशासन की नजरों पर चढ़े रहते हैं। ऐसे में इन दोनों अधिकारियों के बीच पावर की लड़ाई इस मुकाम पर पहुंच गई है कि एडिशनल कमिश्नर विभाग से नौ-दो, ग्यारह होने की फिराक में हैं। सूत्र बताते हैं कि इसके लिए साहब ने नए अड्डे की तलाश शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि दो वरिष्ठ अधिकारियों में छिड़ी वर्चस्व की यह जंग किस स्तर पर जाकर थमती है। उधर, दो वरिष्ठ अफसरों के बीच चल रहे शीतयुद्ध से विभाग के अन्य अधिकारी भी परेशान हैं।

सतपुड़ा-विंध्याचल का भविष्य अधर में

भोपाल की सबसे पुरानी सरकारी इमारतों में शामिल सतपुड़ा और विंध्याचल भवनों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। सतपुड़ा भवन की बिल्डिंग में भीषण आग लगने के एक साल से अधिक समय बीतने के बाद भी सरकार यह तय नहीं कर पाई है कि सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन की बिल्डिंगों का रिनोवेशन होगा या उन्हें ध्वस्त कर नया निर्माण किया जाएगा? बताया जा रहा है कि सरकार इन इमारतों की जगह पर नया आधुनिक ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाएगी। लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है।

दरअसल, सतपुड़ा-विंध्याचल भवन का रिनोवेशन कराने का फैसला किया गया था। इसके लिए 167.59 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी मिल गई थी। लेकिन यह फैसला रद्द कर दिया गया। अब कहा जा रहा है कि सतपुड़ा और विंध्याचल भवनों की जगह पर स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव बनेगा, जिसे कैबिनेट से पास कराने के बाद काम शुरू किया जाएगा। इन दोनों इमारतों को तोड़कर इसी जगह पर नया सरकारी ऑफिस तैयार करवाया जाएगा। सतपुड़ा और विंध्याचल भवन राजधानी भोपाल की सबसे पुरानी इमारतों में शामिल हैं। सन् 1982 में यह भवन तैयार हुए थे। उस वक्त सतपुड़ा भवन का निर्माण 4.61 करोड़ रुपए में हुआ था, जबकि विंध्याचल भवन का निर्माण 4.95 करोड़ में हुआ था। यहां से मप्र सरकार के कई अहम विभाग संचालित होते हैं। जिनमें शिक्षा, आयुष, आदिम जाति कल्याण, उद्योग, सहकारिता, कृषि जैसे विभाग शामिल हैं।

पिछले कुछ महीनों में सतपुड़ा भवन में आग लगने की घटनाएं सामने आई थीं। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की 3 प्रशासनिक इमारतों वल्लभ भवन, सतपुड़ा और विंध्याचल भवन में आग लगने और महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों के राख हो जाने का इतिहास रहा है। 28 नवंबर, 2013 और 4 अक्टूबर, 2015 को विंध्याचल भवन में आग लगने से सरकारी रिकॉर्ड जल गया। पिछले साल 12 जून को सतपुड़ा भवन में भीषण आग ने स्वास्थ्य विभाग की तीन मंजिलों और आदिवासी विभाग की एक मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया था। सतपुड़ा भवन में लगी आग में जले सामान के मलबे में 20 फरवरी को दोबारा आग लग गई। 9 मार्च, 2024 को वल्लभ भवन की पुरानी बिल्डिंग में लगी भीषण आग में सरकारी रिकॉर्ड जलकर खाक हो गया था।

राजधानी स्थित सतपुड़ा भवन की बिल्डिंग में भीषण आग लगने के एक साल से अधिक समय बीतने के बाद भी सरकार यह तय नहीं कर पाई है कि सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन की बिल्डिंगों का रिनोवेशन होगा या उन्हें ध्वस्त कर नया निर्माण किया जाएगा? इन दोनों बिल्डिंगों में विभिन्न सरकारी कार्यालय संचालित होते हैं। सतपुड़ा भवन में पिछले साल 12 जून को लगी आग में जले सामान के मलबे में इस साल 20 फरवरी को फिर आग लग गई थी। हालांकि आग की दो घटनाओं के बाद भी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आया। सतपुड़ा भवन की जली हुई मंजिलों को जून, 2023 की आग के बाद वैसे ही छोड़ दिया गया है। बारिश का पानी जली हुई मंजिलों के अंदर न जाए, इसके लिए सतपुड़ा भवन के जले हुए हिस्से के चारों ओर पॉलिथीन लगा दी गई है। फरवरी, 2024 में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने दावा किया था कि सतपुड़ा और विंध्याचल भवनों के रिनोवेशन का काम जल्द शुरू होगा। सरकार की ओर से दोनों भवनों के लिए करीब 170 करोड़ रुपए की नई परियोजना को मंजूरी दी गई थी, लेकिन जुलाई, 2024 में मुख्य सचिव की मौजूदगी में हुई बैठक में सतपुड़ा और विंध्याचल भवन के रिनोवेशन की बजाय नए भवन के निर्माण पर चर्चा हुई।

● **डॉ. जय सिंह सेंधव**

रिनोवेशन किया जाएगा या पुनर्निर्माण

अधिकारियों का कहना है कि मामला अभी लंबित है और यह अब भी स्पष्ट नहीं है कि दोनों भवनों का रिनोवेशन किया जाएगा या पुनर्निर्माण। दोनों भवन 1982 में अस्तित्व में आए थे। पिछले साल जून में सतपुड़ा भवन में आग लगने के बाद सरकार ने बिल्डिंग की संरचनात्मक ताकत (स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ) का आंकलन करने के लिए गुजरात से फॉरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया था। भवनों के निरीक्षण और सैंपल के परीक्षण के बाद उन्होंने 200 पेज की रिपोर्ट सितंबर, 2023 में मप्र सरकार को सौंपी थी। इसमें कहा गया था कि सतपुड़ा भवन की बिजली की केबल पुरानी थी और लोड सहन नहीं कर पा रही थी, जिससे शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि बिल्डिंग को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। रिपोर्ट में भवन के रिनोवेशन और इसकी संरचनात्मक ताकत में सुधार के तरीके सुझाए गए हैं। इसके आधार पर रिनोवेशन का प्रोजेक्ट बनाया गया। हालांकि बाद में रेनोवेशन की बजाय नए सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन के निर्माण का प्रस्ताव लाया गया और इस पर फैसला होना बाकी है। अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण केसी गुप्ता का कहना है कि सतपुड़ा और विंध्याचल भवन के पुनर्निर्माण पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

एम-सैंड से रुकेगा नदियों में अवैध खनन

मप्र की नदियों में हो रहे रेत के अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार एम-सैंड (मैन्युफैक्चर्ड सैंड) को प्रोत्साहित करने पर बल देगी। राज्य सरकार एम-सैंड नीति बनाने जा रही है, जिससे प्राकृतिक रेत और मौरंग के एक नए विकल्प की उपलब्धता होगी। सरकार की मंशा है कि पर्यावरण एवं नदियों के इकोसिस्टम को बिना नुकसान पहुंचाए सस्टेनेबल विकास को गति दी जाए। इस दृष्टि से एम-सैंड एक बेहतर माध्यम है। नदी तल से प्राप्त होने वाली रेत की सीमित मात्रा और इसकी बढ़ती मांग के दृष्टिगत एम-सैंड को नदी तल से प्राप्त होने वाली रेत के विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे रोजगार के भी नए अवसर सृजित होंगे।

गत दिनों खनिज साधन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एम-सैंड को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ कहा कि विभाग को रेडी मिक्स क्रांकीट को बढ़ावा देने के लिए नीति भी बनाई जाए। जानकारी के अनुसार पर्यावरण और नदियों के संरक्षण के लिए सरकार एम-सैंड (मैन्युफैक्चर्ड सैंड यानी पत्थर से बनने वाली रेत) को बढ़ावा दे रही है। इससे नदियों से रेत लेने की निर्भरता कम होगी। इसके साथ ही बारिश के दौरान घर बनाने वालों को सस्ती रेत मिलेगी। सरकार एम-सैंड नीति तैयार कर रही है, यह नीति जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। इसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। प्रदेश में प्रतिवर्ष सवा करोड़ घन मीटर रेत की जरूरत होती है। सरकार ने प्रदेश के 44 जिलों में स्थित 1,093 रेत खदानों से 3 करोड़ 11 लाख घन मीटर रेत तीन वर्ष के अंदर निकालने के लिए अनुबंध किया है। इसमें सबसे ज्यादा 64 लाख घन मीटर रेत नर्मदापुरम जिले में स्थित रेत खदानों से निकाली जाती है।

सूत्रों के अनुसार अब गिट्टी, पत्थर की खदान की लीज और क्रशर संचालित करने का लाइसेंस लेने वालों को एम-सैंड प्लांट लगाने के लिए सरलता से लाइसेंस मिल जाएगा। गिट्टी, पत्थर की पुरानी खदानों के संचालन की भी अनुमति मिलेगी। इसके लिए सिर्फ एक आवेदन देना होगा। उद्योग विभाग प्लांट लगाने पर 40 फीसदी की छूट देगा। खनिज साधन विभाग ने इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रॉयल्टी में भी छूट दी है। इस तरह की रेत में 50 रुपए प्रति घन मीटर न्यूनतम कीमत रखी है। जबकि नदियों से निकलने वाली रेत खदानों के लिए 250 रुपए प्रति घन मीटर न्यूनतम कीमत रखी गई है। नदियों से निकाली गई रेत की कीमतें ठेकेदार पर निर्भर है। ठेकेदार जितनी महंगी रेत खदानें लेगा उतनी ही महंगी रेत बेचेगा। वर्तमान में कई जगह 300 रुपए घनमीटर तक रेत मिलती है। जबकि एम-सैंड में इसका प्रभाव नहीं होता है।

रेत, गिट्टी, पत्थर और क्रशर से जुड़े कारोबारी भी एम-सैंड उद्योग को फायदे का सौदा मान रहे हैं। उन्होंने इस बारे में पॉजिटिव फीडबैक दिया है। तीन साल पहले शुरू हुए एम-सैंड के लाइसेंस में अब तक भोपाल, कटनी, जबलपुर सहित कई जिलों में 75 संयंत्र स्थापित कर दिए गए हैं। पिछले वर्ष एम-सैंड से सरकार को 4 करोड़ रुपए रॉयल्टी मिली थी। छतरपुर के एम-सैंड कारोबारी रुचिर जैन का कहना है कि बाजार में एम-सैंड की डिमांड ज्यादा है। इसकी क्वालिटी नदियों की रेत से बेहतर होती है। इसकी रेत सस्ती भी है। प्रदूषण भी नहीं होता है। सरकार भी इस उद्योग को प्रमोट करने में लगी है। संचालक खनिज साधन विभाग अनुराग चौधरी का कहना है कि पर्यावरण और नदियों को बचाने के लिए एम-सैंड पर जोर दिया जा रहा है। कोल और ग्रेनाइट की खदानों के संचालन से पहले उनसे बहुत सारे पत्थर निकलते हैं। इसके एम-सैंड बनाने में उपयोग होगा। इसके अलावा गिट्टी, पत्थर के खदान संचालकों को इसके उद्योग लगाने पर सुविधा दी जाएगी। प्रदेश में एम-सैंड नीति भी तैयार की जा रही है। नदियों से निकलने वाली रेत से एम-सैंड बेहतर होती है। इसमें मिट्टी नहीं होती है। इसकी पकड़ भी मजबूत होती है। बिल्डर और कारोबारी मुकेश यादव के अनुसार एम-सैंड में मिट्टी-धूल नहीं होने के कारण सीमेंट से पकड़ मजबूत होती है। एम-सैंड के दाने बराबर होते हैं, यह प्लास्टर और फ्लोरिंग के लिए उपयोगी है।

वहीं दूसरी तरफ यह जानकारी भी सामने आई है कि प्रदेश की बंद कोयला खदानों का उपयोग अब एम-सैंड (यांत्रिकी क्रिया द्वारा पत्थर से निर्मित रेत) बनाने में उपयोग किया जाएगा। खदानों से पर्याप्त मात्रा में कोयला निकालने के बाद पत्थरों का बड़ा सा पहाड़ खड़ा हो जाता है। इन पत्थरों से रेत बनाई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार कोल इंडिया से भी बात कर रही है। फिलहाल, सिंगरौली में इस तरह का प्लांट संचालित किया जा रहा है। इसी तर्ज पर प्रदेश के अन्य जिलों में यह प्रयोग करने की तैयारी है। सिंगरौली जिले में भारत सरकार की मिनीरत्न कंपनी नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) एम सैंड निर्माण संयंत्र संचालित कर रही है। एनसीएल आने वाले समय में अपनी विभिन्न परियोजनाओं में इस तरह के संयंत्र की स्थापना पर विचार कर रही है। एनसीएल इस प्लांट के माध्यम से प्रतिदिन एक हजार क्यूबिक मीटर रेत बनाएगी, जिसके लिए 1429 क्यूबिक मीटर अधिभार का उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार एनसीएल वर्षभर में तीन लाख क्यूबिक मीटर एम-सैंड का उत्पादन करेगी। राज्य सरकार की मंशा है कि नदी से निकलने वाली प्राकृतिक रेत पर निर्भरता कम हो और नदियों को बचाया जा सके, इसके लिए राज्य सरकार एम-सैंड को प्रोत्साहित कर रही है, यही वजह है कि एम-सैंड पर रायल्टी भी बहुत कम रखी है। नई रेत नीति में एम-सैंड के लिए अलग से प्रविधान किए जाएंगे। इसके लिए अन्य राज्यों का भी अध्ययन कराया जा रहा है।

● **विकास दुबे**

सरकारी निर्माण कार्यों में एम सैंड के उपयोग जरुरी

जानकारी के अनुसार सरकार एम-सैंड की जो नीति बना रही है उसके तहत राज्य सरकार अब सरकारी निर्माण कार्यों में उपयोग में आने वाली कुल बजरी की मात्रा में कम से कम 25 प्रतिशत एम-सैंड के उपयोग के प्रति गंभीर हो गई है। देश में राजस्थान के साथ ही कर्नाटक, तेलगांना व तमिलनाडु में बजरी के विकल्प के रूप में एम-सैंड का प्रमुखता से उपयोग किया जा रहा है। कर्नाटक में सर्वाधिक 2 करोड़ टन, तेलंगाना में 70 लाख 20 हजार टन और तमिलनाडु में 30 लाख 24 हजार टन एम-सैंड का सालाना उत्पादन हो रहा है। एम-सैंड निर्माण कार्य के लिए बेहतर होने के साथ ही बजरी की तुलना में सस्ती, सहज उपलब्धता और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। विभाग द्वारा नई एम-सैंड इकाइयों की स्थापना के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं सरकारी विभागों के निर्माण कार्यों में कम से कम 25 प्रतिशत एम-सैंड के उपयोग की अनिवार्यता से बजरी के विकल्प को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

परिसीमन से सारे समीकरण साधे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परिसीमन आयोग का एक ऐसा दांव चल दिया है जिससे वे कई समीकरणों को साधकर अपनी साख को मजबूत बनाएंगे। गौरतलब है कि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से उठ रही नए जिलों की मांग के बाद अब मप्र प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग बनाने की घोषणा कर मुख्यमंत्री ने बड़े लक्ष्य को साधने की कोशिश की है। दरअसल, बीना को जिला बनाए जाने की मांग के बीच खुरई को भी जिला बनाने के लिए भीतरखाने राजनीतिक लामबंदी होने लगी थी। अब आयोग के गठन से ये भी साफ हो गया है कि नए जिलों का गठन सोच समझकर किया जाएगा। वहीं पुनर्गठन आयोग की घोषणा से सरकार ने राजनीति, भूगोल और समाज तीनों को साधने की कोशिश की है। सीनियर अधिकारी कहते हैं कि ऊपरी तौर पर भले ही ये प्रशासनिक आदेश लग रहा है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने बेहद गहरे हैं।

27 फरवरी 2024 को ही कैबिनेट ने प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग को स्वीकृति दे दी थी। मगर, चुनाव आचार संहिता के चलते उस समय नियुक्ति के आदेश नहीं हुए थे। अब 9 सितंबर को सरकार ने रिटायर्ड एसीएस मनोज श्रीवास्तव को आयोग का सदस्य बनाया है। आयोग हर जिलों के दौरे करके उसका भूगोल समझेगा। वहां के लोगों की तकलीफ जानेगा। ये देखेगा कि प्रदेश के किस हिस्से में जिला मुख्यालय लोगों की पहुंच से बेहद दूर है? क्या उस हिस्से को नजदीक के किसी जिले में मिलाया जा सकता है या नहीं? इसके बाद आयोग एक ड्राफ्ट बनाएगा। उस पर दावे-आपत्तियां बुलाई जाएंगी। एक बार फिर उन दावे-आपत्तियों पर सुनवाई होगी। फिर अंतिम ड्राफ्ट तैयार होगा। आयोग की इन गतिविधियों से लोगों का सरकार के प्रति विश्वास मजबूत होगा। जानकारों का कहना है कि सरकार ने जिलों की सीमाओं के फिर से आंकलन के लिए मप्र प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग बनाकर लंबे समय से चल रही विसंगतियों को दूर करने का जो फैसला लिया है, वह निश्चित रूप से बेहतर है पर इस फैसले के राजनीतिक निहितार्थ भी अपनी जगह है। सरकार ने इससे जिलों की राजनीति, भूगोल और समाज तीनों को साधने का प्रयास किया है।

आयोग के गठन से साफ है कि अब कम से कम दो साल तक किसी नए जिले का ऐलान सरकार नहीं करेगी। कुछ क्षेत्रों के जुड़ने-घटने से जिलों के सियासी समीकरण भी प्रभावित होना तय माना जा रहा है। प्रदेश में इस समय आधा दर्जन शहरों के नेता अपने-अपने शहरों को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गत दिनों बीना के दौरे पर गए थे। इस दौरे के ठीक पहले ही उन्होंने आयोग के गठन की जानकारी दी थी। बीना को जिला बनाने की मांग लंबे समय से हो रही है। वहीं समीप के शहर खुरई को भी जिला बनाने की मांग भी पुरानी है। अभी दोनों शहर सागर जिले का हिस्सा हैं। बीना से सागर की दूरी 70 तो खुरई की 50 किमी है। इसी तरह मंदसौर मांग भी पुरानी है। मंदसौर की उज्जैन से दूरी 150 किमी है और यह जिला अभी उज्जैन संभाग का हिस्सा है। चुनाव के समय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी गरौठ को जिला बनाने पर विचार का आश्वासन दिया था। उज्जैन के नागदा को जिला बनाने को लेकर तो परीक्षण भी हो चुका है पर इसके बाद भी मामला अटका हुआ है। इसके अलावा छतरपुर के गौरिहार, गुना से चाचौड़ा, नर्मदापुरम के पिपरिया, खंडवा के ओंकारेश्वर, धार के डही को भी जिला बनाने की मांग उठती रही है। ये वे शहर हैं जिनकी जिला मुख्यालय से दूरी 50 किलोमीटर से ज्यादा है। छिंदवाड़ा को तोड़कर पांडुर्णा को जिला बनाया जा चुका है पर जुन्नारदेव को जिला बनाने की मांग भी लंबे समय से उठ रही है। राजनीतिक दलों के नेताओं की यह मजबूरी होती है कि उन्हें इस मांग का समर्थन करना भी पड़ता है। नागदा, बीना समेत कई जिलों के विधायक अपने शहर को जिला बनाने की मांग को लेकर समय-समय पर मुख्यमंत्री से मिलते रहे हैं। अब नया आयोग बनाकर संभाग और गरौठ को जिला बनाने की सरकार ने इस मांग को लंबे समय के लिए टाल दिया है।

● **सुनील सिंह**

आधा दर्जन नए जिले बनाने की संभावना

सूत्रों का कहना है कि जिस तरह प्रदेश के कई जिलों में स्थिति यह है कि जिला मुख्यालय तक आने के लिए लोगों को सैकड़ों किमी की दूरी तय करनी पड़ रही है। जिलों से तहसीलों की दूरी को ध्यान में रखकर परिसीमन आयोग नए जिले बनाने की सिफारिश कर सकता है। जैसे, सागर से बीना की दूरी 74 किमी और खुरई की 52 किमी है। इनमें से किसी एक को जिला बनाया जा सकता है। छतरपुर जिले में लवकुशनगर की दूरी 60 किमी और बड़ामलहरा की 50 किमी है। इनमें लवकुशनगर को जिला बनाने की ज्यादा संभावना है। गुना से चाचौड़ा की दूरी 64 किमी, उज्जैन से नागदा की दूरी 96 किमी और शिवपुरी से पिछौर की दूरी लगभग 76 किमी है। इन्हें नया जिला बनाया जा सकता है। डबरा को जिला बनाने का आश्वासन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक चुनावी सभा में दे चुके हैं। सिवनी का लखनादौन भी जिला बनने की कतार में है। हालांकि इनमें से कौनसी तहसीलें जिला बनेंगी, यह काफी हद तक परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। इससे यह तय है कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद प्रदेश में आधा दर्जन से ज्यादा नए जिले बनाए जा सकते हैं। इसके लिए सागर, उज्जैन, छतरपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, गुना, शिवपुरी, इंदौर जैसे जिलों की तोड़ा जा सकता है। प्रदेश में वर्ष 2003 के बाद 7 नए जिलों का गठन हुआ है। 2003 में प्रदेश में कुल 48 जिले थे जो 2008 में बढ़कर 50 और 2013 में 51 हो गए। 2018 में जिलों की संख्या 52 पहुंची और 2023 में कुल 55 जिले हो गए। इनमें तीन जिले मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर पिछले साल विधानसभा चुनाव के पहले अस्तित्व में आए थे। रीवा से तोड़कर मऊगंज को अलग जिला बनाया गया। छिंदवाड़ा से अलग कर पांढुर्णा को और सतना से अलग कर मैहर को जिला मुख्यालय का तमगा मिला। इससे पहले निवाड़ी और सिंगरौली जिले बनाए गए थे।

पटवारी का भविष्य उपचुनाव पर टिका

छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में मिली मामूली वोटों से हार के बाद कांग्रेस बुधनी और विजयपुर उपचुनाव से पहले से तैयारियां तेज कर दी हैं। मप्र कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद बुधनी विधानसभा में कई बैठकें कर चुके हैं। पटवारी बूथ मैनेजमेंट पर विशेष फोकस कर रहे हैं। दोनों ही विधानसभाओं के बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी विधायकों को देगी। पटवारी जिस तरह से चुनावी तैयारियों में जुटे हैं उससे साफ दिख रहा है कि उनका भविष्य उपचुनाव पर टिका है। अगर कांग्रेस विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में हारती है तो जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी।

गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने जीतू पटवारी लोकसभा चुनाव की अपनी पहली परीक्षा में बुरी तरह असफल हो चुके हैं। उनकी दूसरी परीक्षा प्रदेश में विजयपुर और बुधनी लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर है। उपचुनाव में कांग्रेस अगर एक भी सीट बचाने में सफल रही तो पटवारी को अभयदान मिल सकता है, अन्यथा पार्टी का प्रदेश नेतृत्व उनके प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर विचार कर सकता है। ज्ञात हो कि मप्र के श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक रहे रामनिवास रावत लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा ने उन्हें मप्र का वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाया है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा से चुनाव लड़ रहे रामनिवास रावत को टक्कर देने के लिए कांग्रेस चुनावी तैयारियों के साथ-साथ प्रत्याशी चयन के लिए भी विशेष रणनीति बना रही है। चूंकि पूर्व विधायक बाबूलाल मेवरा भी 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इसलिए कांग्रेस के पास इस सीट पर रामनिवास को हराने लायक दूसरा नेता नजर नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की नजर 2018 के विधानसभा चुनाव में रावत को पराजित करने वाले पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी पर है। हालांकि कांग्रेस के इस तरह के प्रयासों की भनक लगते ही भाजपा का संगठन पूरी तरह सक्रिय और सजग है।

उपचुनाव में भाजपा ने रामनिवास रावत को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी की तलाश कर रही है। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पुत्र एवं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह को चुनाव प्रभारी बनाया है। जयवर्धन सिंह ने ग्वालियर-चंबल के सभी कांग्रेस विधायकों, पूर्व विधायकों तथा जिला एवं ब्लॉक प्रभारियों को 10-10 बूथों को जिम्मेदारी भी सौंपी है। हर बूथ पर 15-20 कार्यकर्ता विशेष रूप से तैयार करने की भी योजना है। कांग्रेस अपने बागी विधायक को सत्तापक्ष के प्रत्याशी के रूप में पराजित करने के लिए हर तरह से घेराबंदी करने में जुटी है। प्रयास जातिगत आधार पर क्षेत्रवार जिम्मेदारियां सौंपकर भी किया जा रहा है। जनजातीय के स्थान पर ओबीसी को वन विभाग की जिम्मेदारी के नाम पर बहकाने का प्रयास भी जारी है और रावत को पावर दिए जाने पर भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं को बरगलाने का प्रयास भी जारी है। ऐसी स्थिति में भाजपा और स्वयं रामनिवास रावत के लिए भी विजयपुर सीट चुनौती से कम नहीं होगी। बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस स्थानीय और मजबूत उम्मीदवार की तलाश में है। कांग्रेस अब तक इस सीट से बाहर प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारती रही है। कांग्रेस इस बार प्रत्याशी भी स्थानीय देगी और मुद्दे भी स्थानीय ही उठाएगी। हालांकि कांग्रेस के संभावित चहरे भी अब तक साफ नहीं हो सके हैं।

श्योपुर जिले में विजयपुर विधानसभा में होने वाला उपचुनाव बेहद रोचक होने की संभावना है। यहां से वर्ष 2023 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने रामनिवास रावत के त्यागपत्र देने और भाजपा में शामिल होने के कारण उपचुनाव हो रहा है। रावत को भाजपा ने मोहन कैबिनेट में मंत्री भी बनाया है। रावत ही उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी होंगे। यही वजह है कि कांग्रेस यहां आदिवासी प्रत्याशी देना चाहती है ताकि आदिवासी बहुल वोटों का उसे लाभ मिल सके। सीताराम ने ही वर्ष 2018 में भाजपा के टिकट पर रामनिवास रावत को हराया था लेकिन भाजपा ने वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में सीताराम आदिवासी का टिकट काटकर बाबूलाल मेवरा को दे दिया था। कांग्रेस एक अन्य आदिवासी प्रत्याशी के नाम पर भी विचार कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में विजयपुर से निर्दलीय प्रत्याशी रहे मुकेश मल्होत्रा ने 44,128 वोट लिए थे। कांग्रेस का गणित आदिवासी वोटों को एकजुट रखकर भाजपा को मात देना है। रामनिवास रावत से पहले कांग्रेस छोड़कर आए कमलेश शाह को भी अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने चुनाव लड़ाया था। हालांकि इस उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रावत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यहां भाजपा के दो-दो पूर्व विधायक हैं। दोनों ने ही चुनाव लड़ने की इच्छा से पार्टी को अवगत करा दिया है। सीताराम आदिवासी के बगावती सुरों से भाजपा वाकिफ भी है। वहीं बाबूलाल मेवरा भी रावत की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं। यदि यही हाल रहा तो उपचुनाव में भाजपा की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी।

● **अरविंद नारद**

शिवराज की पसंद का प्रत्याशी

पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा चुनाव जीतने से खाली हुई बुधनी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। विगत चार विधानसभा चुनाव से शिवराज ही इस सीट से प्रत्याशी बने और जीते, लेकिन इस बार भाजपा को नए प्रत्याशी की तलाश है। कई स्थानीय नेता दावेदारी भी कर रहे हैं। हालाकि माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जिस नाम पर सहमति देंगे, वही भाजपा का प्रत्याशी होगा। बुधनी से भाजपा के दावेदारों में पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है। इनके अलावा राजेंद सिंह राजपूत, रघुनाथ सिंह भाटी, केंद्रीय मंत्री शिवराज के पुत्र कार्तिकेय चौहान, निर्मला बरेला सहित अन्य कई नामों की चर्चा है। कार्तिकेय चौहान को छोड़कर शेष सभी नेता पार्टी में प्रमुख पदों पर रहे हैं। राजेंद्र राजपूत पूर्व विधायक हैं, जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान के लिए अपनी कुर्सी छोड़ी थी, जबकि विदिशा के पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को लोकसभा का टिकट नहीं मिलने पर अब विधानसभा का टिकट दिए जाने की चर्चा है। भाजपा से टिकट किसी को भी मिले, लेकिन भाजपा के इस अभेद्य किले को जीतना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है।

बड़ी से बड़ी जीत के बाद भी आराम को हराम मानने वाली भाजपा विश्व की एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो हमेशा मिशन मोड में रहती है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद अब मप्र में सत्ता और संगठन मिशन 2028 यानी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है।

मिशन 2028 पर अभी से फोकस

मप्र में लोकसभा चुनाव में मिली भारी जीत से भाजपा सरकार कॉन्फिडेंस में है। राज्य सरकार का अभी से 2028 के विधानसभा चुनाव पर फोकस है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विजन डॉक्यूमेंट 2028 तैयार करने के निर्देश दिए है। विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की गाइडलाइन कलेक्टरों तक पहुंची है। विजन डॉक्यूमेंट 2028 विधानसभा वार तैयार किया जाएगा। विधायकों से चर्चा कर विजन डॉक्यूमेंट 2028 तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादन ने सभी कलेक्टरों को तय समय में विजन डॉक्यूमेंट 2028 तैयार करने के निर्देश दिए है।

विधानसभा वार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, रोजगार, ऊर्जा कृषि, अधोसरंचना, उद्योग के क्षेत्र में विधायकों से सलाह कर डॉक्यूमेंट तैयार करने के निर्देश हैं। मप्र की डॉ. मोहन यादव सरकार ने विधानसभा क्षेत्रों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है। इस घोषणा से राज्य की राजनीति में एक नया विवाद हो गया है। इस योजना के तहत विधायकों को अपने क्षेत्र के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस के विधायकों ने इस प्रक्रिया में भेदभाव का आरोप लगाया है। आरोप है कि कांग्रेस विधायकों से तो इस बारे में पूछा ही नहीं गया है। सरकार का लक्ष्य है कि हर विधानसभा क्षेत्र में अगले चार वर्षों में 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएं। इसके लिए विधायकों को एक विस्तृत विकास योजना (विजन डाक्यूमेंट) प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इस डॉक्यूमेंट में मूलभूत समस्याओं का आंकलन, योजनाओं का कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग की प्रक्रिया शामिल होगी।

विजन डॉक्यूमेंट तीन फेज में होगा। फर्स्ट फेज में मूलभूत समस्याओं का डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। सेकंड फेज में विकास योजनाओं का निर्माण और मॉनिटरिंग पर फोकस रहेगा। थर्ड फेज में गुणात्मक और मात्रात्मक मापदंडों पर आधारित लक्ष्यों का निर्धारण किया जाएगा। दरअसल विधायकों के विजन डॉक्यूमेंट को जमीन पर उतारने का काम जिला योजना समिति करेगी। मप्र में 5 साल बाद एक बार फिर जिला सरकार की वापसी होने जा रही है। इसके तहत जिला योजना समिति के माध्यम से अधिकांश फैसले लिए जाने का अधिकार जिले के प्रभारी मंत्री के हाथ में होगा। इससे व्यवस्था का विकेंद्रीकरण होगा। सूत्रों का कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने जिला योजना समिति के संबंध में दिशा-निर्देश का प्रारूप भी तैयार कर लिया है, जिसे मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद जारी किया जाएगा। प्रदेश में 2003 के पहले लागू जिला सरकार के मॉडल को 2019 में कमलनाथ सरकार ने संशोधित किया था। इसमें जिला योजना समिति का दायरा बढ़ाया गया। समिति में तीन सदस्य और बढ़ाए गए ताकि जिला स्तर पर राजनीतिक जमावट बेहतर की जा सके। समिति को 2 करोड़ रुपए तक के कामों को मंजूर करने का अधिकार दिया गया था। जिले के भीतर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का तबादला भी समिति की सिफारिश पर प्रभारी मंत्री के अप्रूवल से किए जाने का प्रावधान भी किया गया था। इतना ही नहीं, हर विकासखंड को 2-2 करोड़ रुपए का विशेष फंड भी दिया गया था।

मप्र को बीमारू राज्य से उबारने वाली भाजपा का अब पूरा फोकस इस बात पर है कि प्रदेश देश का सबसे विकसित राज्य बन जाए। इसके लिए अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मोर्चा संभाला है। अपने मिशन को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने हर विधानसभा क्षेत्र में 2028 तक 100 करोड़ रुपए का विकास कार्य कराने की रणनीति बनाई है। इसके लिए सरकार विजन

विपक्ष का भेदभाव का आरोप

नई सरकार के गठन के बाद फरवरी 2024 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधायकों से उनके निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए 15-15 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मांगे थे। इसके लिए बजट में राशि का प्रावधान भी कर दिया था। भाजपा के विधायकों ने प्रस्ताव बनाकर दिए, मगर कांग्रेस विधायकों ने भेदभाव का आरोप लगाया था। बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सदन में कहा था कि भाजपा विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए का फंड दिया गया। कांग्रेस विधायकों से मात्र 5-5 करोड़ के प्रस्ताव लिए गए, लेकिन अब तक एक रुपया भी नहीं मिला। संविधान की शपथ लेने के बाद ये भेदभाव करना संविधान का अपमान है। विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का कहना है कि कांग्रेस के विधायकों को विजन डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट मिला ही नहीं है। ऐसा पहले भी हो चुका है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने विधायकों से 15-15 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मांगे थे। कांग्रेस के विधायकों को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का विपक्ष के विधायकों के साथ किया जा रहा भेदभाव संविधान के खिलाफ है। वहीं, इस मसले पर मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि कांग्रेस के विधायकों को विकास से कोई मतलब नहीं है।

डॉक्यूमेंट बनवा रही है। विजन डॉक्यूमेंट में विधायक 100 करोड़ रुपए के कार्य शामिल कर सकते हैं। इसमें 40 करोड़ विधायक निधि, सांसद निधि, जन-भागीदारी, सीएसआर, रिडेंसीफिकेशन और अन्य रिडेवलपमेंट मद से आएंगे। बाकी 60 करोड़ राज्य सरकार हर साल 15-15 करोड़ करके जारी करेगी। हर विधायक अपनी विधानसभा में कलेक्टर के सहयोग से उद्योगों के लिए जमीन आरक्षित कराएंगे और उसे औद्योगिक क्षेत्र घोषित करके उद्योग लगवाए जाएंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में विकास के लिए विधायकों को अब और पावरफुल किया जा रहा है। उनके अधिकारों को बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सभी विधानसभाओं में अगले 4 वर्षों के विकास का खाका खींचने के लिए विधायक क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें। समय-सीमा और जिम्मेदारियां तय हों। उन्होंने कहा, विजन प्लान विधायक, कलेक्टर, विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से तैयार किया जाएगा। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार करके लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर फोकस किया जाए।

मप्र की भाजपा सरकार ने प्रदेश की हर विधानसभा में विकास की नई तहरीर लिखने की तैयारी की है। इसके लिए हर विधानसभा से विजन डॉक्यूमेंट तैयार करवाया जा रहा है। करोड़ों रुपए से होने वाली इस कवायद में महज प्रदेश के भाजपा विधायकों को शामिल किया गया है। जबकि कांग्रेस विधायकों को इससे दूर रखने की मंशा है। जहां भाजपा विधायक इस काम के लिए अपने क्षेत्र की प्राथमिकताएं तय करने में जुट गए हैं, वहीं कांग्रेस को इसकी न तो जानकारी दी गई है और न ही इन क्षेत्रों के विकास की कोई बात की गई है। विजन डॉक्यूमेंट के तहत तय किया गया है कि इसके तहत विधानसभा के विकास पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस विजन के तहत जारी होने वाली राशि अगले 4 साल में विकास पर खर्च करने की बाध्यता भी विधायकों पर होगी। सूत्रों का कहना है कि इस योजना के तहत सिर्फ भाजपा विधायकों को ही फंड दिया जाएगा।

बताया जा रहा है कि सरकार ने विधायकों से विजन डाक्यूमेंट तैयार करने को कहा है। बताया जा रहा है कि विजन डॉक्यूमेंट के हिसाब से प्राथमिकता तय होगी। इसके लिए यह भी कहा गया है कि विधायकों को जारी की गई राशि इसी मद में खर्च करनी होगी। साथ ही इन कामों की मॉनिटरिंग भी करनी होगी।

इधर प्रदेश सरकार के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया है कि विजन डॉक्यूमेंट की कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि एक मुखिया के लिए विकास का दोहरा मापदंड रखना प्रदेश विकास के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। मप्र खेल मंत्री विश्वास सारंग ने दावा किया कि विजन डॉक्यूमेंट से प्रदेश की जनता का कल्याण होगा। उन्होंने कहा कि विकास का विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। विश्वास सारंग ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सोच को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हर विधानसभा क्षेत्र के विकास पर फोकस किया है। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश की सभी विधानसभाओं में विकास कार्यों का विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। विश्वास सारंग कहते हैं कि हमारी सरकार सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। हम प्रदेश का संपूर्ण विकास चाहते हैं। इसलिए सभी विधायकों से विकास के विजन डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। आधारभूत और बुनियादी विकास के साथ ही समय सीमा में योजना बनाकर काम किया जाएगा।

कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया है कि उन्हें इस विजन डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट की जानकारी ही नहीं दी गई, जबकि भाजपा के विधायकों को इसका फायदा मिल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि पिछले फरवरी में भी भाजपा विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए के प्रस्ताव दिए गए थे, जबकि कांग्रेस विधायकों को केवल 5-5 करोड़ रुपए के प्रस्ताव ही दिए गए। कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष के विधायकों के साथ भेदभाव कर रही है और यह संविधान के खिलाफ है। विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं या नहीं? रोजगार के अवसर कैसे पैदा होंगे? बच्चियां स्कूल जा रही हैं या नहीं? बच्चे कुपोषित हैं तो क्यों हैं? अब इन सारे सवालों के जवाब विधायक ही तलाशेंगे। दरअसल, मप्र की डॉ. मोहन यादव सरकार हर विधानसभा इलाके में विकास कार्यों पर अगले चार साल में 100 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। विधायकों को विधानसभा क्षेत्र का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए कहा गया है। विधायक जो प्राथमिकताएं और विजन तय करेंगे, उसके ही हिसाब से सरकार पैसा खर्च करेगी।

● **कुमार विनोद**

जिले के हर ब्लॉक में औद्योगिक क्षेत्र

अगले 5 सालों में जिले के विकास का क्या खाका होगा। आखिर विकास की अगली अवधारणा क्या होगी। इसका विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने जिले के एमएलए और अफसर तैयारी कर रहे हैं। यह डॉक्यूमेंट अगले सप्ताह तक तैयार हो जाएगा। जिसके बाद सभी पांचों एमएलए से चर्चा के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। आज विभागों द्वारा पेश योजना में और बदलाव और नए आइडिया शामिल करने की बात कही गई है। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि 10-15 दिन पहले सभी केंद्रीय मंत्री के साथ बैठकर जिले के विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए चर्चा की गई थी आज सभी के साथ चर्चा कर 5 साल की आवश्यकताओं को देखते हुए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया है। जिसे आज जनप्रतिनिधियों के सामने पेश किया गया था कि किस वर्ष क्या-क्या एक्टिविटी की जाएगी। उसका उल्लेख इस डॉक्यूमेंट में है लेकिन कुछ जनप्रतिनिधियों ने इसमें बदलाव और विकास की अन्य योजनाओं को सम्मिलित करने की बात कही है, जिसके बाद इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार कर अगले सप्ताह होने वाली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

मप्र के कर्मचारियों को कैशलेस इलाज

मप्र के 7.5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों, साढ़े चार लाख पेंशनर्स और करीब 3 लाख निगम-मंडलों के कर्मचारियों को अब कैशलेस इलाज मिलेगा। इसके लिए मप्र सरकार उप्र, हरियाणा और राजस्थान सरकार की तर्ज पर सरकारी कर्मचारियों के लिए इलाज की आयुष्मान योजना जैसी स्कीम ला रही है। सरकार ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसके मुताबिक 5 लाख रुपए तक सामान्य और 10 लाख रुपए तक गंभीर बीमारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।

वर्तमान में मप्र के सरकारी कर्मचारियों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं उसके लिए प्रदेश सरकार ने अगस्त 2022 में चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों में संशोधन किया था। जिसके मुताबिक, राज्य के कर्मचारियों को केंद्रीय स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) में तय रेट के हिसाब से बीमारी के इलाज पर खर्च किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो लिवर ट्रांसप्लांट के लिए सरकार 4 लाख रुपए देती है। यह राशि भी पहले कर्मचारी को खर्च करना पड़ती है, बाद में जब वह बिल लगाता है तो भुगतान किया जाता है। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए करीब 20 लाख रुपए तक का खर्च आता है। यह सुविधा पेंशनर्स को भी मिलती है। लेकिन अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को कैशलेस सुविधा मिलेगी।

प्रस्तावित ड्राफ्ट के मुताबिक योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना होगा। योजना का लाभ लेने वाले कर्मचारियों से अंशदान लिया जाएगा। यह राशि उनके वेतन से काटी जाएगी। अंशदान 250 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक हो सकता है। मप्र सरकार ने अगस्त, 2022 में चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों में संशोधन किया था, जिसके मुताबिक राज्य के कर्मचारियों को केंद्रीय स्वास्थ्य योजना में तय रेट के हिसाब से बीमारी के इलाज पर खर्च किया जाता है। इसका लाभ प्रदेश के निगम, मंडल समेत राज्य सरकार के 15 लाख कर्मचारियों, पेंशनर्स के परिवारों को मिलेगा। इस योजना में कर्मचारियों को वेतन से हर साल 3000 से लेकर 12,000 रुपए अंशदान काटा जाएगा और शेष राशि सरकार जमा कराएगी। खास बात यह है कि कर्मचारियों के परिवार को इलाज की कैशलेस सुविधा होगी। योजना में कर्मचारियों के लिए सामान्य बीमारी में 5 लाख रुपए और गंभीर बीमारी में 10 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने का प्रावधान किया जा रहा है। जांच और इलाज के बाद शासन के कर्मचारी अपने विभाग से रिफंड भी ले सकेंगे।

गौरतलब है कि वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना शुरू होने के बाद कर्मचारी संगठनों ने इसी तरह की योजना लागू करने की मांग शुरू की थी। कांग्रेस ने इसे अपने चुनावी वचन पत्र में भी शामिल किया था। 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा कराने और कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने योजना का प्रस्ताव बनाया था। इसमें बीमा राशि का कुछ हिस्सा कर्मचारियों से लेकर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार कराया जाना था। फरवरी 2022 में इसका आदेश भी जारी हुआ था, लेकिन मार्च 2022 में कमलनाथ सरकार गिर गई और एक बार फिर शिवराज सरकार सत्ता में आई। शिवराज सरकार ने इस प्रस्ताव पर नए सिरे से काम किया। विधानसभा चुनाव-2023 से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 जुलाई 2023 को राजधानी के लाल परेड ग्राउंड पर संविदा कर्मचारियों के सम्मेलन को संबोधित किया था। इस दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री ने संविदा सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और इस वर्ग के अन्य कर्मचारियों को आयुष्मान योजना का लाभ देने की घोषणा की थी। इसके बाद 22 जुलाई 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी किए थे। सूत्रों का कहना है कि दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद मप्र ने 9 जुलाई 2024 को इसकी स्वीकृति देते हुए राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और महिला-बाल विकास के कर्मचारियों की जानकारी मांगी थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आयुष्मान कार्ड बनना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आदेश पूर्व में जारी हो चुके हैं, जबकि संविदा कर्मचारियों को लेकर फिलहाल प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है।

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री लक्ष्मी नारायण शर्मा का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022 से चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों को संशोधित करने के बाद से अस्पतालों को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) में निर्धारित दरों के अनुसार ही भुगतान किया जाता है। उपचार के लिए सीजीएचएस की दरें बाजार दर से 60 प्रतिशत तक कम हैं। इस कारण अस्पताल उपचार करने में आनाकानी करते हैं या फिर रोगियों से अतिरिक्त राशि लेते हैं। सरकारी अस्पताल से रेफर कराने पर ही निजी अस्पताल में उपचार कराने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति मिलती है। एक दिक्कत यह भी है कि दूसरे राज्यों में उपचार के लिए चिकित्सा शिक्षा संचालनालय की स्वीकृति लेना आवश्यक है। ओपीडी में उपचार कराने पर एक बार में अधिकतम 2500 रुपए प्रतिपूर्ति मिलती है। इससे अधिक होने पर सिविल सर्जन से लंबी बीमारी का प्रमाण पत्र लेना होता है।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

अन्य राज्यों में यह है प्रावधान

उप्र सरकार ने साल 2022 में 22 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू की है। योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना है। इसके जरिए सरकारी के अलावा निजी अस्पतालों में 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलता है। योजना का फायदा उन्हीं को मिलता है, जिनके स्टेट हेल्थ कार्ड बने हैं। उप्र सरकार की योजना में ऑफलाइन आवेदन की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाते हैं। हरियाणा सरकार ने इसी साल इस योजना की शुरुआत की है। पहले कुछ विभागों के कर्मचारियों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत योजना शुरू की गई। इसके बाद सरकार ने सभी विभागों के लिए इसे लागू कर दिया। योजना का फायदा कर्मचारियों को परिवार पहचान पत्र देने के बाद ही मिलेगा। हरियाणा में 6.5 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स हैं। कुल 569 अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। राजस्थान के कर्मचारियों के लिए आरजीएचएस यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम चलाई जा रही है। इसके तहत सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाती है।

108 एंबुलेंस संचालन में फर्जीवाड़ा

कंपनी को 10 महीने में 325 करोड़ का हुआ भुगतान

आरटीआई एक्टविस्ट पुनीत टंडन का कहना है कि सूचना के अधिकार से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्राप्त जानकारी अनुसार 10 माह में अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक कुल 10 माह में लगभग 325 करोड़ रुपयों का एनएचएम द्वारा जेएईएस को भुगतान किया गया है, जो कि अपने आप में एक जांच का विषय है। सूचना के अधिकार में मिली जानकारी के अनुसार साल 2023 के जून महीने में लगभग 1 करोड़ 60 लाख किलोमीटर की एंबुलेंस की रनिंग दिखाई गई। जिनके एवज में एनएचएम द्वारा जेएईएस को 30 करोड़ 50 लाख का भुगतान किया गया। साल 2023 के अक्टूबर महीने में लगभग 1 करोड़ 73 लाख किलोमीटर एंबुलेंस चलाई जाना बताई गई जिसके एवज में एनएचएम द्वारा जेएईएस को लगभग 35 करोड़ का भुगतान किया गया। साल 2023 के दिसंबर महीने में लगभग 1 करोड़ 96 लाख किलोमीटर एंबुलेंस चलाई जाना बताया गया है, जिसके एवज में एनएचएम द्वारा जेएईएस को लगभग 38 करोड़ का भुगतान किया गया। जनवरी 2024 में लगभग 1 करोड़ 88 लाख किलोमीटर से अधिक एंबुलेंस चलाने की जानकारी दी गई। जिसके एवज में एनएचएम द्वारा जेएईएस को लगभग 35 करोड़ 50 लाख से अधिक का भुगतान किया गया। लगभग 10 माह में 325 करोड़ रुपए का भुगतान एनएचएम द्वारा जेएईएस को किया गया है जो कि अपने आप में बड़ा भ्रष्टाचार होने के साथ एक जांच का विषय है।

मप्र में संचालित 108 संजीवनी एंबुलेंस में बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आरोप लगाया गया है कि सेवा का संचालन करने वाली कंपनी गलत आंकड़े दिखाकर फर्जीवाड़ा कर रही है। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार, विदिशा जिले में जिन मरीजों को भर्ती किया गया, उनके नामों में एक जनवरी 2023 को मीना नाम की गर्भवती महिला रिकॉर्ड में दर्ज है। मीना नाम की महिलाओं के आगे सरनेम और डिटेल पूरा दर्ज नहीं किया गया है। ऐसे कई मामले हैं। सिर्फ विदिशा जिले में जेएईएस एंबुलेंस द्वारा लगभग प्रतिदिन 160 से 200 व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं, जिसमें 80 प्रतिशत से ज्यादा गभर्वती महिलाओं के पंजीयन दर्ज होना दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मिली जानकारी में 10 माह में अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक कुल 10 माह में करीब 325 करोड़ रुपए का भुगतान एनएचएम द्वारा जेएईएस को किया गया है, जो एक जांच का विषय है।

गौरतलब है कि साल 2021 में एनएचएम मप्र ने जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेज के साथ किराये पर एंबुलेंस चलाने के लिए अनुबंध किया था। 14 अप्रैल 2022 से जेईएस ने एंबुलेंस की सुविधा मप्र में शुरू की। एनएचएम से हुए एग्रीमेंट के अनुसार जो वाहन जय अंबे कंपनी को दिए गए थे। उनमें लगभग 23 एएलएस (एडवांस लाईफ सपोर्ट) गाडियां, लगभग 319 बीएलएस गाडियां, जननी एंबुलेंस 60 टाईप बी के अतिरिक्ति (जेएईएस) द्वारा खरीद कर लगाई गई गाड़ियां निम्नानुसार हैं, जिसमें लगभग 144 एएलएस गाड़ियां, लगभग 516 बीएलएस (बेसिक लाईफ सपोर्ट) गाड़िया, लगभग 990 टाईप बी जननी एंबुलेंस के अतिरिक्त 104 हेल्प लाईन (15 सीटर) भी (जेएईएस) द्वारा गाड़ियां संचालित की जा रही हैं। एनएचएम द्वारा निष्पादित अनुबंध के अनुसार, प्रति किमी के हिसाब से भुगतान की जाने वाली राशि में सभी तरह के खर्चे व संसाधन शामिल हैं। जिसमें गाड़ियों का रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन, ड्यूटी टोल टैक्स, दवाईयां, मेडिकल इक्युपमेंट सामग्री आदि भी शामिल हैं। इसके बावजूद जेएईएस द्वारा मप्र में संचालित की जा रही गाड़ियों का मप्र के आरटीओ दफ्तर में रजिस्ट्रेशन कराने की अपेक्षा छत्तीसगढ़ आरटीओ में रजिस्ट्रेशन है और रोड टैक्स भी छत्तीसगढ़ सरकार को भरा गया है, जबकि किसी अन्य राज्य के आरटीओ में पंजीकृत वाहन को दूसरे राज्य में संचालित किया जाता है, तो उस राज्य के आरटीओ कार्यालय में उनका पंजीयन होना चाहिए। जबकि मप्र में जेएईएस द्वारा अनुबंध तारीख से लेकर आज भी करीब 1950 एंबुलेंस छत्तीसगढ़ नंबर प्लेट पर चलाई जा रही हैं जो कि जांच का विषय है।

एनएचएम से हुए अनुबंध की शर्तों के अनुसार (जेएईएस) द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी छिपाना या लिखित में सूचित कर अनुमति ना लेना अपने आप में भ्रष्ट आचरण की परिधि में आएगा। क्या अनुबंध अनुसार जेएईएस द्वारा एनएचएम को लिखित में सूचित कर अनुमति मांगी गई थी कि उनके द्वारा लगाए गए समस्त एंबुलेंस का रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स आदि का छत्तीसगढ़ राज्य में भुगतान कर गाड़ियां मप्र में संचालित की जा सकेंगी। यदि ऐसा हुआ है तो मप्र राज्य को लगभग 30 से 40 करोड़ के राजस्व की हानि हुई है, क्योंकि (जेएईएस) द्वारा समस्त एंबुलेंस छत्तीसगढ़ में पंजीयन कराकर छत्तीसगढ़ नंबर प्लेट के साथ मप्र में संचालित की जा रही हैं, जो अनुबंध अनुसार मप्र सरकार के साथ बड़ा आपराधिक कृत्य नजर आ रहा है। परिवहन विभाग के नियमों के मुताबिक एक राज्य का वाहन ट्रांसफर कराए बिना दूसरे राज्य में छह महीने से ज्यादा की अवधि तक नहीं चलाया जा सकता। जबकि, मप्र में जेएईएस द्वारा अनुबंध करने से लेकर आज तक लगभग 1950 एंबुलेंस छत्तीसगढ़ नंबर प्लेट की चलाई जा रही है जो कि एक जांच का विषय है। इसको लेकर परिवहन विभाग के प्रमुख अधिकारी को लिखित में शिकायत की गई थी, जिसके बाद भी आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। आज भी जेएईएस द्वारा छत्तीसगढ़ की नंबर प्लेट लगाकर मप्र में एंबुलेंस चलाई जा रही है। क्या परिवहन विभाग ने (जेएईएस) को किसी भी प्रकार का नोटिस दिया या कार्यवाही की गई, यदि नहीं तो क्यों नहीं की गई?

● **बृजेश साहू**

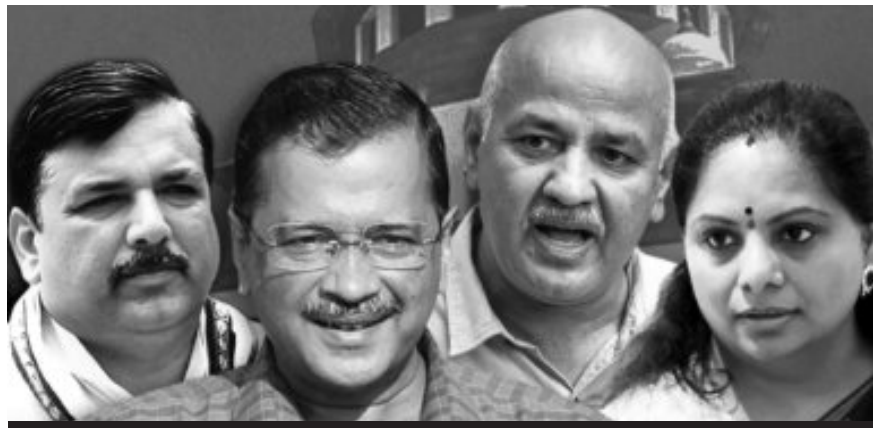

शराब घोटाले के आरोपी बाहर

दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल समेत 7 आरोपी जमानत पर बाहर आ चुके हैं। दिलचस्प बात है कि केस में बेल पाने वाले सभी आरोपियों की जमानत का आधार भी एक ही है। केस की ट्रायल का शुरू न होना। दिल्ली में जुलाई 2022 में शराब घोटाले का मामला सामने आया था।

दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। केजरीवाल इस केस में 7वें आरोपी हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। केजरीवाल से पहले शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, के कविता, विजय नायर, समीर महेंद्रू और अरुण पिल्लई को जमानत मिल चुकी है। दिलचस्प बात है कि शराब घोटाला मामले में संजय सिंह को छोड़कर बाकी के सभी आरोपियों को पिछले 35 दिन के भीतर जमानत मिली है। इतना ही नहीं, केस में बेल पाने वाले सभी आरोपियों की जमानत का आधार भी एक ही है। केस की ट्रायल का शुरू न होना।

दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को मार्च 2024 में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आप दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे, जो पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुए। आप ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को राजनीतिक कार्रवाई बताया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी ऐसे वक्त में हुई थी, जब आप के टॉप-3 नेता जेल में बंद थे। इनमें मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह का नाम शामिल है। लोकसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत जरूर दी, लेकिन फिर उन्हें जेल जाना पड़ा। जून 2024 में इस मामले में ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से नियमित जमानत मिल गई, लेकिन तभी केस में सीबीआई की एंट्री हो गई। सीबीआई ने जून 2024 में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।

मनीष सिसोदिया- दिल्ली शराब घोटाले में पहली बड़ी गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की हुई थी। सिसोदिया को फरवरी 2023 में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सिसोदिया पर आरोप है कि दिल्ली सरकार में आबकारी विभाग के मंत्री रहते हुए इन्होंने ऐसी नीति तैयार की, जिससे कुछ शराब माफियाओं का फायदा हुआ। आरोप के मुताबिक सिसोदिया और उनकी पार्टी को इसके एवज में शराब कंपनियों से पैसे मिले। वहीं सिसोदिया की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था कि यह पूरा ही मामला मनगढ़ंत है। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2024 को मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। कोर्ट का कहना था कि मामले में ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, इसलिए सिसोदिया जमानत के हकदार हैं। सिसोदिया की जमानत पर बहस करते हुए सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि अक्टूबर 2023 में ईडी और सीबीआई ने इस केस की ट्रायल जल्द ही शुरू करने की बात कही थी, लेकिन 10 महीने बाद भी केस की ट्रायल शुरू नहीं हुई है। सिसोदिया केस पर जमानत देते हुए कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी भी की थी। कोर्ट का कहना था कि जेल अपवाद है और बेल नियम।

संजय सिंह- आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी दिल्ली शराब घोटाले के मामले में बेल पा चुके हैं। सिंह को अक्टूबर 2023 में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। सिंह पर शराब नीति मामले में साउथ ग्रुप की कंपनी से 2 करोड़ रुपए लेने का आरोप है। इसी साल अप्रैल में सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। सिंह की जमानत का ईडी ने विरोध तक नहीं किया था। सिंह दिल्ली शराब घोटाले केस में करीब 6 महीने तक जेल में बंद रहे।

के कविता- तेलंगाना की बीआरएस के प्रमुख के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी है। कविता को मार्च 2023 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर पॉलिसी बनवाने के बदले पैसे के लेनदेन में शामिल रहने का आरोप है। कविता को 27 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी।

विजय नायर- आप के कम्युनिकेशन विभाग के इंचार्ज विजय नायर भी दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में जेल जा चुके हैं। नायर को सितंबर 2022 में गिरफ्तार किया था। नायर की पहली गिरफ्तारी सीबीआई ने की थी फिर नवंबर 2023 में उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। नायर को भी इसी महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। नायर पर ही शराब घोटाले की साजिश का आरोप है। हालांकि, केस में ट्रायल शुरू नहीं होने की वजह से नायर को कोर्ट ने जमानत दे दी। नायर की जमानत पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा था कि किसी भी आरोपी को अंतहीन समय तक के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता है।

समीर महेंद्रू- इंडोस्प्रिट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर समीर महेंद्रू भी दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। समीर महेंद्रू पर आरोप है कि इनकी कंपनी ने नीति बदलवाने के एवज में पैसे दिए। महेंद्रू को सितंबर 2022 में गिरफ्तार किया था। महेंद्रू भी जेल से बाहर आ चुके हैं।

अरुण पिल्लई- बिजनेसमैन अरुण पिल्लई भी दिल्ली शराब घोटाले के केस में जेल जा चुके हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने विजय नायर के साथ मिलकर घोटाले की पूरी साजिश रची। उन्हें मार्च 2023 में गिरफ्तार किया गया था। पिल्लई को कुछ पहले इस केस में जमानत मिली है।

● **कुमार राजेंद्र**

दिल्ली का कथित शराब घोटाला

कोरोना के दौरान नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति शुरू की थी। इस नीति के तहत दिल्ली में शराब का ठेका प्राइवेट कंपनियों को देने की बात कही गई। जुलाई 2022 में इस नीति को लेकर बवाल मचा, जिसके बाद एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई को जांच सौंपी। सीबीआई ने इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एफआईआर की। इस एफआईआर के बाद इसमें ईडी की एंट्री हुई। ईडी के मुताबिक यह शराब घोटाला 100 करोड़ से ज्यादा का है। शराब पॉलिसी बदलवाने के एवज में आप की सरकार ने साउथ कंपनियों से पैसे लिए। वहीं आप का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हुई और फाइल पर आखिरी मुहर तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल वैजल ने लगाई थी।

सहकारी समितियों में नेता बनेंगे प्रशासक

प्रशासकों की कार्यशैली से असंतुष्ट प्रदेश के किसान

प्रदेश में आखिरी बार सहकारिता के चुनाव साल 2013 में हुए थे। इनका कार्यकाल साल 2018 में पूरा हो चुका है। जिसके बाद से प्रदेश में 55 हजार से ज्यादा समितियां और सहकारी बैंकों के संचालक मंडल भंग हैं। इस स्थिति में शासन द्वारा नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी प्रशासक के रूप में काम संभाल रहे हैं। वहीं अपने बीच के प्रतिनिधि न होने से कई समितियां डिफॉल्टर हो चुकी हैं। अतिरिक्त भार होने के कारण अधिकारियों की रूचि किसानों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में नहीं होती। इस वजह से खाद-बीज वितरण से लेकर राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायतों में बीते कुछ वर्षों में खासा इजाफा हुआ है। समय पर खाद-बीज उपलब्ध नहीं होने और सहकारी सेक्टर से मिलने वाले फायदों से वंचित होने के कारण किसानों में भी नाराजगी बढ़ रही है।

मप्र में सहकारिता चुनाव पिछले 12 साल से टलता जा रहा है। एक बार फिर से सहकारी समितियों के चुनाव अधर में लटकते दिख रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार ने संगठन के सुझाव के बाद नया रास्ता ढूंढ निकाला है। सरकार प्रशासकों की जगह भाजपा के सहकारी नेताओं को मनोनीत करेगी। इसके लिए सहकारी समितियों में गैर-प्रशासनिक और बिना निर्वाचन ही पार्टी के सक्रिय कार्यकताओं को बैठाने का मसौदा भी तैयार हो चुका है। बीते महीने संगठन और सरकार के बीच इसको लेकर मैराथन बैठक भी हो चुकी है। वहीं संगठन ने जिलों में सक्रिय सहकारी क्षेत्र के नेताओं के नामों का पैनल भी मांगा है। जिला इकाई स्थानीय स्तर पर सहमति के बाद जो पैनल भेजेगी उसमें तीन से पांच नेताओं के नाम होंगे। प्रदेश स्तर पर इन्हीं में से एक का नाम समिति का प्रशासक बनाने चुना जाएगा। यानी सहकारी क्षेत्र के नेटवर्क पर भी भाजपा अपनी पकड़ मजबूत करने का खाका खींच चुकी है। इसे कई जिलों में सहकारिता पर कांग्रेस की मजबूत पकड़ को ढीला करने की रणनीति भी बताया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, सहकारी समितियों की मतदाता सूची का काम लंबित रहने के चलते संगठन और सरकार सहकारी संस्थाओं में प्रशासक नियुक्त करने का मन बना रही है। प्रदेश भाजपा संगठन ने प्रशासक को लेकर जिलाध्यक्षों से तीन नामों का पैनल भेजन को कहा है। इस पैनल को लेकर जिले की कोर कमेटी से चर्चा की जाएगी। इसके बाद सर्वसम्मति से एक नाम फाइनल कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के चुनाव किसी न किसी वजह से टलते आ रहे हैं। अंतिम बार यह चुनाव 2012 में हुए थे। तब कुछ बैंकों में कामकाजी समितियां बनाकर अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे तो कुछ बैंकों में संचालक मंडल के चुनाव कराकर अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। इन अध्यक्षों का कार्यकाल पांच साल बाद खत्म हो गया था। इसके बाद सहकारी समितियों में चुनाव नहीं हुए और अधिकांश बैंकों और अन्य सहकारी संस्थाओं में सरकारी अफसरों को प्रशासक बनाकर बैठा दिया गया। इसके बाद से लगातार चुनावों की प्रक्रिया टलती रही और इन पदों पर सरकारी अधिकारियों का कब्जा रहा। प्रदेश में 4500 प्राथमिक सहकारी साख समितियां हैं। इसके अलावा 38 केंद्रीय को-आपरेटिव बैंक हैं। कुप्रबंधन के कारण अधिकांश सहकारी संस्थाएं और बैंक घाटे में चल रहे हैं। पूर्व में सरकार ने कुछ बैंकों को अपनी गारंटी पर लोन दिलाकर घाटे से उबारने की कोशिश की थी पर इस प्रयास में भी सफलता नहीं मिल पाई थी।

2018 के विधानसभा चुनावों के कुछ महीने पहले सरकार ने सहकारिता अधिनियम में संशोधन करते हुए अधिकारियों के अलावा अशासकीय व्यक्तियों और सांसद, विधायकों को भी सहकारी संस्थाओं में प्रशासक बनाने का तय किया। इसके बाद अपेक्स बैंक समेत कुछ अन्य संस्थाओं, को-आपरेटिव बैंकों में सहकारिता से जुड़े पात्र सदस्यों को प्रशासक बनाया गया। 2018 में कांग्रेस सरकार आते ही अशासकीय व्यक्तियों को प्रशासक पद से हटाकर बोर्ड को भंग कर दिया गया। हालांकि सरकार गिरने से कुछ समय पहले कमलनाथ सरकार ने कुछ संस्थाओं में अशासकीय व्यक्तियों को प्रशासक बनाया पर भाजपा सरकार आते ही इन्हें हटा दिया गया। इसके बाद से ही बैंक और अन्य सहकारी संस्थाओं पर सरकारी अधिकारी प्रशासक बने बैठे हैं। इस मामले में हाईकोर्ट में भी जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने सरकार से इन समितियों में चुनाव कराने को कहा था। इन मामलों में प्रक्रिया भी शुरू की गई पर अब तक कई समितियों में मतदाता सूची ही फाइनल नहीं हो पाई है।

मप्र में सहकारिता क्षेत्र गांव-गांव में लाखों किसानों तक फैला हुआ है। इससे सीधे तौर पर 50 लाख से ज्यादा किसान और उनके परिवार भी जुड़े हैं। यानी प्रदेश में सहकारी क्षेत्र बहुत व्यापक है। बावजूद इसके बीते 12 सालों से प्रदेश में सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं के चुनाव ही नहीं कराए गए हैं। सहकारी समितियां भंग पड़ी हैं और इनकी कमान प्रशासक के रूप में सरकारी अधिकारियों के पास है। सहकारिता चुनाव न होने के कारण इस क्षेत्र में सक्रिय नेताओं की राजनीति भी ठप हो चुकी है और कई नेता तो अपना अस्तित्व ही खो चुके हैं। सरकार बार-बार सहकारी समितियों के चुनाव टालती आ रही है। यह स्थिति तब और भी चिंताजनक हो जाती है, जबकि सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ इन्हीं समितियों के माध्यम से किसान और अंचल के लाखों ग्रामीणों तक पहुंचता है। किसानों को रियायती दर पर उपलब्ध खाद-बीज से लेकर राशन वितरण तक का कामकाज सहकारी समितियों के माध्यम से ही होता है। अंचलों में कुछ गांवों को मिलाकर या पंचायत स्तर पर स्थानीय किसानों को जोड़कर समिति बनती है। इसके सदस्य किसान अपने बीच से प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं जो क्षेत्रीय सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंकों का संचालक मंडल बनाते हैं। इन्हीं के बीच से राज्य सहकारी बैंक यानी अपेक्स बैंक के संचालक मंडल में प्रतिनिधि पहुंचते हैं। यानी सहकारिता के माध्यम से किसान गांव से लेकर राज्य स्तर तक आपस में जुड़े होते हैं। सरकार के सहकारिता विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन इन्हीं बैंक और समितियों के जरिए होता है।

● **लोकेश शर्मा**

सड़क विकास निगम वसूलेगा टोल टैक्स

मप्र के हाईवे पर अंधाधुन टैक्स वसूलने का खेल जारी है। टोल कंपनियां सड़क निर्माण पर आई लागत से कहीं ज्यादा टोल वसूल रही हैं। इसको लेकर सरकार के पास लगातार शिकायतें पहुंच रही हैं। ऐसे में अब सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में बनने वाली नई सड़कों पर प्राइवेट कंपनियों को टोल टैक्स वसूली का काम नहीं दिया जाएगा। अब खुद सड़क विकास निगम नई सड़कों पर टोल टैक्स वसूलेगा। दरअसल, निगम का मानना है कि सड़क बनने के बाद आवागमन बढ़ता है और इससे ठेका एजेंसी प्रतिवर्ष लाभ उठाती हैं, लेकिन अगर सड़क विकास निगम टोल टैक्स वसूलेगा तो आवागमन बढ़ने के साथ ही निगम की आय भी बढ़ेगी।

दरअसल, मप्र में बीते 15-16 सालों में सड़कों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। आप भी जब बेहतरीन सड़कों से गुजरते हैं तो आपको हर टोल प्लाजा पर टोल देना पड़ता है। आपके इस टोल के पैसे से टोल कंपनियां करोड़ों रुपए कमा रही हैं। टोल कंपनियों और सरकार की कमाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टोल से इन्होंने सड़क की लागत काफी पहले निकाल ली है लेकिन टोल का खेल अभी भी जारी है। स्थानीय लोग कहते हैं कि सड़कें तो अच्छी बन गई हैं लेकिन यहां टोल जो लगता है वो महंगा है। टोल बंद होना चाहिए। जब गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स पहले ही जमा करा लिया जाता है और फिर टोल टैक्स भी देना होता है, जो कि महंगा पड़ता है। इंदौर के रास्ते पर हर 50 किलोमीटर पर एक टोल नाका आता है। टोल नाकों पर पैसा बहुत ज्यादा लगता है। जैसे नयागांव टोल पर 35 रुपए लगते हैं, पिपलिया मंडी पर 55 रुपए लगते हैं, माननखेड़ा में लगते हैं, बिलपांक में लगते हैं। ऐसे लेबड़ तक टोल प्लाजा देना पड़ता है। कहीं 45 रुपए तो कहीं 50 रुपए तो कहीं इससे भी ज्यादा टोल देना पड़ता है। आलम ये है कि आने-जाने दोनों समय टोल देना पड़ता है।

जानकारी के अनुसार, प्रदेश में नई सड़कों पर टोल टैक्स वसूली की व्यवस्था बदलने की तैयारियों का खाका तैयार हो रहा है। इसके तहत मप्र की सड़कों पर अब सड़क विकास निगम ही टोल वसूलेगा। स्टेट हाईवे पर बनने वाली नई सड़कों के लिए जारी टेंडर की शर्तों में ही इसके प्रविधान होंगे। इसके एवज में सड़क निर्माण करने वाली ठेका एजेंसी को सड़क बनाने में व्यय होने वाली राशि का 40 प्रतिशत निर्माण के समय और शेष 60 प्रतिशत राशि 15 साल का अनुबंध कर प्रति वर्ष भुगतान की जाएगी। दरअसल, निगम का मानना है कि सड़क बनने के बाद आवागमन बढ़ता है और इससे ठेका एजेंसी प्रतिवर्ष लाभ उठाती हैं, लेकिन अगर सड़क विकास निगम टोल टैक्स वसूलेगा तो आवागमन बढ़ने के साथ ही निगम की आय भी बढ़ेगी। नई सड़कों का ट्रैफिक सर्वे कराकर तय किया जाएगा टोल कितना और कहां वसूला जा सकता है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लोगों से सुझाव भी लिए जाएंगे।

सड़क विकास निगम उज्जैन-जावरा, इंदौर-उज्जैन के अलावा 14 नई सड़कें बना रहा है। इन सड़कों पर निगम ही टोल टैक्स वसूलगा। इसके लिए यातायात गणना के आधार पर टोल टैक्स का निर्धारण किया जाएगा। 14 नई सड़कों में पांच सड़कें ऐसी हैं, जो उप्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से लगी हैं। ऐसे में यहां यातायात बढ़ने की संभावना अधिक है। यहां निगम द्वारा टोल वसूलने से राज्य का राजस्व संग्रहण बढ़ेगा और निगम आर्थिक रूप से भी सशक्त होगा। बजट के अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए एमपीआरडीसी (मप्र सड़क विकास निगम) द्वारा निर्मित मार्गों को यूजर की योजना के तहत चयन के लिए यातायात की गणना कर संभावित वार्षिक संग्रहण राशि (एपीसी) का निर्धारण किया जाएगा। निर्मित मार्गों का टीओटी (टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर), ओएमटी (ऑपरेट मेंटेन एंड ट्रांसफर) मॉडल में परीक्षण कर विकसित किए जाएंगे। यह प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा और वहां से स्वीकृति के बाद टोल टैक्स का निर्धारण कर वसूली की व्यवस्था की जाएगी। यातायात की गणना के आधार पर संभावित राजस्व का आंकलन कर वार्षिक अनुमानित संग्रहण (एपीसी) निर्धारण के बाद प्रारंभिक तौर पर केवल व्यवसायिक वाहनों से टोल वसूला जाएगा, इसके बाद आवश्यक होने पर निजी वाहनों से भी टोल टैक्स वसूलने का निर्णय लिया जा सकेगा।

● श्याम सिंह सिकरवार

लागत से वसूला जा रहा टोल टैक्स

मप्र सरकार ने भोपाल से देवास के बीच स्टेट हाईवे का निर्माण कराया था। यह एक फोरलेन हाईवे है लेकिन यह हाईवे जितने में बना है उससे कहीं ज्यादा टोल लोगों से वसूला जा चुका है। इतना ही नहीं लागत से ज्यादा टोल वसूले जाने के बाद भी टोल वसूलने का खेल जारी है। ये बातें हम हवा में नहीं बल्कि सरकारी कागज के आधार पर कह रहे हैं। प्रदेश सरकार खुद ये मानती है कि भोपाल से देवास तक फोरलेन हाईवे के निर्माण पर 426 करोड़ रुपए की लागत आई थी। मसलन, एक सरकारी दस्तावेज से पता चलता है कि अगस्त 2010 से अब तक 1610 करोड़ रुपए टोल के वसूले जा चुके हैं। मसलन, राज्य सरकार ने आपसे 1,184 करोड़ रुपए ज्यादा टोल वसूल लिए हैं। यही नहीं, सरकार आपसे 9 साल और इस हाईवे पर टोल वसूलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएनडी को लेकर एक आदेश जारी किया था, जिसमें टोल को बंद करने का आदेश दिया गया था। दिल्ली नोएडा डीएनडी टोल रोड 407 करोड़ रुपए में बनी थी, जिस पर 2200 करोड़ का टोल टैक्स जनता से लिया जा चुका था, जिसमें आगे कई वर्षों तक टोल वसूली होनी थी। हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत बताते हुए टोल फ्री कराया। अब जरूरत है कि देश में ऐसा ही हर उस सड़क को टोल फ्री किया जाए, जहां लगात से कई गुना ज्यादा टैक्स सरकारें लेती आ रही हैं। अब जरा राजस्थान की सीमा से शुरू होकर मप्र की आर्थिक राजधानी इंदौर तक जाने वाली नयागांव-जावरा-लेबड़ फोरलेन हाइवे का सच जान लीजिए। 250 किलोमीटर में फैले इस स्टेट हाईवे को बनाने में जितना पैसा खर्च हुआ। उससे चार-पांच गुना ज्यादा टोल लेने के बाद भी जनता की जेब से टोल निकालना जारी है। प्रदेश में जावरा से नयागांव तक सड़क बनाने की लागत 425.71 करोड़ रुपए आई। इस सड़क पर टोल वसूली 17 फरवरी 2012 से शुरु हुई। अब तक यहां से 2168 करोड़ रुपए टोल वसूला जा चुका है, यानी 1743 करोड़ रुपए ज्यादा। इस सड़क पर सरकार का 26 अक्टूबर 2033 तक टोल वसूलने का प्लान है।

बुंदेलखंड में कब पूरे होंगे वादे?

राजा-महाराजाओं की ऐतिहासिक विरासत से ताल्लुक रखने वाले बुंदेलखंड के दिन कब बदलेंगे, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। साल दर साल लोगों को यही उम्मीद रहती है कि अब कुछ बेहतर होगा, कुछ ऐसा होगा कि किसानों के टूटते मनोबल को संबल मिलेगा, सूखते खेतों की दरारों में जल्द पानी दौड़ेगा और युवाओं के हाथों में रोजगार होगा। लेकिन, बुंदेलखंड के लोगों की यह उम्मीद अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। महंगाई की मार और हाथों में बेरोजगारी होने के कारण किसान अपनी जमीन बेचकर जा रहे हैं। जमीनों से दूर होते किसान के पीछे का सच बुंदेलखंड में जलसंकट ही है। बंजर जमीन और सूखते कंठ इस हकीकत की गवाही दे रहे हैं।

पन्ना जैसी डायमंड नगरी के लोगों को दो जून की रोटी के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। बीते बीस वर्षों में ऐसा कुछ नहीं हो सका, जिससे स्थानीय लोगों को काम-धंधा मिलता या किसानों के खेतों में हरियाली बिखरती हुई दिखाई दे। जबकि चुनावी मंचों पर दावे और वादे करने वाले नेता हमेशा बुंदेलखंड के विकास की बातें कहते रहे हैं। जब चुनाव आते हैं तब हर वर्ग के विकास की बात कही जाती है। इसी विश्वास के चलते लोगों ने खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में हर सांसद को भरपूर प्यार दिया। लेकिन, चुनाव के बाद फिर क्षेत्र के लोगों को पलटकर नहीं देखा।

पूरे बुंदेलखंड में गर्मियों के समय पानी की किल्लत रहती है। चाहे बुंदेलखंड के मप्र क्षेत्र की बात हो या उप्र की, हर जगह पानी के लिए लोग भटकते हैं। केन-बेतवा प्रोजेक्ट शुरू होने से मप्र के छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, विदिशा, सागर, शिवपुरी, दतिया और रायसेन जिले को इस परियोजना का लाभ मिलेगा। वहीं उप्र के महोबा, बांदा, झांसी और ललितपुर जिले लाभान्वित होंगे। इतनी बड़ी आबादी को फायदा होने के बावजूद अब तक यह प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका है। 1999 के बाद से बुंदेलखंड की खजुराहो सीट पर भाजपा का राज चला आ रहा है। इससे पहले कांग्रेस का दबदबा था। इस बार फिर मंचों से दावे और वादों का दौर शुरू हो गया है। 44 हजार करोड़ के केन-बेतवा प्रोजेक्ट की अभी तक ईंट नहीं रखी जा सकी है।

बुंदेलखंड के मुद्दों पर छतरपुर भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रभान सिंह का कहना है कि हमारी सरकार ने बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने का काम किया है। हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई हैं। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में कई बड़े काम हुए हैं। खजुराहो का आधुनिक रेलवे स्टेशन, हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर सहित कई बड़े काम हुए हैं। गांवों से लेकर शहरों तक विकास का खाका खींचा गया है। विकास की यह रफ्तार आगे भी जारी रहेगी। वहीं खजुराहो लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रहे आरबी प्रजापति का कहना है कि भाजपा के राज में हमेशा झूठे वादे होते रहे हैं। आज खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में लोग परेशान हैं। युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। किसानों के खेत सूखे पड़े हैं। लोगों के पास काम-धंधा नहीं है, फिर कैसा विकास है। लंबे समय से यहां भाजपा काबिज रही है, लेकिन कितना ध्यान दिया गया है यह बुंदेलखंड की तस्वीर खुद बयां कर रही है।

गत दिनों बुंदेलखंड जल मंच की बैठक में बुंदेलखंड में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव पर चिंता व्यक्त की गई। साथ ही क्षेत्र की अन्य समस्याओं पर भी चर्चा हुई। इस दरम्यान तय हुआ कि बुंदेलखंड की विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए आगामी पांच सालों के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाएगी। बैठक में जल जन जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक संजय सिंह ने कहा कि क्षेत्र में बेरोजगारी, अतिवृष्टि, पलायन और सामाजिक-आर्थिक विपन्नता जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। इस दौरान उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए बुंदेलखंड की सभी संस्थाओं को एकजुट होकर आगे आने का आव्हान किया। साथ ही कहा कि बुंदेलखंड के विकास की रूपरेखा तय करते हुए आगामी पांच सालों के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाएगी। देश और प्रदेश की सरकारों को भी यहां की समस्याओं की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान मार्गश्री संस्था के निदेशक ध्रुव सिंह यादव ने स्वशासन की प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात कही।

वरिष्ठ समाजसेवी अमित त्रिपाठी का कहना है कि जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ठोस और प्रभावी कार्य के लिए एक सशक्त फोरम का गठन किया जाना चाहिए। बुंदेलखंड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसर डॉ. अभय प्रताप वर्मा ने बुंदेलखंड के जल संकट के समाधान पर चर्चा की। हालांकि सूखाग्रस्त कहलाने वाले बुंदेलखंड के गांवों में घर-घर तक पेयजल पहुंचने के रास्ते खुल गए हैं। साथ ही गांव के लोगों को यहां बनाई गई परियोजनाओं में पंप ऑपरेटर, मोटर मैकेनिक, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मेसन के रूप में काम भी मिलने लगा है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ीं सारी योजनाएं

बुंदेलखंड को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार से बुंदेलखंड पैकेज जैसा भारी भरकम पैकेज मिला। लेकिन, उसका बंदरबांट ऐसा हुआ कि किसान पैकेज की ओर ताकते ही रह गए। बाद में पता चला कि बुंदेलखंड पैकेज की फाइलों में आग लग गई। जो बची वह दूसरी बार लगी आग में जल गई। इसी तरह नल जल योजना में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच सका है। जहां पाइप लाइन बिछाई गई, वहां पानी नहीं पहुंचा। इसके अलावा एनटीपीसी प्रोजेक्ट भी अब तक आकार नहीं ले सका है। बुंदेलखंड के छतरपुर में कुछ ऐसे गांव थे, जहां जल संकट की वजह से लोग अपनी लड़कियों की शादी नहीं करते थे। जल जीवन मिशन योजना पहुंचने के बाद हालात बदले और साफ पीने का पानी पहुंचने लगा है। ऐसे गांवों के लिए जल जीवन मिशन योजना रिश्तों की लाइफ लाइन बनी है। पथरीली जमीनों पर पीने के पानी के लिए पाइपलाइन बिछाने, गांव-गांव पानी टंकियां बनाने, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने, जल स्त्रोतों को बढ़ाने और घर-घर तक नल से जल पहुंचाने का काम तेजी से किया गया है।

कानून सख्त अपराधी मस्त

भारत में महिलाओं के विरुद्ध बढ़े अपराध, नाकाफी साबित हो रहे हैं उपाय

तीन नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद भी अपराधियों में खौफ नहीं

विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। 1 जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारत साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। जिनके आधार पर देश और प्रदेश में शासन-प्रशासन सुशासन का दम भर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में कमी नहीं आ रही है। आलम यह है कि सख्त कानून के बाद भी देश में अब भी हर दिन 86 बलात्कार हो रहे हैं।

● राजेंद्र आगाल

आधुनिकता के रथ पर सवार होकर भारत विकास की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश की सरकार भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का दम भर रही है। लेकिन विडंबना यह है कि सख्त कानून और सरकार की सख्ती के बाद भी देश में आपराधिक घटनाएं साल दर साल बढ़ रही हैं। विश्व को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले भारत में बलात्कार, हत्या, मारपीट, आगजनी, धार्मिक उन्माद आम बात हो गई है। वर्तमान सरकार ने अंग्रेजों के कानून को बदलकर 3 नए आपराधिक कानून- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारत साक्ष्य अधिनियम लागू किए हैं। लेकिन उसके बाद भी देश में आपराधिक और हिंसात्मक घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। कई राज्यों में तो अपराधियों के ठिकानों पर बुल्डोजर चलाने की परंपरा बन गई है, लेकिन उसके बाद भी अपराधियों के हौंसले बुलंद हैं। उन्हें न तो कानून का भय है, न पुलिस और न सरकार का।

महिलाओं और लड़कियों के विरूद्ध हिंसा दुनिया के सर्वाधिक प्रचलित मानवाधिकार उल्लंघनों में से एक है। इससे दुनिया का कोई भी कोना अछूता नहीं हैं। यह बेहद गंभीर मामला है क्योंकि इसके महिलाओं और लड़कियों पर गंभीर अल्पकालिक व दीर्घकालिक शारीरिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव होते हैं, जो समाज में उनकी भागीदारी को रोकते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंसा का प्रभाव केवल पीड़िता पर पड़ता है, बल्कि यह उसके परिवार और समाज को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। भारत में तो महिलाओं-बच्चियों के प्रति हिंसा-दुराचार अत्यंत चिंताजनक मुद्दा बना हुआ है। यह लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में देश की प्रगति को बाधित कर रहा है। चाहे वह हाल की कोलकाता में हुई युवा महिला चिकित्सक के साथ नृशंस दुष्कर्म एवं हत्या की घटना हो, महाराष्ट्र के बदलापुर में छोटी बच्चियों के यौन शोषण का मामला हो, या फिर देश के कोने-कोने में हर दिन महिलाओं के साथ होने वाली शारीरिक-मानसिक हिंसा की घटनाएं, महिला सुरक्षा उपायों की खामियों को उजागर करती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की वार्षिक रिपोर्ट से पुष्टि होती है कि सख्त कानून और बढ़ती जागरूकता के बावजूद महिलाओं के प्रति क्रूरता में वृद्धि दर्ज हो रही है। घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न से लेकर दहेज से संबंधित अपराधों और मानव तस्करी तक, भारत में महिलाओं को अपनी सुरक्षा एवं सम्मान को लेकर अनेक खतरों का सामना करना पड़ रहा है।

अपराध की प्रकृति काफी जटिल

देश में नए प्रकार के अपराध उभरकर सामने आ रहे हैं, और नित नए कानून बनाए जा रहे हैं, जिसके तहत अपराध नियंत्रण से संबंधित नए विभागों का निर्माण किया जा सके, ताकि डेटा को सही तरह से संग्रहित किया जा सके। इसके अलावा, देश में अपराध की प्रकृति काफी जटिल होती जा रही है। भारत को अपराध के कारणों का पता लगा पाने में अब भी काफी कमी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे-जैसे देश में शहरीकरण बढ़ेगा, वैसे-वैसे अपराध का स्वभाव एवं उसकी प्रकृति भी जटिल होती जाएगी। इसीलिए, डेटा संग्रह को समय-समय पर आगे बढ़ाना पड़ेगा एवं इसकी लगातार जांच की जानी चाहिए कि डेटा का संग्रह एवं उसका संयोजन किस गति से बढ़ रहा है। इस प्रकार की पहल से पुलिस प्रशासन एवं देश, शहरी भारत में अपराध के मोर्चे पर व्याप्त चुनौतियों का सामना कर पाने में सक्षम होंगे।

देश के बड़े रेप कांड

निर्भया गैंगरेप: 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया के साथ जो हुआ, उसने देश को झकझोर दिया। 23 वर्षीय युवती से चलती बस में न सिर्फ गैंगरेप किया गया बल्कि हद दर्जे की हैवानियत की गई थी। फिजियोथैरेपी से लोगों का दर्द दूर करने वाली इस युवती ने 13 दिन का दर्द झेला। 29 दिसंबर को सिंगापुर के अस्पताल में उसकी मौत हुई। मामले में 6 आरोपी पकड़े गए, इनमें एक नाबालिग था जो 3 माह की सजा के बाद छोड़ दिया गया। एक ने खुदकुशी कर ली और चार को फांसी की सजा हुई।

बुलंदरशहर गैंगरेप कांड: साल 2016 के अंत में देश की राजधानी दिल्ली से महज 65 किमी दूर यमुना एक्सप्रेस-वे पर कार सवार मां-बेटी को गैंगरेप का शिकार बनाया गया। यह परिवार एक रिश्तेदार की तेरहवीं में शामिल होने नोएडा जा रहा था, पत्थर मारकर बदमाशों ने कार रुकवाई और खेतों में ले जाकर मां के सामने ही 14 साल की बेटी का गैंगरेप किया। फिर मां को भी शिकार बनाया।

हैदराबाद कांड: 2019 में तेलंगाना में वेटरनिटी डॉक्टर की रेप और हत्या ने देश को हिलाकर रख दिया था। युवती की टोल प्लाजा के पास अधजली लाश मिली थी। जांच में सामने आया था कि युवती के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या की गई है। इस मामले में चार आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, इनमें मोहम्मद पाशा, चिंताकुंता, शिवा और नवीन थे, जिन्हें पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था।

कठुआ कांड: जम्मू-कश्मीर के कठुआ में 2018 में 8 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया था। इसे लेकर देश में खूब विरोध प्रदर्शन हुए थे। खासतौर से कठुआ में सांप्रदायिक तनाव के भी हालात बन गए थे। बच्ची से गैंगरेप के बाद उसके सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। बाद में सामने आया था कि यह हत्या बकरवाल समुदाय को इलाके से बाहर निकालने के लिए की गई थी।

हाथरस गैंगरेप कांड: 14 सितंबर 2020 को उप्र के हाथरस जिले में एक दलित युवती का चार युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। वारदात के दो सप्ताह बाद दिल्ली के एक अस्पताल में युवती की मौत हो गई थी। यह गैंगरेप कांड देशभर में सुर्खियां बना था। इसके बावजूद शुरुआती 10 दिन में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। युवती की मौत के बाद परिवार की सहमति के बिना ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। हालांकि बाद में पुलिस ने परिवार के इस दावे का खंडन किया था।

वर्षों बाद भी अधूरा न्याय

जानकारों का कहना है कि देश में अपराधों पर अंकुश न लगने की बड़ी वजह है दोषियों को उनके किए की सजा न मिल पाना। दिल्ली का निर्भया कांड, जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया था। 16 दिसंबर 2012 की रात करीब 9:45 बजे चलती बस में 21 वर्षीय युवती के साथ छह लोगों ने हैवानियत की हदें पार कर दीं। संसद से लेकर सड़क तक खूब हंगामा हुआ। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई, बावजूद निर्भया के परिवार को इंसाफ के लिए सात वर्ष से ज्यादा इंतजार करना पड़ा। ऐसे कई उदाहरण हैं, जब इंसाफ के इंतजार में पीढ़ियां बदल गईं। बावजूद भारत में अपराध और कोर्ट केस के बढ़ते आंकड़े डराने वाले हैं। मप्र पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, हमारे यहां अपराध के जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं वो एक बड़े झूठ के अलावा कुछ नहीं होता। वास्तविकता इससे बहुत अलग है। हकीकत ये है कि इंसाफ पाना तो बहुत दूर, आम लोगों के लिए थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराना ही एक बड़ी चुनौती है। तमाम मामलों में पुलिस केस दर्ज ही नहीं करती। इसलिए अपराध के जो आंकड़े सामने आते हैं, वह पूरी हकीकत बयां नहीं करते। वह बताते हैं कि भारत की तरह प्रत्येक देश की न्याय व्यवस्था में कुछ

पुलिस ने दिखाई आंकड़ों की बाजीगरी... अपराधों में बता दी कमी

मप्र में कानून व्यवस्था की स्थिति भी बदतर ही है। एक के बाद एक कई जघन्य वारदातें पिछले दिनों सामने आई हैं और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को भी निर्देश देने पड़े कि प्रदेश में कानून का राज है और कानून हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ कठघरे में खड़ी हुई पुलिस ने इस बार भी आंकड़ों की बाजीगरी दिखाते हुए अपराधों में कमी बताई है। यहां तक कि हत्या, डकैती, बलात्कार से लेकर तमाम गंभीर अपराधों के प्रतिशत में गिरावट के साथ 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई के आंकड़े पुलिस मुख्यालय भोपाल की ओर से जारी हुए। थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है और हालत यह है कि थाना प्रभारी अपने वरिष्ठ अफसरों की भी नहीं सुनते, क्योंकि उन्हें मंत्री से लेकर अन्य राजनीतिक संरक्षण हासिल रहता है। सूत्रों का कहना है कि इंदौर के थानों की तो नीलामी भी लगती है और कई कमाऊ थानों पर पदस्थ होने के लिए मुंहमांगी कीमत चुकाई जाती है। दूसरी तरफ अभी कन्फेक्शनरी व्यापारी का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसमें सीए को बंधक बनाने, मारपीट करने का खुलासा हुआ। उसके बाद पता चला कि उक्त कारोबारी खुद नटवरलाल है, जिसके खिलाफ अब अन्य उद्यमी शिकायत कराने आ रहे हैं, तो ऐसी ही शर्मनाक घटना जाम गेट और उसके बाद मेडिकैप्स कॉलेज के सामने घटित हुई, जिसमें एक छात्रा के भाई को छेड़खानी का विरोध करने पर बुरी तरह बीच सड़क पर पीटा गया।

खूबियां और कुछ खामियां हैं। जैसे- कैलिफोर्निया पुलिस को हाल में अधिकार दिया गया है कि चोरी के मामलों में वह तभी रिपोर्ट दर्ज करें, जब उसकी कीमत एक निश्चित सीमा से ज्यादा हो। कुछ इसका स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं कुछ इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ऐसे तो कोई अपराधी ऐसी चीजों को आसानी से निशाना बनाएगा, जो निर्धारित कीमत से कम की है।

आम लोग जानते हैं कि एफआईआर दर्ज कराना कितना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का आदेश है कि एफआईआर दर्ज करना पुलिस के लिए अनिवार्य है। रिपोर्ट दर्ज करने के लिए किसी प्राथमिक जांच की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट दर्ज न करने से कानून का राज कमजोर होता है। इसी वजह से लोग अपराध के आंकड़ों पर भरोसा नहीं करते। रिपोर्ट दर्ज न करना या संगीन अपराध को छिपाने के लिए किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा दशकों से चल रहा है। इसलिए अपराध के जो आंकड़े दिखाए जाते हैं वो काल्पनिक और हकीकत से परे होते हैं। ये एक बिना लिखी हुई, सोची-समझी नीति है, ताकि आंकड़े नियंत्रित दिखें और पुलिस या राज्य सरकार पर इसका दबाव न पड़े। अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए भाजपा शासित राज्यों में अपराधियों के अवैध ठिकानों पर बुल्डोजर चलाए जा रहे हैं। गत दिनों मप्र के छतरपुर में थाने को घेरने और पथराव करने के आरोप में एक कांग्रेस नेता के मकान पर बुल्डोजर चला दिया गया। इसको लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने साफ-साफ शब्दों में कह दिया कि एक व्यक्ति की गलती का खामियाजा पूरे परिवार को देना उचित नहीं है। इसलिए सरकारें बुल्डोजर चलाना बंद करे।

आंकड़ों से न हो पुलिसिंग का आंकलन

पुलिस के काम का आंकलन अपराध के आंकड़ों की जगह, इस आधार पर होना चाहिए कि लोग कितना सुरक्षित महसूस कर रहे। पुलिस इसलिए भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करती, क्योंकि इसकी जांच का भार और पेडिंग केस की संख्या बढ़ने पर उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है। किसी भी राज्य में पांच-गुना अपराध का आंकड़ा बढ़ने से वहां राजनीतिक भूचाल आ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि पुलिसिंग के आंकलन का पैमाना बदला जाए। अन्यथा कानून का राज स्थापित नहीं हो सकता। महाराष्ट्र पुलिस ने वर्ष 2013 में आम जनता के बीच पुलिसिंग के बारे में सर्वे कराने का एक प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा था, जिसे महत्व नहीं दिया गया।

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के स्कूल ऑफ लॉ, राइट्स एंड कॉन्स्टीट्यूशनल गवर्नेंस में प्रोफेसर व डीन डॉ. अरविंद तिवारी देश की निचली अदालतों में लंबित केस को गंभीर समस्या मानते हैं। वह कहते हैं कि इनमें काफी संख्या छोटे-छोटे आम नागरिक मुद्दों से जुड़े केस की है, जैसे कूड़ा न उठाना, नालियां ओवरफ्लो होना आदि। इसके अलावा भू-रिकॉर्ड दुरुस्त न होने के कारण संपत्ति के विवाद भी अदालों में बहुत ज्यादा हैं। नागरिक मुद्दों और संपत्ति विवाद से जुड़े इन छोटे-छोटे मामलों में तत्काल समाधान न होने पर ये बड़े अपराध की शक्ल ले लेते हैं। ऐसे मामले बहुत से झूठे आरोपों व तथ्यों के साथ अदालत पहुंचते हैं और पर्याप्त साक्ष्य न होने की वजह से लंबे समय तक पेंडिंग रहते हैं। ज्यादातर राज्यों में पुलिस भारी दबाव में और बहुत लंबी ड्यूटी करती है। उन्हें मौजूद चुनौतियों के लिहाज से बेहतर प्रशिक्षण मिले। पुलिस कई बार वास्तविक मामलों की जगह, दबाव में गैर जरूरी या अनुचित मामले दर्ज कर लेती है। पुलिस पर राजनीतिक नियंत्रण, उसकी स्वतंत्रता छीनता है। इससे पुलिसिंग प्रभावित होती है। जानकार कहते हैं कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था पीड़ित केंद्रित होनी चाहिए, मतलब जो पीड़ित के हितों को ध्यान में रखे। अभी केस दर्ज होने के बाद इंसाफ की प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल है। ट्रायल पूरा होने में ही कई वर्ष लग जाते हैं, ट्रायल के बाद अदालत का फैसला आने में कई और वर्ष लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में न्यायधीशों की संख्या बहुत कम है, जबकि प्रत्येक स्तर पर जजों के कई पद खाली पड़े हैं। लंबित कोर्ट केस की संख्या कम कर व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है।

भारत की विशाल आबादी भी जिम्मेदार

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता फ्लाइड ग्रेसियस कहते हैं कि पिछले कुछ दशक में न्याय प्रणाली पर काम का बोझ बहुत बढ़ गया है। इसके लिए हमारी विशाल आबादी भी जिम्मेदारी है। शिकायतकर्ता को अदालत जाने से पहले मामले की गंभीरता पर विचार करना चाहिए और छोटे-छोटे मामलों में कोर्ट केस करने से बचना चाहिए। जिन मामलों में संभव हो, आपसी समझौतों से कोर्ट केस कम किए जा सकते हैं। दो दशक से क्रिमिनल केस लड़ रहे अधिवक्ता दिनेश तिवारी का कहना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय न्यायिक सिस्टम ध्वस्त होने की कगार पर है। आलम ये है कि एफआईआर दर्ज होने, उसकी जांच होने और फिर उसके कोर्ट ट्रायल तक सिस्टम में शायद ही कहीं कोई उम्मीद की किरण बाकी है। ज्यादातर जांच, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, जिससे न्यायिक व्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इस फेल सिस्टम ने आम लोगों को ही पीड़ित बना दिया है। इस पर तत्काल ध्यान देने और जरूरी कदम उठाने की जरूरत है।

देश और प्रदेश में शासन-प्रशासन सुशासन का दम भर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में कमी नहीं आ रही है। आलम यह है कि सख्त कानून के बाद भी देश में अब भी हर दिन 86 बलात्कार हो रहे हैं। बलात्कार के मामले में राजस्थान पहले, उप्र दूसरे और मप्र तीसरे स्थान पर है। केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर घंटे 3 महिलाएं रेप का शिकार होती हैं, यानी हर 20 मिनट में 1 महिला को शिकार बनाया जाता है। देश में रेप के मामलों में 96 प्रतिशत से ज्यादा आरोपी महिला को जानने वाले होते हैं। रेप के मामलों में 100 में से 27 आरोपियों को ही सजा होती है, बाकी बरी हो जाते हैं। ये तीन आंकड़े बताते हैं कि सख्त कानून होने के बावजूद हमारे देश में रेप के मामलों में न तो कमी आ रही है और न ही सजा की दर बढ़ रही है।

केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि भारत में सालभर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4 लाख से ज्यादा अपराध दर्ज किए जाते हैं। इन अपराधों में सिर्फ रेप ही नहीं, बल्कि छेड़छाड़, दहेज हत्या, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग, एसिड अटैक जैसे अपराध भी शामिल हैं।

16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली की सड़क पर चलती बस में युवती के साथ गैंगरेप किया गया था। इस दौरान दरिंदों ने सारी हदें पार कर दी थीं। बाद में उस युवती की मौत हो गई थी। इस कांड ने देश को झकझोर कर रख दिया था। निर्भया कांड के बाद कानून को बहुत सख्त कर दिया गया था। रेप की परिभाषा भी बदल दी थी, ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी लाई जा सके। पहले जबरदस्ती या असहमति से बनाए गए संबंधों को ही रेप के दायरे में लाया जाता था। लेकिन 2013 में कानून में संशोधन कर इसका दायरा बढ़ाया गया।

हाल-फिलहाल में रेप के कुछ मामलों ने देश को हिलाकर रख दिया है। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की रेप और उसके बाद हत्या का मामला चर्चा में बना है। कोलकाता के इस रेप कांड ने 2012 के निर्भया कांड की यादें ताजा कर दीं। इसके खिलाफ सिर्फ कोलकाता ही नहीं, बल्कि देशभर के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसे सख्त से सख्त सजा देने की मांग हो रही है। लेकिन विडंबना यह है कि सख्त कानून के बाद भी देश में बलात्कार के मामले कम नहीं हो रहे हैं।

सख्त कानून... फिर भी रेप बढ़े

साल दर साल बढ़ रहे मामले

- 2009-21,397
- 2010-22,172
- 2011-24,206
- 2012-24,923
- 2013-33,707
- 2014-36,735
- 2015-34,651
- 2016-38,947
- 2017-32,559
- 2018-33,356
- 2019-32,032
- 2020-28,046
- 2021-31,677
- 2022-31,516

2022 में रेप के 31 हजार से ज्यादा मामले दर्ज

- राजस्थान - 5,399
- उप्र - 3,690
- मप्र - 3,029
- महाराष्ट्र - 2,904
- हरियाणा - 1,787
- ओडिशा - 1,464
- झारखंड - 1,298
- छत्तीसगढ़ - 1,246
- दिल्ली - 1,212
- असम - 1,113

इतना ही नहीं, जुवेनाइल कानून में संशोधन किया गया था। इसके बाद अगर कोई 16 साल और 18 साल से कम उम्र का कोई किशोर जघन्य अपराध करता है तो उसके साथ वयस्क की तरह ही बर्ताव किया जाएगा। ये संशोधन इसलिए हुआ था, क्योंकि निर्भया के छह दोषियों में से एक नाबालिग था और तीन साल में ही रिहा हो गया था। इसके अलावा, रेप के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान भी किया गया था। इसके बाद अगर रेप के बाद पीड़िता की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा जैसी हालात में पहुंच जाती है, तो दोषी को फांसी की सजा भी दी जा सकती है। हालांकि, इन सबके बावजूद सुधार नहीं हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि 2012 से पहले हर साल रेप के औसतन 25 हजार मामले दर्ज किए जाते थे। लेकिन इसके बाद ये आंकड़ा 30 हजार के ऊपर पहुंच गया। 2013 में ही 33 हजार से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। 2016 में तो आंकड़ा 39 हजार के करीब पहुंच गया था।

महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े डराने वाले हैं। 2012 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 2.44 लाख मामले दर्ज किए गए थे। जबकि, 2022 में 4.45 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए। यानी, हर दिन 1200 से ज्यादा मामले। वहीं, रेप के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। एनसीआरपी की रिपोर्ट के मुताबिक, 2012 में रेप के 24 हजार 923 मामले दर्ज हुए थे। यानी, हर दिन औसतन 68 मामले। जबकि, 2022 में 31 हजार 516 मामले दर्ज किए गए थे। इस हिसाब से हर दिन औसतन 86 मामले दर्ज किए गए। यानी, हर घंटे 3 और हर 20 मिनट में 1 महिला रेप की शिकार हुई। अगर राज्यों की बात की जाए तो रेप के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में सामने आते हैं। 2022 में राजस्थान में रेप के 5,399 मामले दर्ज किए गए थे। 3,690 मामलों के साथ उप्र दूसरे नंबर पर था। बलात्कार के ज्यादा मामलों में जो आरोपी होता है, वो पीड़िता की जान-पहचान वाला

ही होता है। आंकड़े बताते हैं कि रेप के 96 फीसदी से ज्यादा मामलों में पहचान वाला ही आरोपी निकलता है।

2022 में रेप के 31 हजार 516 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 30 हजार 514 मामलों में आरोपी पीड़िता की पहचान वाला ही था। इनमें से 2,324 आरोपी तो ऐसे थे जो पीड़िता के ही परिवार के सदस्य थे। जबकि, 14 हजार 582 मामलों में ऑनलाइन फ्रेंड, लिव-इन पार्टनर या शादी का झांसा देने वाला आरोपी था। वहीं, 13 हजार 548 मामले ऐसे थे, जिनमें आरोपी कोई पारिवारिक दोस्त, पड़ोसी या जान-पहचान वाला ही था।

एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, रेप के मामलों में सजा मिलने की दर 27 से 28 फीसदी ही है। यानी, रेप के 100 में से 27 मामलों में ही आरोपी दोषी साबित हो पाता है, बाकी मामलों में उसे बरी कर दिया जाता है। रिपोर्ट बताती है कि 2022 के आखिर तक देशभर की अदालतों में रेप के लगभग दो लाख मामले लंबित थे। 2022 में इनमें से साढ़े 18 हजार मामलों में ही ट्रायल पूरा हुआ। जिन मामलों में ट्रायल पूरा हुआ, उनमें से करीब 5 हजार मामलों में ही दोषी को सजा दी गई। जबकि, 12 हजार से ज्यादा मामलों में आरोपी को बरी कर दिया गया। भारत से इतर, ब्रिटेन में रेप के मामलों में सजा मिलने की दर 60 फीसदी से ज्यादा है। कनाडा में भी रेप के मामलों में कन्विक्शन रेट 40 फीसदी से ज्यादा है। जानकारों का कहना है कि भारत में जज रेप के आरोपियों को सजा देने में बचते हैं। उनका मानना है कि अगर सबूतों की कमी है तो वो आरोपी को बरी कर देते हैं, जबकि उन्हें इसके लिए कम से कम कुछ सजा तो जरूर देनी चाहिए ताकि उसे **दोषी** ठहराया जा सके। इतना ही नहीं, रेप के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान होने के बावजूद 24 साल में पांच दुष्कर्मियों को ही फांसी की सजा मिली है। 2004 में धनंजय चटर्जी को 1990 के बलात्कार के मामले में फांसी दी गई थी। जबकि, मार्च 2020 में निर्भया के चार दोषियों- मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी।

दो महीने पहले नए आपराधिक कानूनों को लागू किया गया है। इसके बाद आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) ने ले ली है। आईपीसी में धारा 375 में रेप को परिभाषित किया गया है, जबकि 376 में इसके लिए सजा का प्रावधान है। जबकि, भारतीय न्याय संहिता में धारा 63 में रेप की परिभाषा दी गई है और 64 से 70 में सजा का प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 64 में भी यही सजा रखी गई है। बीएनएस में नाबालिगों से दुष्कर्म में सख्त सजा कर दी गई है। 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इस सजा को आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा होने पर दोषी की सारी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। बीएनएस की धारा 65 में ही प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल की जेल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। इसमें भी उम्रकैद की सजा तब तक रहेगी, जब तक दोषी जिंदा रहेगा। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान भी है। इसके अलावा जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।

गैंगरेप के मामलों में दोषी पाए जाने पर 20 साल से लेकर **उम्रकैद** और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 70(2) के तहत, नाबालिग के साथ गैंगरेप का दोषी पाए जाने पर कम से कम उम्रकैद की सजा तो होगी ही, साथ ही मौत की सजा भी हो सकती है। ऐसे मामलों में जुर्माने का भी प्रावधान है। जबकि, आईपीसी में 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ गैंगरेप का दोषी पाए जाने पर ही मौत की सजा का प्रावधान था। बीएनएस की धारा 66 के तहत, अगर रेप के मामले में महिला की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा जैसी स्थिति में पहुंच जाती है तो दोषी को कम से कम 20 साल की सजा होगी। इस सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा में भी बदला जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता में एक नई धारा 69 जोड़ी गई है। इसमें शादी, रोजगार या प्रमोशन का झूठा वादा कर यदि कोई व्यक्ति महिला के साथ यौन संबंध बनाता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसमें पहचान छिपाकर शादी करने पर भी 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाबालिगों के लिए पॉक्सो एक्ट

2012 के निर्भया कांड के बाद ही यौन हिंसा के नाबालिग पीड़ितों के लिए भी कानून लाया गया था। ये कानून था- पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। इस कानून को 2012 में लाया गया था। ये बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण को अपराध बनाता है। ये कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों, दोनों पर लागू होता है। इसका मकसद बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लीलता से जुड़े अपराधों से बचाना है। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चा माना गया है और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। पॉक्सो कानून में पहले मौत की सजा नहीं थी, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन कर मौत की सजा का भी प्रावधान कर दिया। इस कानून के तहत उम्रकैद की सजा मिली है तो दोषी को जीवन जेल में ही बिताना होगा। इसका मतलब हुआ कि दोषी जेल से जिंदा बाहर नहीं आ सकता। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2021 में पॉक्सो एक्ट के तहत देशभर में करीब 54 हजार मामले दर्ज किए गए थे। जबकि, इससे पहले 2020 में 47 हजार मामले दर्ज हुए थे। 2017 से 2021 के बीच 5 साल में पॉक्सो एक्ट के तहत 2.20 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि, पॉक्सो एक्ट में कन्विक्शन रेट काफी कम है। आंकड़े बताते हैं कि 5 साल में 61,117 आरोपियों का ट्रायल कम्प्लीट हुआ है, जिनमें से 21,070 यानी करीब 35 प्रतिशत को ही सजा मिली है। बाकी 37,383 को बरी कर दिया गया।

दुनिया की भूख मिटाने को तैयार भारत

भारत में 92 हजार करोड़ का भोजन रोज होता है बर्बाद

प्राचीन भारतीय ज्ञान के अनुसार, भोजन को अमृत के रूप में माना जाता है और भोजन की बर्बादी को पाप माना जाता है। यह विचार आगे सिखाता है कि हमें हमेशा उससे थोड़ा कम खाना चाहिए, जितने से पेट भरता है। दूसरे शब्दों में हमें अपनी भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए। अनुपात यह है कि अपने पेट को पचास फीसद ठोस भोजन से, पच्चीस फीसद तरल पदार्थ से भरकर और बाकी पच्चीस फीसद को खाली रखना चाहिए। अगर भोजन की बर्बादी नामक एक देश होता, तो यह ग्रह पर तीसरा सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक होता! अगर हम सभी खाने योग्य भोजन को बर्बाद करना बंद कर दें, तो यह ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की दृष्टि से चार में से एक कार को सड़क से हटाने के बराबर होगा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारत में औसत व्यक्ति प्रतिदिन 137 ग्राम भोजन बर्बाद करता है। यानी 0.96 किलोग्राम प्रति सप्ताह या पचास किलोग्राम प्रति वर्ष। भारत में 40 फीसदी भोजन बर्बाद हो जाता है जो एक वर्ष में 92,000 करोड़ रुपए के बराबर है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हुए कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीएई) को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत खाद्यान्न अधिशेष वाला देश बन गया है और वह वैश्विक खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए समाधान उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि 65 वर्ष पूर्व जब यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ था, उस समय भारत की खाद्य सुरक्षा विश्व के लिए चिंता का विषय थी, लेकिन अब वैश्विक खाद्य संकट की चुनौतियों के बीच भारत दुनिया के 150 से अधिक देशों को खाद्य पदार्थों के निर्यातक देश के रूप में रेखांकित हो रहा है। साथ ही कोरोनाकाल से लगातार 80 करोड़ से अधिक कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त में अनाज देने की भारत की पहल दुनियाभर में रेखांकित हो रही है। वर्ष 2023 में भारत ने करीब 50 अरब डॉलर मूल्य का कृषि निर्यात किया है और दुनिया का आठवां बड़ा कृषि निर्यातक देश बन गया है।

इन दिनों वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर प्रकाशित हो रहीं विभिन्न अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में भारत की नई अहमियत पता चल रही है। इस समय जब रूस-यूक्रेन युद्ध, इस्त्राइल-हमास युद्ध और अन्य भू-राजनीतिक कारणों से वैश्विक खाद्य संकट गहराता जा रहा है, तब दुनिया के अनेक देशों को खाद्य संकट से निपटने और उनकी खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर भारत एक मददगार देश बना हुआ है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से कहा कि कृषि व्यवस्था को बदलना समय की मांग है। देश के किसान भारत को विश्व की ऑर्गेनिक फूड बास्केट बना सकते हैं और विश्व के देशों के लिए भारत मददगार हो सकता है। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष सहित सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न वैश्विक संगठनों द्वारा भारत की खाद्य सुरक्षा की सराहना की जा रही है।

इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि देश ने कृषि उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। खासतौर से पिछले 10 वर्षों में कृषि विकास के अभूतपूर्व प्रयासों से अब भारत दुनिया के खाद्य कटोरे के रूप में पहचान बना रहा है। कृषि भारत की आर्थिक नीतियों के केंद्र में है। भारतीय कृषि में 90 प्रतिशत किसानों के पास बहुत कम जमीन है और ये छोटे किसान भारत की खाद्य सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत हैं। कृषि क्षेत्र के सतत् विकास के लिए फसलों की 1,900 नई जलवायु-अनुकूल किस्में उपलब्ध कराई गई हैं। भारत रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। भारत ने मोटे अनाज को श्रीअन्न का नाम देकर इसे एक लाभदायक समाधान के रूप में प्रस्तुत किया है। भारत कृषि क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहा है।

वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में घोषित 9 उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र भी शामिल है। बजट में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नए बजट में सरकार उपज के संग्रहण, भंडारण और विपणन सहित सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए किसान-उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा संबंधी प्रावधान शामिल किए गए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के लिए प्रमुख फसलों का, जो तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, उसके मुताबिक कुल खाद्यान्न उत्पादन 3288.52 लाख टन अनुमानित है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भारत दुनिया में दूध, दालों और मसालों का नंबर एक उत्पादक है। इसके अलावा, देश खाद्यान्न, फल, सब्जियां, कपास, चीनी और चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। ऐसे में जब देश में खाद्यान्न उत्पादन ऊंचाई बना रहा है, तब खाद्यान्न भंडारण की अधिक क्षमता भी जरूरी है। अभी 12 से 14 फीसदी तक अन्न बर्बाद हो जाता है। देश में भंडारण क्षमता फिलहाल 1,450 लाख टन की है, उसे 2,150 लाख टन किए जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि बढ़ती हुई वैश्विक खाद्यान्न सुरक्षा जरूरतों के बीच देश में सरकार के द्वारा अधिक खाद्यान्न उत्पादन कृषि प्रणाली मॉडल पर केंद्रित जलवायु स्मार्ट दृष्टिकोण, हरित और जलवायु अनुकूल कृषि के लिए वित्तपोषण, छोटे और सीमांत किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कृषि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि सरकार के द्वारा कृषि प्रौद्योगिकी साझा करने के लिए अधिक निवेश, समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखलाएं, कृषि-खाद्य क्षेत्र को बदलने के लिए नई-उभरती डिजिटल तकनीकों की, भूमि के डिजिटलीकरण के लिए खेती में ड्रोन को बढ़ावा, कृषि अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों के बीच मजबूत साझेदारी और टिकाऊ कृषि-खाद्य प्रणालियों की डगर पर आगे बढ़ने की कारगर रणनीति अपनाई जाएगी। खाद्य नुकसान को शून्य पर नहीं लाया जा सकता- विकसित राष्ट्र भी इसका अनुभव करते हैं। लेकिन इससे अभिन्न कुछ समस्याओं पर विचार करना जरूरी है। पिछले साल चौदह अक्टूबर को वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया गया। उसमें 121 देशों की सूची में भारत 107वें स्थान पर था।

● इंद्र कुमार

आजादी के पहले जब सांप्रदायिक तौर पर निर्वाचक मंडल और प्रतिनिधित्व तय करने से अंग्रेजों का पेट नहीं भरा तो उन्होंने जातिवाद और ऊंच-नीच की भावना को खूब भड़काया। साम्राज्य की खातिर पहले उन्होंने अलग-अलग, असमान लोगों को ठोक-पीटकर एक किया और बाद में वे उन्हीं टुकड़ों को बांटने में लग गए। उन्होंने ध्येय बनाया कि केवल अंश, केवल टुकड़े ही वास्तविक हैं। समग्र, संपूर्ण तो महज गढ़ी हुई कल्पना भर है।

संघ के बिना कुछ नहीं...

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की केरल के पलक्कड़ में आयोजित 3 दिवसीय बैठक के दौरान कई ऐसे मुद्दे रहे जिन पर विस्तार से चर्चा हुई। देश में जाति जनगणना कराना, डीलिमिटेशन और महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण, केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक में इन तीन बड़े मुद्दों पर बात हुई। इनमें भी जनगणना और महिला आरक्षण पर ज्यादा फोकस रहा। आरएसएस का मानना है कि 2029 तक अगर 33 प्रतिशत महिलाएं संसद में आ जाती हैं, तो देश का इतिहास बदल जाएगा।

जाति जनगणना पर आरएसएस के स्टैंड से भाजपा का धर्मसंकट खत्म हो गया है, क्योंकि अब तक पार्टी इस मुद्दे का न खुलकर विरोध कर पा रही थी और न ही समर्थन। क्रीमीलेयर में बदलाव पर आरएसएस का मानना है कि आरक्षण से जुड़ी जातियों को भरोसे में लेकर और उनकी सहमति के बगैर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। इसके अलावा आरएसएस ने कुटुंब प्रबोधन के जरिए 30 करोड़ हिंदू परिवारों तक पहुंचने का टारगेट रखा है। इस बैठक में आरएसएस के 32 संगठनों के 300 पदाधिकारी शामिल हुए। भाजपा की ओर से अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष इस बैठक में शामिल हुए। बैठक से जो संदेश निकलकर आया है वह यही है कि संघ के बिना भाजपा कुछ नहीं कर सकती। बैठक में महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण देने को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ कि सरकार जल्द से जल्द महिला आरक्षण विधेयक को लागू करे। संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी की मानें तो लोकसभा चुनाव से पहले हर लोकसभा क्षेत्र की 1 हजार महिलाओं के साथ संघ ने संवाद किया था। तब भी महिलाओं ने आरक्षण लागू करवाने की मांग की थी। संघ अपने संगठन कुटुंब प्रबोधन के जरिए 30 करोड़ परिवारों तक पहुंचेगा। चुनाव में भाजपा को इसका फायदा कैसे मिल सकता है इस पर भी गहनता से बातचीत हुई। संघ मानता है कि परिवारों में एकता और राष्ट्रीयता की भावना से ही देश मजबूत बन सकता है। व्यक्ति को सामाजिक इकाई मानना भ्रांति है। संघ परिवारों के बीच बेहतर तालमेल और सहयोग पर काम करता है। संघ हिंदू धर्म की सभी जातियों तक पैठ बढ़ाना चाहता है। जो भी जाति हिंदू धर्म को मानती है उन तक कैसे पहुंचा जाए, इस पर भी बैठक में चर्चा हुई। इसके लिए संघ समरसता मंच शुरू करेगा। संघ अगले वर्ष अपनी स्थापना का 100वां साल पूरा कर रहा है।

लोकसभा चुनाव में चौथे राउंड की वोटिंग के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि शुरुआत में हम कम सक्षम थे। तब हमें संघ की जरूरत पड़ती थी। अब हम सक्षम हैं। आज भाजपा खुद को चलाती है। सूत्रों की मानें तो

हिंदू धर्म मानने वाली सभी जातियों में पैठ बनाना

बैठक में शामिल पदाधिकारी बताते हैं कि 1972 में ठाणे में चिंतन बैठक हुई थी। तब संघ प्रमुख माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर ने कहा था कि आरएसएस अखिल भारतीय हो चुका है। हमें हिंदू धर्म को मानने वाली सभी जातियों में पैठ बनानी होगी। उनका मकसद था ऐसे लोगों को आरएसएस की छाया में लाना, जो किसी न किसी तरीके से हिंदू धर्म को मानते हैं। ये कोशिश आज भी अधूरी है। कैसे आरएसएस को सभी जातियों का प्रतिनिधि बनाया जाए, इस पर भी बैठक में चर्चा हुई है। इसके लिए आरएसएस समरसता मंच शुरू करेगा। संघ नेता दिलीप देवधर का कहना है कि 2029 तक आरएसएस इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करेगा। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी। संगठन के 100 साल पूरे होने वाले हैं। आरएसएस समय-समय पर अपने काम की समीक्षा करता है, विस्तार की योजनाओं पर काम करता है। शताब्दी वर्ष को ध्यान में रखते हुए इसमें तेजी लाने पर बात की गई। देवधर कहते हैं कि राहुल गांधी आज जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। आरएसएस हमेशा से इसका पक्षधर रहा है। हमारे पास पहले से जातिगत आंकड़े मौजूद हैं। हमें बस सरकार के आधिकारिक आंकड़े का इंतजार है। जातिगत जनगणना के बाद आरएसएस के लोग हिंदुओं की सभी जातियों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा कि सामाजिक समरसता की जड़ें मजबूत करने के लिए सभी स्वयंसेवकों को निकलना होगा। लोगों तक मैसेज पहुंचाना होगा कि मंदिर, तालाब जैसी जगहों पर सभी जातियों का समान अधिकार है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से विपक्ष ने भाजपा और आरएसएस को आरक्षण और संविधान विरोधी बताने के लिए अभियान चलाया था, उससे भाजपा का दलितों और पिछड़ों में आधार घटा है। इस लिहाज से आरएसएस ने अपना रुख साफ किया है।

बैठक के इतर जेपी नड्डा और संघ प्रमुख के बीच बातचीत हुई। यानी आगे इस प्रकार की बयानबाजी न हो ये भी तय हुआ। भाजपा और संघ मिलकर काम करेंगे। 2001 में यह तय हुआ कि सरकार पार्टी की होगी और संगठन पर संघ का नियंत्रण होगा। संघ सूत्रों की मानें तो भाजपा और आरएसएस में तालमेल बिगड़ने का नतीजा लोकसभा चुनाव में दिख चुका है। इसी नुकसान से बचने के लिए समय-समय पर सुझाव देने का फैसला किया गया है।

केरल के पलक्कड़ में तीन दिनों तक संघ और उसके संगठनों के 300 से ज्यादा पदाधिकारियों ने समन्वय बैठक की। बैठक में विचार परिवार के सभी संगठनों के लिए भविष्य की रणनीति बनाई गई। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। संघ भाजपा के लिए केरल में राह बनाने में जुटा हुआ है। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस से प्रेरित 32 संगठनों के प्रतिनिधियों ने तीन दिवसीय समन्वय बैठक में हिस्सा लिया। संघ की इस बैठक में कई सारे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद संघ समन्वय बैठक के लिए केरल को चुना गया था उसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या केरल में सामाजिक और राजनीतिक रूप से भाजपा तीसरे विकल्प के तौर पर खुद को तैयार कर चुकी है। पलक्कड़ शहर से थोड़ी दूर बसे गांवों में आज भी जमीन पर आरएसएस के पताके सालों से लहरा रहे हैं। वहीं, भाजपा शिशु से किशोर अवस्था में पहुंच रही है। गांव में या तो संघ के पताके और बैनर पोस्टर पटे मिलेंगे या डीएफआई या अन्य वामपंथी दलों के बैनर पोस्टर ज्यादा दिखेंगे। पलक्कड़ से 16 किलोमीटर दूर रामासेरी गांव है। गांव का रंग रूप आप देखें तो पूरा भगवामय दिखेगा या फिर वामदलों की छाप दिखेगी। हां, गांव के कुछ मोड़ पर संघ के झंडे से सटे भाजपा के झंडे लहराते हुए दिखेंगे। साफ दिखेगा कि कैसे संघ के पताके भाजपा के झंडे को सहारा दे रहे हैं। पलक्कड़ जैसी जगहों पर आज भी भाजपा को संघ की उंगली पकड़कर चलाना पड़ता है। पलक्कड़ म्युनिसिपैलिटी के काउंसलर अच्चूतानंदन एसपी ने कहा कि यहां हम भाजपा के काउंसलर हैं। हम संघ के वजह से यहां जीते हैं। अगर संघ का समर्थन नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते।

संघ की यह बैठक केरल के पलक्कड़ जिले में हुई। पलक्कड़ वही जिला है जहां भाजपा ने 2022 में म्युनिसिपल चुनाव जीता, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि पूरे केरल में एकमात्र जगह भाजपा किसी नगर पालिका में सत्ता में आई। 52 काउंसलर वाले पलक्कड़ म्युनिसिपैलिटी में भाजपा के 28 काउंसलर जीते थे। यहां पहली बार यूडीएफ और एलडीएफ को भाजपा ने पटखनी दी। पलक्कड़ म्युनिसिपैलिटी की चेयरमैन प्रमिला शशिधरण ने कहा कि हमारा पलक्कड़ पहली म्युनिसिपैलिटी है जहां भाजपा ने पहली बार सरकार बनाई।

पलक्कड़ म्युनिसिपैलिटी में भाजपा की सत्ता में आने की कई सारी वजह रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिस तरह से संघ का काम केरल के गांव में देखने को मिला, ऐसा लगा कि सेवा के भाव के जरिए संघ सालों से सामाजिक परिवर्तन की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। पलक्कड़ के सूरदास नगर में आरएसएस द्वारा बच्चों का अनाथालय चलाया जा रहा है। थोड़ी ही दूर पर एक दूसरे प्रकल्प के तौर पर ब्लाइंड और बहरे लोगों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाए जा रहे हैं, जिसमें किसी भी सरकार से कोई मदद नहीं ली जा रही। स्थानीय आम लोगों की मदद से इन सेंटर्स को चलाया जा रहा है।

साफ है संघ सेवा कार्यों के जरिए प्रदेश के लोगों के मन पर सालों से अपनी छाप छोड़ रहा है। वहीं, संघ के कामों से इतर भाजपा ने इस बार केरल में अपना सबसे बेहतर वोट प्रतिशत हासिल किया है जिसकी बड़ी वजह केंद्र सरकार के लाभार्थी हैं। 2.33 लाख किसानों को केरल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला। 2 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बने। 3.5 लाख उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं। 28 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला। वहीं 1 लाख लोगों को हर घर नल योजना से पानी का कनेक्शन मिला है। 1020 किलोमीटर के नेशनल हाईवे की सौगात मिली है। इसी तरह से ढेरों योजनाओं का लाभ केरल में केंद्र सरकार के द्वारा आम लोगों को दिया गया है। वहीं, संघ भी 5 हजार से ज्यादा शाखाओं के साथ गांव-गांव में पहुंच गया, जो कि बड़े स्तर पर सामाजिक परिवर्तन के कार्य कर रहा है। ऐसे में ये साफ है कि भाजपा भले ही अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हो, लेकिन अब भी देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां संघ उसके लिए लगातार जमीन तैयार करने में जुटा है।

जातीय जनगणना पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक संयमित और संतुलित बयान दिया है। संघ का कहना है कि समाज के कल्याण के लिए सरकार को आंकड़ों की जरूरत होती है और जातीय जनगणना इसका जरिया हो सकती है। लेकिन इसका चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सीधा-सा मतलब है कि संघ की लीडरशिप, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जातीय जनगणना की मांग से तो सहमत है लेकिन राहुल के तरीके से असहमत है।

● **विपिन कंधारी**

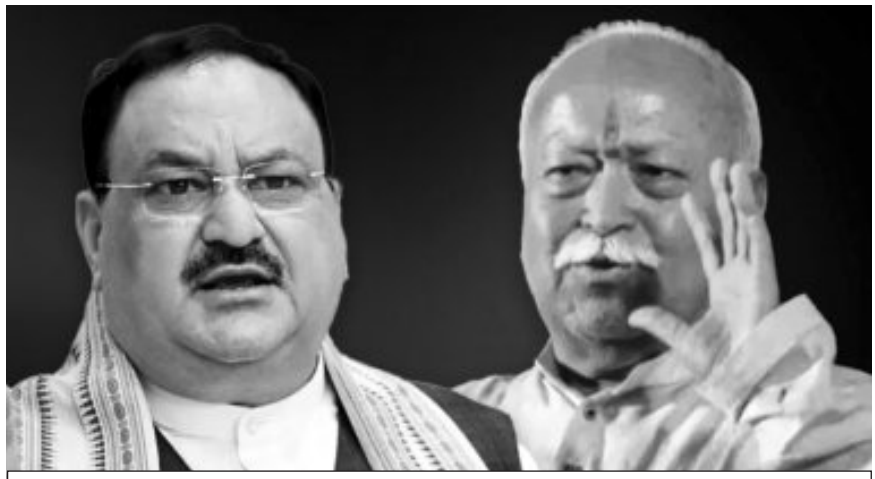

आरएसएस की छाया से बाहर नहीं होगी भाजपा

इसी साल 21 मई को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा था, शुरुआत में हम कम सक्षम थे। तब हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। अब हम सक्षम हैं। आज भाजपा खुद अपने आप को चलाती है। ये बयान लोकसभा चुनाव में चौथे राउंड की वोटिंग के बाद आया था। बैठक में इस पर भी बात हुई कि आगे किसी तरह का कन्फ्यूजन न हो। संघ के नेता दिलीप देवधर का कहना है कि अब फिर से आरएसएस केंद्रित भाजपा बन चुकी है। तीन दिन की बातचीत के बाद आरएसएस-भाजपा हार्मनी फिर से बन गई है। बैठक में शामिल एक सूत्र कहते हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच मीटिंग हुई है। एक हफ्ते पहले तक भाजपा अध्यक्ष को बैठक का न्यौता नहीं मिला था। चर्चा होने लगी कि शायद उन्हें नहीं बुलाया जाए। मोहन भागवत और जेपी नड्डा के बीच पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा की बात सामने आ रही है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। आरएसएस और भाजपा के रिश्तों पर सुनील आंबेकर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि दोनों का टारगेट एक ही है। आरएसएस के लिए देश सबसे पहले है। हर स्वयंसेवक मानता है कि राष्ट्र सनातन और शाश्वत है। इसलिए हम सभी देश की सेवा के लिए समर्पित हैं।

हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक महीने से भी कम का वक्त बचा है। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होना है। 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। सभी दल अपने-अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं। कांग्रेस 89 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है, जबकि एक सीट उसने सीपीआईएम को दी है। टिकट बंटवारे में पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग का खास ख्याल रखा है। कांग्रेस ने साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को कांटे की टक्कर दी थी। कांग्रेस ने 90 में से 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 27 विधानसभा सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। अब इन सीटों पर पार्टी ने जीत के लिए खास रणनीति बनाई है।

बिछ गई सियासी बिसात

हरियाणा की सियासत में 10 साल से सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी जीत की हैट्रिक लगाने की जुगत में है तो वहीं कांग्रेस अपनी वापसी के लिए बेताब है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही चुनावी जंग में अपने-अपने सिपाहसलार उतार दिए हैं।

हरियाणा में फर्श से अर्श पर पहुंची भाजपा ने 2019 में भले ही 40 सीटें जीतकर दूसरी बार सरकार बनाने में सफल रही हो, लेकिन 3 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। इसी तरह से कांग्रेस ने भाजपा को पिछले चुनाव में कांटे की टक्कर दी थी, लेकिन 27 सीट पर पार्टी कैंडिडेट अपनी जमानत नहीं बचा सके थे।

भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस बार पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी हैं। ऐसे में 2019 में जमानत जब्त हुई विधानसभा सीटों को जीतने के लिए खास रणनीति बनाई गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार दोनों ही पार्टियों ने इन सभी सीटों पर पिछले चुनाव में शिकस्त खाए हुए उम्मीदवारों पर दांव लगाने के बजाय नए चेहरों को उतारा है। ऐसे में अब देखना है कि खास रणनीति के साथ उतरी कांग्रेस और भाजपा अपनी-अपनी जमानत जब्त सीटों पर जीत का स्वाद चखने में कामयाब होंगी?

हरियाणा के पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के 3 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। 2019 में पुंडरी, रानिया और पृथला विधानसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। पुंडरी विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी वेदपाल एडवोकेट को 20,990 (15.33 फीसदी) वोट मिले थे। रानिया सीट पर भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र कम्बोज को 20,709 (14.42 फीसदी) वोट मिले थे और पृथला सीट पर पार्टी कैंडिडेट सोहन पाल के खाते में 21,322 (14.50 फीसदी) वोट आए थे। इस तरह भाजपा के ये तीनों उम्मीदवार जमानत नहीं बचा सके।

भाजपा ने इस बार पुंडरी, रानिया और पृथला विधानसभा सीट पर जमानत जब्त कराने वाले उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया। भाजपा ने पुंडरी सीट पर वेदपाल की जगह सतपाल जाम्बा को उतारा है तो रानिया सीट पर रामचंद्र कम्बोज की जगह शिशपाल कम्बोज और पृथला सीट पर सोहन पाल की जगह टेकचंद शर्मा को टिकट दिया है। 2019 के चुनाव में भाजपा ने इस तरह से 2014 में जमानत जब्त वाली 12 विधानसभा सीटों पर पुराने चेहरों की जगह नए उम्मीदवारों पर दांव खेला था, जो कई सीटों पर सफल भी रहा। भाजपा उनमें से कुछ सीटें जीतने में कामयाब रही तो रानिया सीट छोड़कर बाकी विधानसभा सीट पर अपनी जमानत जब्त होने से बचा ले गई थी।

कांग्रेस ने साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को कांटे की टक्कर दी थी। कांग्रेस ने 90 में से 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 27 विधानसभा सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी।

कांग्रेस ने जाटों पर खेला बड़ा दांव

हरियाणा में कांग्रेस ने जाटों पर सबसे बड़ा दांव खेला है। वहीं पार्टी ने गैरजाटों का भी खास ख्याल रखा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सबसे ज्यादा जाट उम्मीदवारों को टिकट दिया है। पार्टी ने चुनावी मैदान में 35 जाट कैंडिडेट उतारे हैं। वहीं, दूसरे नंबर पर उसने ओबीसी को टिकट दिया है। 20 सीटों पर कांग्रेस ने ओबीसी उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा पार्टी ने अन्य जातियों पर भी पूरा भरोसा जताया है। कांग्रेस ने 17 सीटों पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इसके अलावा पार्टी ने पांच मुसलमानों को भी चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं, पार्टी ने पंजाबियों का भी खास ध्यान रखा है। छह सीटों पर कांग्रेस ने पंजाबियों को टिकट दिया है। इसके अलावा पार्टी ने चार सीटों पर ब्राह्मण, दो सीटों पर बनिया, एक सीट पर राजपूत उम्मीदवार उतारे हैं।

हरियाणा की अंबाला कैंट, अंबाला ग्रामीण, यमुनानगर, शाहबाद, नीलोखेड़ी, इंद्री, पानीपत ग्रामीण, उचाना, जुलाना, जींद, उकलाना, नारनौंद, हांसी, बरवाला, भिवानी, अटेली, नांगल चौधरी, गुरुग्राम, बादशाहपुर, सोहना, पटौदी, नरवाना, टोहना, फेतहाबाद, रानिया और सिरसा विधानसभा सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट अपनी जमानत नहीं बचा सके थे। कांग्रेस प्रत्याशियों में हांसी सीट पर ओमप्रकाश और उचाना सीट पर बलराम को सबसे कम वोट मिले थे। हांसी में कांग्रेस को 2.7 फीसदी वोट तो उचाना में 3.14 फीसदी वोट मिले थे।

कांग्रेस ने भी पिछले चुनाव में जमानत जब्त कराने वाले एक उम्मीदवार को छोड़कर सभी के टिकट इस बार काट दिए हैं। 2019 में जमानत जब्त हुई 27 सीटों में से 26 पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और एक सीट उसने सीपीआई-एम को चुनाव लड़ने के लिए दे दी है। कांग्रेस ने नरवाना सीट पर विद्या रानी दनोदा की जगह सतबीर, फतेहाबाद में प्रहलाद सिंह की जगह बलवान सिंह, रानिया में विनीत कम्बोज की जगह सर्वमित्र कम्बोज, सिरसा में होशियारी लाल की जगह गोकुल सेतिया, अंबाला कैंट में वेणु सिंगला की जगह परिमल परी, अंबाला शहर जसबीर मलौर की जगह चौधरी निर्मल सिंह, यमुनानगर में निर्मल चौहान की जगह मन त्यागी, शाहबाद सीट पर अनिल धंतौड़ी का जगह रामकरन और नीलोखेड़ी में बंता राम के स्थान पर धर्मपाल गोंदर को उतारा है।

इसी तरह कांग्रेस ने इंद्री सीट पर नवजोत कश्यप की जगह राकेश कुमार कम्बोज, पानीपत ग्रामीण सीट पर ओमप्रकाश जैन की जगह सचिन कुंडू, जुलाना में धर्मेंद्र ढुल की जगह विनेश फोगाट, जींद सीट पर अंशुल सिंगला की जगह महाबीर गुप्ता, उचाना में बलराम की जगह बृजेंद्र सिंह, उकलाना में बाला देवी की जगह नरेश सेलवाल, नारनौंद में बलजीत सिहाग की जगह जसबीर सिंह, हांसी में ओमप्रकाश की जगह राहुल मक्कड़ और बरवाला सीट पर भूपेंद्र गंगवा की जगह राम निवास घोरेला को प्रत्याशी बनाया है।

कांग्रेस ने चरखी-दादरी में नृपेंद्र सांगवान की जगह सोमबीर सांगवान, अटेली सीट पर अर्जुन सिंह की जगह अनीता यादव, नांगल चौधरी सीट पर राजा राम की जगह पर मंजू चौधरी और गुरुग्राम सीट पर सुखबीर कटारिया की जगह मोहित ग्रोवर को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने पटौदी सीट पर सुधीर कुमार की जगह पर्ल चौधरी, बादशाहपुर सीट पर राव कमलबीर की जगह वर्धन यादव और सोहना सीट पर शमशुद्दीन की जगह पर रोहताश खटाना को प्रत्याशी बनाया है। वहीं, कांग्रेस ने टोहाना सीट पिछली बार चुनाव लड़ने वाले परमवीर पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। पिछली बार परमवीर की जमानत जब्त हो गई थी। इसके बाद भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। इसके अलावा भिवानी में कांग्रेस के अमर सिंह हलुवासिया की जमानत जब्त हो गई थी। कांग्रेस ने इस बार भिवानी विधानसभा सीट को सीपीआई-एम के लिए छोड़ दी है। इस तरह कांग्रेस ने नए चेहरे ही नहीं बल्कि मजबूत प्रत्याशी उतारने का दांव चला है। विनेश फोगाट और बृजेश सिंह जैसे नेताओं को उतारा है।

चुनाव से पहले सीएम फेस पर घमासान

हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर देखी जा रही है। सूबे में पार्टी आंतरिक कलह से गुजर रही है। पार्टी के दो बड़े नेता कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच कुर्सी की जंग छिड़ गई है। इस बीच कुमारी सैलजा ने साफ कह दिया है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। सैलजा के इस बयान पर अब हुड्डा खेमे के विधायक का बयान सामने आया है। कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक मेवा सिंह का कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये पार्टी आलाकमान तय करेगा। उन्होंने कहा कि अगर आलाकमान कुमारी सैलजा को मुख्यमंत्री बनाना चाहेगा तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है और उनका फैसला सभी के लिए मान्य होगा। इसके साथ ही विधायक ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब हुड्डा राज्य के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में जनहित काफी काम किए। उनके कार्यकाल में हरियाणा का काफी विकास हुआ। विधायक ने कहा, उम्मीद है कि जनता एक बार फिर से उन पर भरोसा जताएगी।

हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुल 10 प्रमुख पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। भाजपा, कांग्रेस (89), आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। वहीं, जेजेपी-एएसपी का गठबंधन है। इसमें जजपा 70 तो आजाद समाज पार्टी (काशी राम) 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आई एनएलडी-बसपा-एचएलपी का गठबंधन है। आईएनएलडी 52, बीएसपी 37 और हरियाणा लोकहित पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) तीन और सीपीआई पांच सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को एक चरण में मतदान होना है। 12 सितंबर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। 16 सितंबर पर्चा वापस लेने की तारीख है। 8 अक्टूबर को इसके नतीजे आएंगे। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। चुनाव के बाद जननायक जनता पार्टी और सात निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर भाजपा ने यहां गठबंधन की सरकार बनाई थी। बाद में भाजपा-जजपा का गठबंधन टूट गया था। दरसअल हरियाणा में कांग्रेस दो खेमों में बंटती नजर आ रही है। एक खेमा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, तो वहीं दूसरा खेमा कुमारी सैलजा और कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला का है। दोनों ही खेमों के बीच खींचतान चल रही है जो अब खुलकर सामने आ गई है। हरियाणा में कांग्रेस दलित और जाटों को साधने की पुरजोर कोशिश कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सूबे के सबसे बड़े जाट नेता हैं तो वहीं कुमारी सैलजा दलित चेहरा हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए हुड्डा प्रबल दावेदार हैं, वहीं सैलजा के इस बयान से अब हुड्डा और उनके बीच की खाई और भी गहरी हो सकती है। चुनाव से पहले इस तरह की गुटबाजी से कहीं न कहीं पार्टी पर असर पड़ सकता है।

● **रजनीकांत पारे**

नक्सलवाद के खिलाफ मिशन-2026

छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खात्मे के लिए सीआरपीएफ की और 4 बटालियन को बस्तर में तैनात किया जा रहा है। करीब 4 हजार जवान बस्तर के अलग-अलग जिलों में नक्सल मोर्चे पर तैनात होंगे। इनमें झारखंड से 3 और बिहार से 1 बटालियन को भेजा जा रहा है। आईजी सुंदरराज पी के मुताबिक कुछ जवान बस्तर पहुंचे हैं। अन्य की ट्रेनिंग चल रही है। बारिश के बाद ट्रेनिंग पूरी करके वे आएंगे। साल 2026 तक बस्तर से नक्सलवाद खत्म करने केंद्र सरकार की नई स्ट्रैटजी है। सरकार का दावा है कि नक्सलियों के साथ अब यह निर्णायक लड़ाई है। नक्सलियों से लड़ने के लिए फोर्स को और मजबूत किया जा रहा है। इससे पहले नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में इंडियन आर्मी बेस कैंप खोलने की तैयारी में है। जमीन का सर्वे भी किया जा चुका है। अंदरूनी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आने वाले कुछ महीनों के अंदर और कैंप स्थापित करने की योजना है। इसलिए सीआरपीएफ की 159, 218, 214 और 22वीं बटालियन के 4 हजार जवानों को बस्तर भेजा जा रहा है।

सीआरपीएफ की हर एक बटालियन में करीब 1 हजार जवान होते हैं। इलाके के हिसाब से इन्हें कंपनियों में बांटा जाता है। हर एक कंपनी में लगभग 130 से 150 (ये संख्या बढ़ भी सकती है।) सोल्जर होते हैं। जिन 4 हजार जवानों को नक्सलियों से लड़ने के लिए बस्तर भेजा जा रहा है ये कहां तैनात होंगे, किस इलाके में नया कैंप खुलेगा, फिलहाल अभी ये स्पष्ट नहीं है। इनकी तैनाती प्रदेश की राजधानी रायपुर से करीब 450 से 500 किलोमीटर दक्षिण स्थित बस्तर क्षेत्र में की जाएगी। सीआरपीएफ को देश में प्रमुख आंतरिक सुरक्षा और नक्सल विरोधी अभियान बल के तौर पर जाना जाता है। झारखंड एवं बिहार में नक्सली हिंसा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और घटनाएं नगण्य हैं। इसलिए इन बटालियनों को वहां से हटाकर छत्तीसगढ़ में तैनात किया जा रहा है, जहां अब नक्सल विरोधी अभियान केंद्रित हैं। बता दें कि सीआरपीएफ की एक बटालियन में करीब 1,000 जवान होते हैं। सूत्रों ने बताया कि इन इकाइयों को दंतेवाड़ा और सुकमा के दूरदराज के जिलों और ओडिशा, आंध्रप्रदेश व तेलंगाना के साथ लगती सीमा पर तैनात किया जा रहा है।

बस्तर में इस साल जनवरी से अब तक अलग-अलग जिलों में हुई मुठभेड़ों में जवानों ने कुल 153 नक्सलियों को ढेर किया है। इनमें 25 लाख रुपए के डीकेएसजेडसी कैडर के नक्सली भी मारे गए हैं। जबकि 669 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। 654 नक्सली हथियार डाल चुके हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों रायगढ़ में कहा था कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरण में है और इसे खत्म करने के लिए कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। केंद्र नक्सलवाद (वामपंथी उग्रवाद) का खात्मा करने को प्रतिबद्ध है। इस दौरान नक्सलियों को खुली चुनौती देते हुए शाह ने कहा, यदि वे अपना रास्ता नहीं बदलते हैं तो अंतिम प्रहार होगा। छत्तीसगढ़ समेत देश को 2026 तक नक्सल समस्या से मुक्त कर लेंगे। वामपंथी उग्रवाद की वजह से लोग निरक्षर रह गए हैं उन्हें साक्षर बनाने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पहल करेगी। एनआईए की तर्ज पर एसआईए बनाएंगे। राज्य सरकार जल्द नई सरेंडर पॉलिसी की घोषणा करेगी। बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में 3 सितंबर को हुई मुठभेड़ में जवानों ने 9 नक्सलियों को मार गिराया था। उसके बाद 5 सितंबर को बीजापुर बॉर्डर से लगे तेलंगाना के गुंडाला करकागुडेम के नीलाद्रि वन क्षेत्र के झाड़ागुट्टा गांव के पास ग्रेहाउंड्स फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में ग्रेहाउंड फोर्स ने 6 नक्सलियों को ढेर किया। बता दें कि वामपंथी उग्रवाद को कभी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा कहा जाता था।

दिल्ली में बल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये बटालियनें सीआरपीएफ की कोबरा इकाइयों के साथ मिलकर जिलों के दूरदराज के इलाकों में और अधिक फारवर्ड ऑपरेटिंग बेस (एफओबी) स्थापित करेंगी, ताकि क्षेत्र को सुरक्षित करने के बाद विकास कार्य शुरू किए जा सकें। पिछले तीन वर्षों में बल ने छत्तीसगढ़ में लगभग 40 एफओबी बनाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बेस स्थापित करने में कई तरह की चुनौतियां आती हैं, जैसे कि नक्सलियों द्वारा जवानों पर घात लगाकर और विस्फोटक उपकरणों से हमला करना। नई बटालियनें तैनात करने का उद्देश्य बस्तर के सभी नो-गो क्षेत्रों में पैर जमाना है ताकि सरकार द्वारा तय की गई समय-सीमा के भीतर नक्सलवाद को समाप्त किया जा सके। हालांकि, एक अन्य अधिकारी ने बताया कि सीआरपीएफ बटालियनों को लगातार तकनीक, हेलीकॉप्टर और संसाधन सहायता की आवश्यकता होगी, क्योंकि दक्षिण बस्तर नक्सल विरोधी अभियानों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। छत्तीसगढ़, खासकर बस्तर संभाग के लिए सुकून भरी खबर है। यहां नक्सली हिंसा की वजह से 20 साल पहले कई स्कूल बंद हो गए थे। इन स्कूलों को अब दोबारा शुरू कर दिया गया है। सैकड़ों बच्चे वापस पढ़ाई की ओर लौटे रहे है। इन बच्चों के हाथों में एक बार फिर कॉपी-किताबें और पेंसिल हैं। जानकारी के मुताबिक, सरकार ने बस्तर संभाग के 41 स्कूलों को फिर से खोल दिया है। इन स्कूलों में वे 34 स्कूल भी शामिल हैं, जो बीजापुर जिले में हैं।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

बस्तर में तैनात हैं 60 हजार से ज्यादा जवान

बस्तर में अलग-अलग फोर्स के करीब 60 हजार से ज्यादा जवान तैनात हैं। इनमें कांकेर में एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, नारायणपुर में आईटीबीपी, बीएसएफ, एसटीएफ, कोंडागांव में आईटीबीपी, सीआरपीएफ, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। इसके अलावा सभी जिलों में डीआरओ, जिला बल, बस्तर फाइटर्स, बस्तरिया बटालियन भी नक्सलियों के खिलाफ लोहा लेती है। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में इंडियन आर्मी का बेस कैंप खोलने की तैयारी है। इसके लिए जमीन का सर्वे भी किया गया है। अवर सचिव ने कलेक्टर से सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी मांगी है। अवर सचिव उमेश कुमार पटेल ने नारायणपुर कलेक्टर को जो पत्र लिखा है उसमें थल सेना के कैंप से संबंधित जमीन की जानकारी मांगी गई है।

अजित ने बढ़ाई महायुति में टेंशन

महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राज्य में विधानसभा की 288 सीटें हैं। सूबे के दो बड़े गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर मंथन चल रहा है। कहां से कौन लड़ेगा, किसे टिकट दिया जाए, ये सवाल एमवीए और महायुति के सामने है। महायुति की बात करें तो भाजपा के नेतृत्व वाले इस गठबंधन में सीट बंटवारे पर घमासान मचा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 60 से ज्यादा सीटों की मांग की है। एनसीपी अजित पवार गुट की ओर से बताया गया है कि उनकी पार्टी इन सभी सीटों पर चुनाव लड़ने और जीतने का माद्दा रखती हैं। पूरे मसले पर हाल ही में अजित पवार गुट की आंतरिक बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल के आवास पर अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक हुई। इस बैठक में महायुति में सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद यह अजित पवार गुट की आंतरिक बैठक थी। इस बैठक में अजित पवार गुट के नेताओं ने 60 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अजित पवार को 60 से 65 सीटें मिलने पर महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर असंतोष है।

लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। इसी के चलते दोनों पार्टियां फिलहाल सीट बंटवारे को लेकर चर्चा करती नजर आ रही हैं। सूत्रों ने जानकारी दी है कि एनसीपी अब महायुति में 60 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। एनसीपी के पास फिलहाल 54 विधायक हैं। अजित पवार ने ये भी दावा किया है कि एक सभा में कांग्रेस के तीन विधायक और तीन निर्दलीय विधायक उनके साथ थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस के हीरामन खोसकर, जीशान सिद्दीकी और सुलभा खोडके जल्द ही उनके साथ जुड़ेंगे। अजित पवार ने कहा था कि शेकाप के निर्दलीय विधायक देवेंद्र भुयार, संजय मामा शिंदे और श्यामसुंदर शिंदे भी उनके साथ हैं। इसलिए कहा जा रहा था कि अजित पवार 60 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भाजपा आधी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। यानी भाजपा 288 में से 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसलिए महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर फिलहाल मंथन चल रहा है।

भाजपा और अजित पवार की एनसीपी के बीच 21 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। ये वो सीटें हैं जहां पर दोनों पार्टियों के बीच बराबर का मुकाबला रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में दोनों के बीच इन सीटों पर कांटे की टक्कर देखी गई थी, यही वजह है कि दोनों पार्टियां उन सीटों पर दावा ठोक रही हैं। इनमें से ज्यादातर सीटें पश्चिमी महाराष्ट्र की हैं। जिन सीटों पर पेच फंसता दिख रहा है वो इंदापुर, उडगीर, वाई, पार्ली, वडगांव शेरी, मवाल, कागल, हड़पसार, अहमदपुर, अमलनेर, अर्जुनी मोरगांव, अहेरी, विक्रमगढ़, अकोले हैं। दोनों पक्षों के कम से कम चार वरिष्ठ नेताओं ने एक-दूसरे के खिलाफ खुलकर बात की है। इनमें से कई तो पार्टी छोड़ने की कगार पर हैं। चुनाव नजदीक आने के साथ-साथ ये टकराव और बढ़ने की उम्मीद है। भाजपा नेता हर्षवर्द्धन पाटिल, समरजीत घाटगे और गणेश हेके इन सीटों पर अपनी राय बता चुके हैं। एनसीपी (अजित पवार) के नेता रामराजे नाइक निंबालकर भाजपा के खिलाफ बयान दे चुके हैं। पाटिल और घाटगे क्रमशः इंदापुर और कागल विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। ये दोनों नेता शरद पवार के गुट में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि उनका दावा है कि ये सीटें अजित पवार के पास हैं।

पाटिल और घाटगे 2019 का विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। एनसीपी उम्मीदवारों के हाथों उन्हें शिकस्त मिली। इस बार जब उन्हें लगा कि वे जीत सकते हैं, तो उन्हें बताया गया कि सीट एनसीपी के खाते में जा सकती है। हेके की नजर लातूर की अहमदपुर सीट पर है। वह भी एनसीपी से गठबंधन के खिलाफ बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये जारी रहा तो भाजपा को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। निंबालकर भी अजित पवार के साथ हैं। वह कभी शरद पवार के करीबी हुआ करते थे। अब वह फिर से शरद पवार के गुट को ज्वाइन करने की धमकी दे रहे हैं। उनका कहना है कि वह भाजपा नेताओं, रंजीत सिंह निंबालकर और जयकुमार गोरे के साथ सोलापुर और सतारा की स्थानीय राजनीति में कंफर्टेबल नहीं हैं। वह भाजपा और एनसीपी के समीकरण से भी खुश नहीं हैं। सोलापुर के दो अन्य भाजपा नेता उत्तमराव जनकर और प्रशांत पारिचरक भी जिले के बदलते समीकरण को देखते हुए शरद पवार गुट की तरफ जाते दिख रहे हैं। मराठवाड़ा के एक भाजपा नेता ने कहा, अजित पवार गुट के 21 विधायकों ने 2019 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के खिलाफ जीत हासिल की। दोनों पार्टियां और उनके कार्यकर्ता वर्षों से चुनावी राजनीति में विभिन्न स्तरों पर एक-दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं। उनकी विचारधाराएं और टारगेट वोटर अलग-अलग हैं और वे एक-दूसरे के साथ मेल नहीं खा सकते हैं। लोकसभा चुनाव में यह स्पष्ट हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता पिछले जुलाई में अजित पवार से हाथ मिलाने के पार्टी नेतृत्व के फैसले से नाराज थे। उन्होंने कहा, वे इस बात से भी चिंतित हैं कि अगर एनसीपी (अजित पवार) को इन निर्वाचन क्षेत्रों पर लड़ने की अनुमति दी गई तो पार्टी इन निर्वाचन क्षेत्रों में अपना आधार खो देगी।

● **बिन्दु माथुर**

60-65 सीटों पर लड़ सकती है एनसीपी

कहा जा रहा है कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को 60 सीटें मिलेंगी। दूसरी ओर अजित पवार ग्रुप 60 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहा है। इसी के तहत हाल ही में अजित पवार गुट की बैठक हुई थी। सूत्रों के मुताबिक, प्रफुल्ल पटेल के आवास पर पार्टी की ये बैठक हुई। इस बैठक में गठबंधन में सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद यह अजित पवार गुट की ये बैठक हुई थी। इस बैठक में अजित पवार गुट के नेताओं ने 60 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने पर टिप्पणी की। सूत्रों के मुताबिक, अजित पवार को गठबंधन से 60 से 65 सीटें ही मिलेंगी। ऐसे में अब सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन में असंतोष देखने को मिल रहा है। एनसीपी के पास 54 विधायक हैं। इसके साथ ही अजित पवार दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के 3 और निर्दलीय विधायक भी उनके साथ हैं। यही वजह है कि अजित पवार 60 से ज्यादा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं।

साइलेंट वसुंधरा अचानक मुखर

वसुंधरा राजे राजस्थान में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद की मजबूत दावेदार थीं। पार्टी ने पहले बगैर सीएम फेस के चुनाव लड़ने का ऐलान किया और फिर जीत के बाद भजनलाल शर्मा को सरकार की कमान सौंप दी। करीब 10 महीने पहले मुख्यमंत्री पद के लिए भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव भी विधायक दल की बैठक में वसुंधरा राजे से ही रखवाया गया। तब से ही वसुंधरा के सियासी करियर को लेकर कयासों का दौर चलता आया है लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव के बाद से ही साइलेंट रहीं। वसुंधरा अब अचानक मुखर हो गई हैं।

उन्होंने सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर के सम्मान में आयोजित अभिनंदन समारोह के दौरान कहा, ओम माथुर चाहे कितनी ही बुलंदियों पर पहुंच गए लेकिन इनके पैर हमेशा जमीन पर ही रहते हैं। इसीलिए इनके चाहने वाले भी असंख्य हैं। वरना कई लोगों को पीतल की लौंग क्या मिल जाती है, वे खुद को सर्राफ समझ बैठते हैं। वसुंधरा राजे की इस टिप्पणी ने नई चर्चा को जन्म दे दिया है। वसुंधरा की इस टिप्पणी को कोई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जोड़कर देख रहा है, तो कोई विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके मदन राठौड़ से। यह टिप्पणी किसके लिए थी, यह तो वसुंधरा ही जानें लेकिन बात इसे लेकर भी हो रही है कि चुनाव के बाद से साइलेंट चल रहीं वसुंधरा राजे अचानक मुखर क्यों हो गईं, क्यों तेवर दिखा रही हैं? राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी का कहना है कि वसुंधरा राजे राजस्थान भाजपा का पावर सेंटर हुआ करती थीं लेकिन पिछले करीब एक साल में ही परिस्थितियों ने ऐसी करवट ली कि वह हाशिए पर चली गई हैं। सत्ता परिवर्तन का असर कहें या क्या, जो नेता-विधायक पहले वसुंधरा की परिक्रमा करते नजर आते थे, अब दूरी बना रहे हैं। उनकी यह टिप्पणी नेताओं के व्यवहार में खुद को लेकर आए बदलाव को लेकर निराशा बता रही है। सरकार में नहीं तो संगठन में ही सही या फिर कोई और जिम्मेदारी, महारानी अब तेवर दिखा रही हैं तो उसके पीछे अपना खोया सियासी वैभव पाने की कोशिश ही है।

एक पहलू यह भी है कि वसुंधरा राजे 71 साल की हो चुकी हैं। भाजपा की अघोषित नीति 75 साल से अधिक उम्र के नेताओं को टिकट देने से परहेज कर मार्गदर्शक मंडल में डाल देने की रही है। राजस्थान के अगले चुनाव तक वसुंधरा भाजपा में एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट की इस आयु सीमा तक पहुंच चुकी होंगी। वसुंधरा राजे के सामने अब आगे भी एक्टिव पॉलिटिक्स में प्रासंगिक बनाए रखने की चुनौती है। वहीं वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत भी सियासत में हैं। दुष्यंत झालावाड़-बारां सीट से चौथी बार के सांसद हैं। भाजपा ने जब मुख्यमंत्री के लिए भजनलाल शर्मा का नाम आगे किया और इसका प्रस्ताव खुद वसुंधरा से ही रखवाया गया, ऐसा कहा जाने लगा कि पार्टी ने उन्हें दुष्यंत को लेकर जरूर कोई बड़ा आश्वासन दिया होगा। वसुंधरा की राजनीति का मिजाज भी ऐसा नहीं रहा है, जिससे यह मान लिया जाता कि वह समर्पित सिपाही की तरह आलाकमान का हर फैसला ऐसे ही मान लेंगी। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बन गई लेकिन दुष्यंत खाली हाथ ही रहे। चौथी बार के सांसद दुष्यंत मोदी मंत्रिमंडल में जगह पाने से भी वंचित ही रहे।

वसुंधरा राजे सिंधिया के तेवरों के पीछे यह भी एक फैक्टर हो सकता है कि दुष्यंत का लोकसभा चुनाव में टिकट पक्का रहे। दुष्यंत चार बार के सांसद हैं और अब जब पार्टी वसुंधरा की परछाई से बाहर निकलने की तरफ बड़े कदम बढ़ा चुकी है, पूर्व मुख्यमंत्री को यह चिंता भी सता रही होगी कि कहीं चार बार की एंटी इनकम्बेंसी का हवाला देकर पार्टी उनके बेटे का टिकट ही न काट दे। हालिया लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के बेटे और उप्र की पीलीभीत सीट से सांसद रहे वरुण गांधी का टिकट काट दिया था।

2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर पूर्ण बहुमत के आंकड़े को पार करने वाली भाजपा हालिया लोकसभा चुनाव में 240 सीटें ही जीत सकी। दोनों ही चुनावों में राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप करने वाली भाजपा को इस बार 11 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सीटों पर पार्टी के कमजोर प्रदर्शन को भी वसुंधरा के लिए आपदा में अवसर की तरह बताया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि वसुंधरा राजे एक बड़ा चेहरा होने के बावजूद मुख्यमंत्री नहीं बनाई गईं। जबकि उनका नाम सबसे आगे चल रहा था। लेकिन उनकी जगह भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। यही उनकी नाराजगी का कारण हो सकता है। इससे पहले 24 जून 2024 को वसुंधरा राजे ने पाला बदलने वाले नेताओं पर निशाना साधा था।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

घूम लिया मैंने जग सारा...

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। वसुंधरा राजे लगातार अपने शायराना अंदाज में जहां विरोधियों पर तंज कस रही हैं। वहीं अपनी बात भी वह इसी अंदाज में रख रही हैं। बीते दिनों वसुंधरा राजे जयपुर में ओम प्रकाश माथुर के अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुई थीं। उन्होंने इस कार्यक्रम में भी अपने अंदाज में संबोधित किया। वहीं उन्होंने सदस्यता अभियान शुरू होने पर जयपुर में सदस्यता ग्रहण नहीं की। जबकि उन्होंने झालावाड़ में आकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। हालांकि वसुंधरा राजे ने इसकी वजह भी बताई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ जिले के दौरे के दौरान कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान राजे ने कहा, घूम लिया मैंने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा...। उन्होंने कहा कि मुझे जयपुर में सदस्यता ग्रहण करने के लिए कहा गया था, लेकिन मैंने निर्णय लिया, कि मैं अपने घर झालावाड़ में ही सदस्यता लूंगी। वसुंधरा राजे ने कहा कि 21 अक्टूबर 1951 में हमारी विचारधारा का जो जनसंघ रूपी कारवां शुरू हुआ, वह विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन चुका है। यह हमारे कार्यकताओं की बदौलत हुआ, कार्यकर्ताओं के धैर्य की वजह से हुआ।

न अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, न ही सदस्य

आयोग के दफ्तर में बैठने की पर्याप्त जगह नहीं

लखनऊ के इंदिरा भवन के तीसरे तल पर मौजूद पिछड़ा वर्ग आयोग का दफ्तर जगह की कमी से भी कराह रहा है। यहां पर अध्यक्ष, दो उपाध्यक्षों समेत सचिव, अन्वेषण अधिकारी, विधि अधिकारी समेत करीब 30 अन्य कर्मचारियों की तैनाती है लेकिन इन सबके बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। आयोग में कुल 25 सदस्य हैं जो केवल बैठकों के दौरान ही लखनऊ में उपस्थित होते हैं। ये बैठकें मुख्य रूप से आयोग में 2010 में बने छत्रपति शाहू जी महाराज सभागार (सुनवाई कक्ष) में संपन्न होती हैं। आयोग के लिए स्वतंत्र रूप से एक नया भवन बनाने की कार्रवाई साल 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने शुरू की थी। मायावती ने अधिकारियों को लखनऊ के गोमतीनगर इलाके में पिछड़ा वर्ग आयोग के दफ्तर के लिए जमीन तलाशने का निर्देश दिया था। साल 2012 में बसपा की सरकार जाने के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए नया भवन बनाने का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया। हालांकि मंत्री नरेंद्र कश्यप पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए नया भवन बनाने के लिए जरूरी कार्रवाई करने की बात कहते हैं। लेकिन आयोग का नया दफ्तर कब हकीकत में उतरेगा, इसे बता पाना जिम्मेदारों के लिए अभी संभव नहीं है।

सरकारें संस्थाओं का गठन करती हैं कि लोगों की समस्याओं का समाधान समय पर हो सके। लेकिन कई संस्थाएं ऐसी हैं जो सफेद हाथी साबित हो रही हैं। इन्हीं में से एक है उप्र पिछड़ा वर्ग आयोग। असल में उप्र पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों का पद पिछले दो साल से खाली चल रहा है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने 16 जून 2021 को उप्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर जसवंत सैनी को अध्यक्ष और हीरा ठाकुर व प्रभुनाथ चौहान को आयोग का उपाध्यक्ष मनोनीत किया था। साल 2022 में योगी सरकार ने उप्र की सत्ता में वापसी की और जसवंत सैनी को मंत्री की कुर्सी से नवाजा गया। इसके बाद से ही उप्र पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष की कुर्सी खाली पड़ी है। जुलाई 2022 में पिछड़ा वर्ग आयोग के दोनों उपाध्यक्ष और 25 सदस्यों का कार्यकाल भी समाप्त हो गया। इसके बाद से आयोग के दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है। आयोग में कार्यरत एक अन्वेषण अधिकारी बताते हैं कि अभी जो भी शिकायतें आ रही हैं, उन्हें जिलों में संबंधित अधिकारियों के पास कार्रवाई के लिए भेज दिया जा रहा है।

लोकसभा चुनाव में जिस तरह विपक्ष ने आरक्षण और संविधान के मुद्दों के जरिए भाजपा के समर्थक पिछड़े वर्ग में सेंध लगाई है उसके बाद से पिछड़ा वर्ग आयोग के पुनर्गठन की चर्चाओं ने भी जोर पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार जल्द ही आयोग में एक अध्यक्ष और दो उपाध्यक्षों सहित 28 सदस्यों की नियुक्ति करेगी, जिनके पास ओबीसी समूहों से संबंधित नीतिगत मामलों में निर्णय लेने का अधिकार होगा। पिछड़ी जाति कल्याण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), नरेंद्र कश्यप का कहना है कि नए सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही पूरी होने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष उनकी मंजूरी के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव रखा गया है, जिसके बाद कश्यप की अध्यक्षता वाले पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया जाएगा।

राज्य सरकार उप्र की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के पहले हर हाल में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर लोकसभा चुनाव में मिले झटके की भरपाई करना चाहती है। लोकसभा चुनाव के बाद उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा की सहयोगी अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल पहले से ही योगी सरकार में पिछड़ा आरक्षण की विसंगतियों को लेकर हमलावर हैं। राजनीतिक विश्लेषक और लखनऊ के शिया कॉलेज में इतिहास विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर अमित राय कहते हैं कि उप्र में लंबे समय से पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होने का खामियाजा सत्तारूढ़ योगी सरकार को भुगतना पड़ रहा है। आयोग के न होने से ओबीसी वर्ग की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण नहीं हो पा रहा है जिसके चलते पिछड़े समाज में सरकार और भाजपा के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उप्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रहे राम आसरे विश्वकर्मा का कहना है कि योगी सरकार नहीं चाहती कि पिछड़ों के आरक्षण और अन्य समस्याओं से जुड़ी विसंगतियों पर कोई हस्तक्षेप करे। इसीलिए सरकार ने कार्यकाल पूरा हो जाने के दो साल बाद भी पिछड़ा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं की है। चूंकि आयोग सरकार की मनमानी पर अंकुश लगाता है इसलिए योगी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग के पुनर्गठन में कोई रूचि नहीं दिखाई है।

लोकसभा चुनावों में उप्र में बड़ा झटका खाने के बाद अब भाजपा ओबीसी समुदाय की ओर देखने के लिए मजबूर हो रही है। यही नहीं लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में रूचि नहीं दिखाई उसे भी पार्टी के खराब प्रदर्शन का एक कारण माना जा रहा है। जुलाई में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से दिल्ली में मुलाकात करके उन्हें पार्टी के खराब प्रदर्शन की जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का समायोजन न होने को एक बड़ी वजह बताया गया था। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। पार्टी में शीर्ष स्तर से कार्यकर्ताओं को समायोजित करने का निर्देश मिलने के बाद उप्र में आयोगों के गठन को लेकर हलचल कुछ बढ़ी है।

साल 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद भी विभिन्न आयोगों में समायोजन के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं की एक सूची बनी थी लेकिन संगठन और सरकार में तालमेल न बन पाने के कारण यह अधर में ही लटक गई। अब भाजपा ने अपने क्षेत्रीय और जिला अध्यक्षों से एक बार फिर पिछड़ा वर्ग समेत विभिन्न आयोगों में समायोजित किए जाने वाले कार्यकर्ताओं के नाम मांगे हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि आयोगों में समायोजित किए जाने के लिए ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं के नामों पर विचार किया जा रहा है जो अपनी-अपनी जातियों में जमीनी स्तर पर पकड़ रखते हों। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं के नाम न भेजकर ऐसे कार्यकर्ताओं के नाम भेजने को कहा गया है जो लंबे समय से पार्टी से जुड़े हैं और अभी तक उन्हें कोई पद नहीं मिला है। इसके अलावा सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं को भी आयोग में समायोजित किया जाएगा।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

कितना चटकेगा चंपाई रंग...

छह महीने के भीतर तस्वीर इस कदर बदल जाएगी, शायद इसका एहसास खुद पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को भी नहीं रहा होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के सुप्रीमो शिबू सोरेन के खासमखास और पार्टी के पुराने सिपाही रहे चंपाई की राहें अब जुदा हो गई हैं। कोल्हान के टाइगर के रूप में चर्चित नेता के भाजपा में जाने से झारखंड में राजनीतिक सरगरमी बढ़ गई है। अगले एक-दो महीने में झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है। फिलहाल उनके अकेले पाला बदलने से हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार और इंडिया गठबंधन को खास फर्क पड़ता नहीं दिखता है, लेकिन कोल्हान क्षेत्र में आदिवासी वोटों के बिखरने का खतरा हो सकता है। हालांकि 20 अगस्त को दिल्ली से खाली हाथ लौटे चंपाई ने नई पार्टी बनाने का संकेत दिया था। लेकिन आखिरकार 26 अगस्त की रात को असम के भाजपाई मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी कि चंपाई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन 30 अगस्त को भाजपा में शामिल होंगे।

दरअसल 81 सदस्यीय विधानसभा वाले झारखंड में कोल्हान क्षेत्र में 14 सीटें हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में यहां भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया था। 14 सीटों में से 11 झामुमो, दो कांग्रेस और एक निर्दलीय ने जीती थी। यही नहीं, 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड में आदिवासियों के लिए सुरक्षित 28 सीटों में भाजपा को सिर्फ दो ही सीटें मिली थीं। इस साल 2024 के संसदीय चुनाव में तब और बड़ा झटका लगा, जब आदिवासियों के लिए सुरक्षित सभी पांच सीटों पर भाजपा को हार मिली। इससे आदिवासी वोटों को लेकर भाजपा में भारी बेचैनी है। अब चंपाई की बगावत के सहारे भाजपा स्थितियां बदलने के प्रयास में है।

चंपाई सरायकेला से 1991 में विधानसभा उपचुनाव बतौर निर्दलीय जीते थे। फिर, 1995 में झामुमो की टिकट पर जीते। 2000 में भाजपा लहर को छोड़कर वे लगातार छह बार जीते हैं। हाल में विवादास्पद मामले में हेमंत सोरेन को जब जेल जाना पड़ा तो मुख्यमंत्री की कुर्सी चंपाई को सौंपी गई थी। करीब पांच महीने बाद हेमंत हाइकोर्ट के आदेश से जब जेल से निकले, तो चंपाई को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। कहते हैं कि चंपाई इसी से आहत हुए और नए रास्ते की तलाश में जुट गए। मौके की ताक में बैठी भाजपा उनकी आहत भावनाओं का लाभ उठाने में जुट गई। आदिवासी वोटों पर डोरे डालने को बेताब भाजपा ने कोल्हान में झामुमो के किले को ढहाने का फौरन एक्शन प्लान बना लिया। मगर भाजपा से लाइजनिंग कर रहे और विधायक बनने की लालसा रखने वाले चंपाई के पुत्र बाबूलाल और मीडिया सलाहकार चंदन की कमजोर प्लानिंग से खेल बिगड़ गया। चंपाई के साथ कोल्हान के कई विधायकों के पाला बदल कर भाजपा में शामिल होने की तैयारी की खबर लीक हो गई। जानकारों के मुताबिक, भाजपा के एक बड़े आदिवासी नेता भी फौरन सक्रिय हो गए क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा मजबूत आदिवासी नेता पार्टी में शामिल होकर उनके रास्ते का कांटा बने। झामुमो भी फौरन सक्रिय हो गया।

चंपाई का झामुमो से मोहभंग हो चुका है, इसकी तस्दीक उनके घर और एक्स हैंडल से झामुमो का झंडा हटने से भी हो रही थी। वे 18 अगस्त को वाया कोलकाता चंपाई दिल्ली पहुंचे थे। उनके साथ कोल्हान के चार और विधायकों के पहुंचने की खबर थी। लेकिन जब वे अकेले दिल्ली पहुंचे, तब सूत्रों के मुताबिक भाजपा के बड़े नेताओं ने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी। हालांकि अखबारों में उन चार नेताओं के नाम भी छपने लगे थे। चंपाई खाली हाथ लौट आए। लौटने पर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वे भाजपा नेताओं से मिलने नहीं बल्कि पोते के बुलाने पर चश्मा बनवाने दिल्ली गए थे। चंपाई जिस दिन लौटे, उसी दिन कोल्हान के पोटका विधायक संजीव सरदार, घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती और जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने मुख्यमंत्री आवास जाकर हेमंत सोरेन से मिलकर झामुमो में अपनी निष्ठा जताई।

चंपाई सोरेन का कहना था कि उनके पास तीन विकल्प हैं- संन्यास, संगठन या किसी के साथ जाना। अब सोशल मीडिया पर भी चंपाई और झामुमो के बीच की खटास बाहर आने लगी है। चंपाई सोरेन के आहत होने वाली एक पोस्ट पर कांग्रेस के जमशेदपुर पश्चिम विधायक और राज्य के स्वास्थ्य एवं खाद्य तथा आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने जवाबी हमला किया। बन्ना गुप्ता ने चंपाई को विभीषण कह डाला। कहा जा रहा है कि झामुमो की ओर से बन्ना गुप्ता को ऐसा करने को कहा गया था। हालांकि एक कार्यक्रम में जब हेमंत सोरेन ने पत्रकारों के सवाल पर कहा था कि चंपाई दा ने उन्हें पार्टी या उनसे नाराजगी के बारे में कुछ नहीं बताया है। बहरहाल, देखना होगा कि कोल्हान के संतालियों में कभी सबसे दमदार नेता रहे 68 वर्ष की उम्र में खुद को कितना प्रभावी साबित कर पाते हैं। भाजपा को शायद उम्मीद है कि वे आदिवासी वोटों में कुछ सेंध लगा सकेंगे।

● **विनोद बक्सरी**

जदयू में सरयू

झारखंड की राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले जमशेदपुर पूर्व से निर्दलीय विधायक सरयू राय अब जदयू के हो गए हैं। कभी वे भाजपा दिग्गज हुआ करते थे। सरयू राय झारखंड की राजनीति में मुखर और बड़ा चेहरा हैं। 2019 के चुनाव में टिकट कटने के बाद वे तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवरदास के खिलाफ जमशेदपुर पूर्व से चुनाव लड़े और जीत गए। इसके पहले वे जमशेदपुर पश्चिम से विधायक और रघुवर सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। अब 2024 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनके जदयू में जाने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। नीतीश कुमार झारखंड में अपनी पार्टी का विस्तार चाहते हैं और सरयू राय सुरक्षित ठिकाना। सरयू राय और नीतीश कुमार छात्र जीवन से मित्र हैं। इसके पहले सरयू राय की घर यानी भाजपा में वापसी और रघुवरदास के अड़चन को लेकर बीच-बीच में चर्चाएं चलती रहीं। रघुवरदास ओडिशा के राज्यपाल बन चुके हैं। जदयू झारखंड की 11 सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। जदयू को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता के लिए पार्टी को और राज्यों में विस्तार की जरूरत है। जदयू में शामिल होने पर सरयू राय का कहना है कि नीतीश कुमार से मिलने गया था वे बोले ज्वाइन कर लीजिए, मैंने हां कह दिया। सरयू राय की पुरानी जमशेदपुर पश्चिम सीट पर हेमंत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री, कांग्रेस के बन्ना गुप्ता का कब्जा है। एनडीए में जमशेदपुर पूर्व पर सिटिंग विधायक के नाते इस सीट पर जदयू की दावेदारी होगी। भाजपा के समर्थन से सरयू राय का रास्ता आसान हो जाएगा।

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच बढ़ता टकराव

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों में पाकिस्तानी सेनाएं और तालिबान के बीच कई बार टकराव की स्थिति बनी है। इस बीच तालिबान ने डूरंड लाइन के करीब कई नई सैन्य चौकियों का निर्माण किया है। इन चौकियों से वे पाकिस्तानी सैनिकों को उकसा रहे हैं। अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान के कुनार प्रांत के डांगम इलाके में पाक सीमा पर पाकिस्तानी बाड़ के करीब नई चौकियां बनाई हैं। इन सैन्य चौकियों को पाकिस्तानी सेना पर दबाव के लिए बनाया गया है। इससे पहले भी तालिबान और पाकिस्तान में पिछले कई दिनों रुक-रुककर झड़पें हुईं। टकराव के बीच, अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पास सीमा क्षेत्र में पाकिस्तानी सुरक्षाबलों के साथ झड़प में दो प्रमुख कमांडरों सहित कम से कम आठ अफगान तालिबान सैनिक मारे गए। प्रांत के खुर्रम सीमावर्ती जिले में हुई गोलीबारी में 16 अफगान तालिबान सैनिक भी घायल हो गए।

पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अफगान बलों की ओर से अफगानिस्तान के पिलवासिन इलाके में अकारण गोलीबारी की गई। इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की गई है। जियो न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया कि अफगानिस्तान तालिबान के दो प्रमुख कमांडर खलील और जान मोहम्मद गोलीबारी में मारे गए। कथित तौर पर अफगान बलों ने 7 सितंबर की सुबह पिलवासिन में हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर गोलीबारी की। पाकिस्तान में लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं। इसके अलावा हाल के महीनों में पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर अफगानिस्तान की ओर से हमलों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। पाकिस्तान ने फिर अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार से अपनी जमीन का इस्तेमाल तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को करने से रोकने को कहा है। वहीं 2021 में दर्जनों बार दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर टकरा चुकी हैं। इनमें दोनों ही पक्षों के कई लोग हताहत भी हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीमा पर हुई झड़पों में तालिबान के लगभग 8 लड़ाके मारे गए हैं। वहीं 16 अन्य लोग घायल हो गए। इसमें अफगानिस्तान तालिबान के दो प्रमुख कमांडर खलील और जान मोहम्मद गोलीबारी में मारे गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तानी सेना के कमांडर मुहम्मद अली हाल ही में डूरंड लाइन पर हुई हिंसा में मारे गए। वहीं 3 अन्य सैनिक घायल हुए।

अफगानिस्तान में तालिबान के वापस आने के तीन साल बाद पाकिस्तान ने माना है कि तालिबान की वापसी में पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की। पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ और विदेश मंत्री इशहाक डार ने अपने ब्रिटेन दौरे पर कहा कि आईएसआई प्रमुख जनरल फैज हमीद की अफगानिस्तान यात्रा पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ी। उन्होंने कहा कि आईएसआई प्रमुख की काबुल में चार चुस्कियां पाकिस्तान के लिए महंगी साबित हुई। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक जनरल हमीद को तालिबान की वापसी को आसान बनाने के लिए अफगान भेजा गया था, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान सशस्त्र सहायता के लिए तालिबान पर भरोसा कर सके, लेकिन ये पाक के लिए भारी पड़ा। इस वक्त अफगान सरकार और पाक सरकार के बीच रिश्ते खराब चल रहे हैं और पाकिस्तान बार-बार आरोप लगा रहा है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान में आतंक फैलाने के लिए हो रहा है। तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान में जश्न मनाया गया था। तत्कालीन इमरान सरकार ने तालिबान नेताओं से मिलने अपने कई अधिकारियों को काबुल भेजा था। तालिबान के सत्ता में वापसी के बाद से पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई हैं और आए दिन हो रहे धमाकों में कई नागरिकों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान इन घटनाओं का इल्जाम अफगानिस्तान पर लगा रहा है, वहीं पाकिस्तान के अफगान शरणार्थियों को वापस भेजने के फैसले के बाद से दोनों सरकारों में तल्खी और बढ़ गई है।

बलूचिस्तान में हो रही आतंकवादी घटनाओं के लिए और पाकिस्तान की आज की स्थिति के लिए इशहाक डार ने तत्कालीन इमरान खान की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इशहाक डार ने ब्रिटेन में एक प्रेस कॉफ्रेंस के दौरान पाक की सुरक्षा को लेकर पूर्व सरकार और उसके चीफ इमरान खान पर जमकर निशाना साधा। डार ने कहा है कि तालिबान के वापस आने के बाद ऐसे करीब 100 आतंकवादी रिहा किए गए, जो पाकिस्तान में कई हमलों को लेकर जिम्मेदार थे। रिहा होने के बाद इन आतंकवादियों ने फिर से पाकिस्तान पर हमले शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के खराब शासन के कारण पाकिस्तान की वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में गिरावट आई। डार ने दुख जताते हुए कहा, 2017 तक पाकिस्तान दुनिया की 24वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। 2018 के बाद की इमरान सरकार के खराब शासन की वजह से 2022 तक हमारी रैंकिंग गिरकर 47वीं हो गई। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की ओर से इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। यह पहली बार नहीं है जब अफगान सैनिकों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई है।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

अफगानिस्तान नहीं मानता डूरंड लाइन

इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमाओं पर अंतरराष्ट्रीय कानूनों को सख्ती से लागू करने के फैसले के तहत एक प्रमुख नीतिगत बदलाव पेश किया था, ताकि आतंकियों और तस्करी के सामानों को रोका जा सके। दोनों देशों के बीच डूरंड लाइन है। अफगानिस्तान इसे मान्यता नहीं देता है। उसका तर्क है कि अंग्रेजों ने जातीय पश्तूनों को अलग करने के लिए इसे बनाया था। 2,640 किलोमीटर लंबी सीमा 1893 में ब्रिटिश शासित भारत और अफगानिस्तान के तत्कालीन शासक अब्दुर रहमान खान के बीच एक समझौते के तहत बनी थी। दोनों देशों के बीच 18 क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं। जिसमें तोरखम और चमन का इस्तेमाल व्यापार और लोगों की आवाजाही के लिए किया जाता है। साल 2017 में पाकिस्तान ने सीमा पार से आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए अफगानिस्तान के साथ सीमा पर बाड़ लगाना शुरू कर दिया था। अफगानिस्तान ने इसकी निंदा की थी। इंटर-सर्विस पब्लिक रिलेशन ने कहा था कि पिछले महीने खैबर पख्तूनख्वा के पास अफगान सीमा पर मुठभेड़ की कोशिश कर रहे तीन पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे।

क्या बदलेगा 250 साल का इतिहास

विश्व के किसी भी देश में पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की सिरीमाओ भंडारनायके थीं। वे 1960 में प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई थीं। उनके बाद इंदिरा गांधी 1966 में हुईं और फिर गोल्डामायर इजराइल की प्रधानमंत्री 1969 में बनीं। मार्ग्रेट थैचर का नंबर छठा था, वे 1990 में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई थीं। बीच में अर्जेंटीना में इसाबेल पेरोन और केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य में एलिजाबेथ डोमिटियन भी प्रधानमंत्री रहीं। मजे की बात कि विश्व में लोकतंत्र, विश्व बंधुत्व और अभिव्यक्ति की आजादी के सबसे बड़े पैरोकार अमेरिका में अभी तक कोई महिला सरकार प्रमुख (राष्ट्रपति) नहीं रही। अब अगर कमला हैरिस वहां राष्ट्रपति चुनाव जीत गईं तो इतिहास रच देंगी। 1777 में आजाद हुए संयुक्त राज्य अमेरिका में 250 साल के इतिहास में कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनीं।

कमला महिला हैं और अश्वेत भी। उनके पिता जमैका (अफ्रीकी) मूल के थे और मां भारतीय मूल की ब्राउन। ऐसे में कमला का राष्ट्रपति बनना इतिहास की दुर्लभ घटना होगी। हंसमुख कमला अपने प्रतिद्वंदी रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में युवा हैं। ट्रंप 78 साल के हैं और कमला 59 की। 10 सितंबर को पेंसिलवानिया के फिलाडेल्फिया शहर में हुई प्रेसीडेंशियल डिबेट में कमला अपने प्रतिद्वंदी ट्रंप पर भारी पड़ी हैं। कई मुद्दों पर उन्होंने ट्रंप की बोलती बंद कर दी। इस डिबेट के बाद राजनीतिक प्रेक्षक कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कमला के जीतने के आसार हैं। हालांकि अमेरिका के इतिहास को देखते हुए ऐसा कहना आसान नहीं है। यह सच है कि पिछले दो दशक से अमेरिका में बदलाव की बयार चल रही है। 2008 में एक अश्वेत बराक ओबामा का जीतना भी एक ऐतिहासिक घटना थी। मगर अभी भी वहां महिला जीतेगी, इसे लेकर कोई भी श्योर नहीं है।

डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस के जीतने से अमेरिका की नीतियों में कोई खास बदलाव तो नहीं आएगा लेकिन अमेरिका के अंदरूनी मामलों में काफी परिवर्तन होंगे। सबसे बड़ा बदलाव महिलाओं के संदर्भ में होगा। लंबे समय से अमेरिका में एक बहस छिड़ी हुई है कि महिला अपने शरीर को लेकर स्वतंत्र है या नहीं। गर्भपात जैसे मुद्दों पर अभी तक अमेरिका में विक्टोरियन कानून लागू हैं। कुछ दशक पहले अमेरिका में एक संघीय (फेडरल) कानून बनाया गया था कि अमेरिकी महिलाएं एक निश्चित अवधि के भीतर गर्भपात करवा सकती हैं। मगर 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो इस कानून को राज्यों के खाते में डाल दिया। अमेरिका के कुछ राज्य गर्भपात को लेकर बहुत दकियानूसी हैं इसलिए 20 राज्यों में इस पर रोक लग गई। इसके विपरीत कुछ में छूट है।

श्वेत-अश्वेत दोनों समुदाय की महिलाएं गर्भपात को लेकर एक रुख रखती हैं। अश्वेत परिवारों में आमतौर पर मर्द ही कमाते हैं, इसलिए वे परिवार को ज्यादा नहीं बढ़ने देना चाहतीं। दूसरी तरफ श्वेत महिलाएं चूंकि नौकरीपेशा हैं इसलिए वे भी अनचाही संतान को जन्म नहीं देना चाहतीं। बोस्टन में रह रहे भारतीय मूल के राजनीतिक प्रेक्षक महेंद्र सिंह कहते हैं कि इस मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप खिसिया गए। क्योंकि डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन के समर्थक इस मुद्दे पर समान कानून के पक्षधर हैं। अमेरिकी समाज में इसे महिला की आजादी से जोड़ा जाता है। मजे की बात यह है कि अमेरिका के कुछ राज्य गर्भपात के मुद्दे पर महिला आजादी चाहते हैं और कुछ इस पर संपूर्णतया रोक। जो बाइडेन और उनके पहले के डोनाल्ड ट्रंप दोनों राष्ट्रपतियों ने अमेरिका को किसी न किसी संकट में फंसाने की सदैव कोशिशें कीं। ट्रंप ने कोरोना में अमेरिकियों को बचाने के कोई दमदार प्रयास नहीं किए और बाइडेन ने यूक्रेन को लेकर कई समर्थक देशों को अपने से दूर किया।

ट्रंप ने कमला पर वामपंथी होने का आरोप लगाया और कमला ने कहा, चूंकि ट्रंप खुद तानाशाह हैं इसलिए वे पुतिन के दोस्त हैं। लेकिन असली मुद्दा महंगाई का है, जिसे रोकने पर कोई स्पष्ट नहीं बोल सका। इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन-रूस युद्ध ने अमेरिका में महंगाई चरम पर है। महेंद्र सिंह का कहना है कि इसका निदान किसी के पास नहीं है। लेकिन लोगों को भरोसा है कि ट्रंप यूक्रेन युद्ध को बंद कराने का प्रयास करेंगे। उन्हें लगता है कि कमला सत्ता में आती हैं तो युद्ध अभी चलेगा। ट्रंप ने पूरी बहस में कमला की अनदेखी की और निशाने पर बाइडेन को रखा। कमला ने कहा, इस चुनाव में जो बाइडेन नहीं बल्कि कमला हैरिस चुनाव लड़ रही है। इसी जून में हुई प्रेसीडेंशियल डिबेट में कमला रेस में नहीं थीं। तब तक मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ही डेमोक्रेटिक उम्मीदवार थे। मगर उस बार की डिबेट में बार-बार लड़खड़ाने के बाद डेमोक्रेट्स का दबाव पड़ा और बाइडेन ने स्वयं ही उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम राष्ट्रपति का उम्मीदवार हेतु प्रस्तावित किया। पार्टी ने इस पर मुहर लगा दी। इसके बाद से कमला हैरिस मुखर होकर चुनावी रेस में आ गईं। उनको अमेरिका के अश्वेत समुदाय की तरफ से भारी सपोर्ट की उम्मीद है। मगर इसमें दो बाधाएं हैं। एक तो अमेरिका में अधिकांश अश्वेत मूल के लोग ब्लू कॉलर जॉब में हैं। वे प्रति घंटा काम करने वाले मजदूर हैं। वे वोटिंग के रोज वोट देने गए तो उनके काम का हर्जा होगा और यह समय वेतन में से कट जाएगा। आज की तारीख में कोई भी मजदूर अपना वेतन में कटौती बर्दाश्त नहीं कर सकता।

● **कुमार विनोद**

प्रवासी नीति में बदलाव मुश्किल

ऐसा नहीं है कि भारतीय मूल की कमला हैरिस राष्ट्रपति का चुनाव जीत गईं तो भारत के लिए अमेरिका की राहें खुल जाएंगी। कोई बदलाव नहीं आएगा। यूं भी कोई पार्टी सत्ता में आए विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं आता। 10 सितंबर की प्रेसीडेंशियल डिबेट में इस मसले पर ट्रंप और कमला अपनी सफाई देते रहे। बराक ओबामा 2008 से 2016 तक दो बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। डेमोक्रेटिक दल से थे। भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और उनके बाद 2014 में आए नरेंद्र मोदी से खूब याराना जताया। मगर भारतीयों के अमेरिका आने के लिए पॉलिसी बहुत कड़ी कर दी। 2016 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और 2020 में आए जो बाइडेन भी प्रवासियों को लेकर कड़ाई करते रहे इसलिए यह उम्मीद करना कि कमला भारतीयों के प्रवासन को लेकर उदार होंगी, व्यर्थ है। कमला हैरिस के प्रति अश्वेत समुदाय में एक नाखुशी भी है, क्योंकि जब वे कैलिफोर्निया में अटॉर्नी जनरल थीं तब उन्होंने भारी संख्या में अश्वेत समुदाय के अपराधियों को सजा दिलवाई थी। इसके विपरीत श्वेत जज फिर भी उदारता दिखाते थे। ट्रंप ने इस तरफ भी इशारा किया।

नारी सब पर भारी, पर अपनों से हारी

वर्तमान समय में नारी सब पर भारी है। यानी क्षेत्र कोई भी हो वह सबसे आगे है, लेकिन वह अपनों (दूसरी महिलाओं) से ही हार रही है। ताजा मामला कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में सामने आया है। दरअसल, इस घटना के बाद एक तरफ देशभर में धरना-प्रदर्शन चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी की महिला सांसद लापता रही। तृणमूल कांग्रेस की लापता लेडीज आखिरकार तब जाकर प्रकट हुईं, जब अपनी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में कोलकाता में निकले मार्च में भाग लिया। इसका आयोजन शहर के एक सरकारी अस्पताल में कार्यरत और कोई एक सप्ताह पहले बलात्कार एवं हत्या की शिकार बनी महिला डॉक्टर के समर्थन में किया गया था।

महुआ मोइत्रा, सायोनी घोष, डोला सेन, शताब्दी रॉय, शर्मिला सरकार, काकोली घोष दस्तीदार, जून मालिहा (सभी महिला सांसद) और मंत्री शशि पांजा उस हुजूम में शामिल थे, जो कोलकाता के मौलाली से डोरीना क्रॉसिंग तक ममता के साथ पैदल चला। यह काम ममता बनर्जी की साख पुन: स्थापित करने का भरसक प्रयास था, जो भारत की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से पिछले एक हफ्ते में गंवा दी लगती है। लगता है सालों में पहली बार, दीदी बैकफुट पर हैं। उन्हें मालूम है, उनसे गलती हो गई है। पूर्व पत्रकार सागरिका घोष को छोड़कर, उनकी 11 महिला लोकसभा सांसद, जिनमें से कई सोशल मीडिया की स्टार हैं, उन्हें भली भांति पता था कि जघन्य कांड की खबर आने के बाद, पीड़िता के समर्थन में बयान देने के लिहाज से आरंभिक कुछ घंटों और दिनों का क्या महत्व है, लेकिन उन्होंने फिर भी चुप्पी साधे रखी, तृणमूल ने सूचना-शून्यता बनने दी, अब विपक्षी भाजपा सही में इसका लाभ उठा रही है।

संसद और कोलकाता में भाजपा के लिए सिरदर्द बनी रहने वाली इन मुखर महिलाओं को पता है कि जब उन्होंने अपने बेहतर निर्णय के विरुद्ध जाकर, चुप्पी धारण किए रखी, शायद कोलकाता पुलिस द्वारा अपनी जांच करने का इंतजार कर रही हों या हो सकता है पहले अपनी प्रिय नेता, दीदी, द्वारा इस संबंध में दिए जाने वाले बयान की प्रतीक्षा में थीं, तो उन्होंने बहुत लंबा इंतजार किया। राजनेता महिलाओं और पुरुषों में अपने प्रति जिस भरोसे की भावना को लगातार बनाए रखने के प्रयास में रहते हैं, कम से कम, फिलहाल, वह घटा दिखाई दे रहा है। क्योंकि कोई एक दशक से अधिक समय में पहली बार संदेह का बीज समाता नजर आ रहा है।

अब तक जो कुछ हम जान पाए हैं, वह यह कि युवती के साथ बलात्कार और हत्या 9 अगस्त की सुबह 3 से 5 बजे के बीच हुई, जब अस्पताल में लगातार 36 घंटे काम करने के बाद उसने सेमिनार रूम में कुछ देर आराम करने का फैसला किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दरिंदगी का डरावना विवरण है- उसका गला घोंटकर मारा गया (गला घुटने से थायरॉयड उपास्थि टूटी पाई गई), उसके प्राइवेट पार्ट्स पर गहरे घाव थे, जो स्पष्ट रूप से विकृत कामुकता और मातृत्व संबंधी अंगों को यातना दर्शाता है। उसकी आंखों और मुंह से भी खून बह रहा था। सोशल मीडिया पर दिखी तस्वीरों में, उसकी टांगें परस्पर अजीब एंगल पर दिखाई दे रही थीं, कुछ का कहना है कि यह तभी संभव है जब पेल्विक गर्डल (कूल्हा) टूट जाए। हालांकि, हैरानी की बात कि ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी समेत, तृणमूल के युवा सितारों से सज्जित इस समूह ने अगले छह दिनों तक खुद को अन्य नाना प्रकार के मामलों में व्यस्त रखा, जिसमें पेरिस में विनेश फोगाट को मिला झटका भी शामिल था। बताया जाता है कि दीदी ने कोलकाता में हत्याकांड पर बांग्ला में कुछ बोला था, कुछ-कुछ जंगल में नाचे मोर की तरह, जिसे शायद ही किसी ने देखा हो, तब फिर यह किस काम का। आगे, घटनाएं अपने आप जन्म लेने लगीं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया लेकिन चंद घंटों में उन्हें एक और बढ़िया पद दे दिया गया। तरह-तरह की अफवाहें भी चलीं, मसलन, पुलिस इसे आत्महत्या ठहरा रही है (हालांकि उसने ऐसा किया नहीं) या माता-पिता को बताए बिना प्रशासन ने शव को अग्नि दी (जबकि दाह-संस्कार परिवार ने ही किया), इससे सूचना-शून्यता और गहराई। इन सभी महिला सांसदों के एक्स हैंडल, जिस पर अक्सर ये कुछ गलत होने पर काफी मुखरता से बयानबाजी करती रहती हैं, अजीब ढंग से शांत रहे। यहां तक कि 14-15 अगस्त की रात में, जब कोलकाता की आधी से ज्यादा आबादी रात्रि में महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर सड़कों पर उतरी और हजारों नर-नारी न्याय, जीने का अधिकार और सुरक्षा की मांग कर रहे थे, तब भी तृणमूल के लोग गायब थे। उनका गुस्सा, जुनून और जोश, जो अक्सर लोकसभा में हलचल मचा देता है, या तो चुक गया या फिर कहीं और बेकार गया।

● **ज्योत्सना**

क्या असर दिखाएगी यह दर्दनाक घटना

कईयों का कहना है कि निर्भया ने एक राजनीतिक पार्टी के लिए तकदीर की राह खोल दी। स्पष्टत: भाजपा को यकीन है कि आज अभया उसके लिए वह कर सकती है, जो प्रधानमंत्री मोदी पिछले 10 वर्षों में करने में विफल रहे अर्थात् बंगाल को भाजपा के लिए वोट डालने को राजी करना या फिर कम से कम अपने पक्ष में करना, हालांकि बंगाल में चुनाव अभी दूर-दूर तक नहीं हैं। हालिया लोकसभा चुनाव में अमेठी में साधारण कांग्रेसी उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा से हारने के बाद पहली बार स्मृति ईरानी का टीवी स्क्रीन पर दिखना अकारण नहीं है। लेकिन भाजपा अभी भी पाएगी कि जिन हिंदी भाषी राज्यों को जीतने का उसे अनुभव है, बंगाल उनसे कुछ अलग है। हिंदुत्व के प्रति बढ़ते चाव के बावजूद, आज कोलकाता की सड़कों पर दिखने वाला आक्रोश भाजपा की वजह से नहीं बल्कि लोगों में तृणमूल के खिलाफ गुस्सा और लाचारी महसूस किए जाने के चलते अधिक है। यह भाजपा नहीं बल्कि दीदी हैं, जो बंगाल की महिलाओं से अपनी मुख्य शक्ति बनने और वोट डालकर हाथ मजबूत करने का आह्वान किया करती हैं। 14 अगस्त को, आधी रात से पहले भीड़ ने उस अस्पताल में तोड़फोड़ की जहां लड़की की हत्या हुई थी, उससे कुछ घंटे पहले सायोनी घोष कन्याश्री परियोजना के लिए ममता की वाहवाही कर रही थीं, जिसमें बच्चियों के वास्ते कई किस्म की योजनाएं हैं।

मोक्ष की प्राप्ति का माध्यम श्रीमद्भगवद्गीता

श्रीमद्भगवद्गीता महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। जिसमें भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले दिन उपदेश देते हैं। भगवद्गीता में ज्ञान, भक्ति और कर्म के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन दिया गया है। यह 18 अध्यायों में विभाजित है और कुल मिलाकर 700 श्लोक हैं। बता दें कि भगवद्गीता का संक्षिप्त सार है। यह अर्जुन की संदेह और उसके मन की हलचल को देखते हुए उन्हें श्रीकृष्ण ने उपदेश के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। इस गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। जिसके अनुसार, एक व्यक्ति को अपने कर्मों को समर्पित करना चाहिए और उसके फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए।

गीता में भगवान द्वारा बताए गए उपदेश जीवन में तरक्की के रास्ते खोलते हैं। दरअसल, गीता में जीवन जीने के कई सार बताए गए हैं। इसे पढ़ने से इंसान की सभी दुविधा और समस्याओं का हल मिल जाता है। इन बातों का अनुसरण करने से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है और व्यक्ति हर काम में सफलता हासिल करता है।

जैसा कि हम सभी वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं कि कठिन परिस्थिति में परमेश्वर हमेशा आपके साथ खड़ा होता है क्योंकि इस वक्त मन से एक आवाज आती है कि सबकुछ अच्छा होगा। चाहे कितनी ही मुश्किल स्थिति क्यों ना सामने आ जाए, मनुष्य को हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। गीता उपदेश के अनुसार, ईश्वर हमेशा हम सभी के साथ होते हैं और ऐसे में आपके सारे काम आसानी से हल हो जाते हैं।

गीता उपदेश में श्रीकृष्ण द्वारा बताया गया है कि बढ़ती आयु के साथ हमारे ज्ञान में और अनुभव में लगातार वृद्धि होती है। जिसके माध्यम से इंसान चीजों के महत्व को समझने लगता है। एक समय के बाद मनुष्य को यह एहसास होता है क्यों उन्होंने किन लोगों को महत्व दिया। जिनका उनके जीवन में कोई योगदान नहीं था और उन्होंने उन लोगों को महत्व नहीं दिया जो उनके लिए अच्छे व्यक्ति थे। कई बार विषम परिस्थिति आती है, इसलिए गीता के उपदेश आपके बहुत काम आ सकते हैं। आप चीजों के महत्व को समय रहते सीख सकते हैं।

श्रीकृष्ण कहते हैं कि जब भी आपका मन परेशान हो तो एक गहरी सांस लें। अपने सारे कष्ट, परेशानी और दुविधाओं को प्रभु का नाम लेकर उन्हें समर्पित कर दें। वह आपके सभी परेशानियों का हल निकालते हैं और इसके लिए आपको उन पर विश्वास रखना होगा क्योंकि ईश्वर हमेशा इंसान के साथ खड़े रहते हैं।

कई बार हम कुछ चीजों को लेकर दुखी हो जाते हैं। जिस कारण हमारा काम में मन नहीं लगता लोगों से बातचीत करना छोड़ देते हैं, किसी पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। श्रीकृष्ण ने गीता उपदेश के दौरान बताया है कि कभी भी अपने मन को खुद पर हावी न होने दें। अपने मन पर काबू पा लेना इंसान की सफलता का सबसे बड़ा गुण होता है। इससे आप अपने जीवन को बहुत आसान तरीके से जी सकते हैं।

आपके पास जितना है जो है सब बढ़िया है। बस इसी मूल मंत्र पर खुश रहने की कोशिश करें। इससे आप हमेशा सुख और शांति से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। गीता उपदेश में बताया गया है कि मन में पैदा होने वाली चिंता और इच्छाओं को दूर रखना चाहिए, क्योंकि यह आपके लक्ष्य में बाधा बन सकती है।

हिंदू धर्म में भगवत गीता को एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना गया है। दरअसल भगवत गीता धर्म के रास्ते पर चलने के लिए व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है। साथ ही भगवत गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कलयुग को लेकर कई ऐसी बातें बताई हैं, जो कलयुग में सत्य हो रही हैं। कलयुग को लेकर भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि इस युग में धर्म, सत्य, सहनशीलता और शारीरिक शक्ति के साथ-साथ व्यक्ति की स्मरण शक्ति भी दिन-ब-दिन कम होने लगेगी। आज के समय में भगवान श्रीकृष्ण द्वारा व्यक्ति की इस चिंता के कई उदाहरण देखने को मिल जाते हैं।

इस तरह होगी व्यक्ति की पहचान- कलयुग को लेकर भगवान श्रीकृष्ण ने यह भी कहा था कि कलयुग में व्यक्ति की पहचान उसके धन से होगी न कि उसके व्यवहार और गुणों से। व्यक्ति की चालाकी पर ही उसकी सफलता निर्भर करेगी।

इस तरह के होंगे संबंध- कलयुग में स्त्री-पुरुष में वैवाहिक संबंध के अलावा भी अन्य संबंध यानी विवाहेत्तर संबंध भी देखने को मिलेंगे। वहीं, कलयुग में व्यक्ति का दोस्त ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी होगा। क्योंकि दोस्त और हितैषी बनकर ही लोग दूसरों के साथ विश्वासघात करेंगे।

ये होगी व्यक्ति की सबसे बड़ी बीमारी- कलयुग में मनुष्य की चिंता ही उसकी सबसे बड़ी बीमारी का कारण बनेगी। साथ ही यह चिंता ही मनुष्य की उम्र कम करने का एक कारक भी होगी। कई तरह की बीमारियां मनुष्य को घेरे रहेंगी, जिस कारण कई लोगों की आयु केवल बीस या तीस वर्ष की ही होगी।

झेलनी पड़ेगी ये मुसीबतें- कलयुग में वर्षा की कमी देखने को मिलेगी जिसके कारण सूखा पड़ेगा। कभी बहुत-ही भीषण सर्दी पड़ेगी तो कभी भीषण गर्मी, जिस व्यक्ति का जीवन प्रभावित होगा। तूफान और बाढ़ आदि जैसी समस्याएं भी व्यक्ति को प्रभावित करेंगी।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि

इस श्लोक के जरिए श्रीकृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन! तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसलिए तुम फल की चिंता को छोड़कर अपना कर्म करो। जो व्यक्ति फल की अभिलाषा से कर्म करते हैं, वे न तो उचित कर्म कर पाते हैं और न ही उस फल को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए हे अर्जुन! कर्म को तुम अपना धर्म मानकर करो।

अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं
लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः

इस श्लोक के माध्यम से श्रीकृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति संदेह या संशय करता है, उसे कभी भी सुख और शांति नहीं मिलती। ऐसे में वो खुद का ही विनाश करता है। उसे न इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में।

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः

गीता के इस श्लोक में कहा गया है कि आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है? न ही अग्नि जला सकती है, न ही पानी गीला कर सकता है और न ही वायु सूखा सकती है।

● ओम

अहंकार

अजय का तबादला दूसरे शहर में हो गया था। किसी दलाल के द्वारा उसने अपना मकान राजीव को किराये पर उठा दिया। दो वर्ष तक तो सब ठीक चलता रहा।

पर एक दिन महीने की आखिरी तारीख को उसके पास राजीव का फोन आया, हम कल मकान खाली कर रहे हैं। आप हमारा एक महीने का जमानती किराया लौटा दीजिए, ताकि आपको मकान की चाभी लौटाई जा सके।

शर्त के अनुसार आपको हमें एक महीने पहले बताना चाहिए था, ताकि हम नए किरायेदार की व्यवस्था कर पाते। अब हम आपको जमानती किराया तो लौटा नहीं पाएंगे। आप दलाल आशुतोष के पास चाभी छोड़कर चले जाएं।

पर राजीव किराया वापिस लौटाने पर अड़ा रहा व चाभी दलाल को देकर नहीं गया। अगले दिवस उसी शहर के सेशन जज गोपाल दास का फोन आया, मैं सेशन जज गोपाल दास बोल रहा हूं। राजीव मेरा दामाद है, आप उसे एक महीने का जमानती किराया वापिस करके अपनी चाभी ले लीजिए।

पर सर, तय तो यह हुआ था कि राजीव को मकान खाली करने से पहले एक महीने का नोटिस देना चाहिए था, जो उसने दिया नहीं। अत: हम उसे किराया क्यों लौटाएं? अजय ने विनम्रता से कहा।

देखो मिस्टर अजय, आप नोटिस की बात मत करो। राजीव से मकान मालिक द्वारा तंग किए जाने की शिकायत पर, मैं कल ही आपके मकान पर नोटिस लगवा दूंगा ओर तब आपको मकान का ताला खुलवाने में कोर्ट के चक्कर लगाते-लगाते बरसों लग जाएंगे। कहकर जज ने गुस्से में फोन पटक दिया। यह पद का कैसा दुरुपयोग था?

- विष्णु सक्सेना

जोगन समझ नहीं पाई

दृग रोए हंसे अधर धर कर, मुस्कन की झूठी अरुणाई,
मैं सरित चंचला सागर को, सर्वस्व समर्पित कर आई
वह बाहु पाश जो अंक समो, विश्वास भाव का द्योतक था,
जो मैले आंचल पर कलंक के, हर बिंदु का शोषक था।
मर्यादित पुण्य प्रसंगों ने, देवों की उपमा दी जिसको,
उसकी निष्ठुरता ने मेरी, निष्ठा किस कारण ठुकराई
मैं जोगन समझ नहीं पाई, पोखर पोखर हंसता मुझ पर,
नद ताल कूप लज्जित होते, मेरी ममता का पुष्प सघन घन,
आह! विसर्जित कर रोते। ठुकराई गई सिंधु से मैं,
किस घाट पुण्य का घट फोडूं, किस घाट जले झर्झर-झर्झर,
यह देह मलिनता की जाई मैं जोगन समझ नहीं पाई...
निष्पाप जली विरहानल में, नि:शंक पाप से मुक्त करूं,
अपराध क्षमा सब हैं लेकिन, अब कौन भभूति मांग भरूं।
यह पांच तत्वों की रेत पड़ी, तट पर सहर्ष इठलाती है,
अस्तित्व स्वयं का खोकर भी, मैं बिंदु सिंधु से मिल पाई
बस जोगन समझ यही पाई ओ जोगी तेरी निठुराई

- दीपशिखा सागर

घमंड

शिखा ने अपने घर के पीछे की जमीन पर रंग-बिरंगे फूलों की एक छोटी-सी बगिया बना ली थी। देखभाल के लिए एक माली भी रख लिया था। उसके शयन कक्ष की एक खिड़की इस बगीचे की तरफ खुलती थी। उसने अपना बिस्तर इसी खिड़की के पास लगा लिया था जिसके कारण उसकी हर सुबह खुशबूदार होती। फूलों के झूमने और भंवरे की मधुर गूंज से उसकी आंख खुलती। वह फूलों की भाषा भी कुछ-कुछ समझने लगी थी।

एक दिन सुबह-सुबह उसके कानों में कर्कश आवाज पड़ी। आवाज बगीचे से आ रही थी। वह झट से चादर फेंक दौड़ पड़ी बगीचे की ओर। उसने एक झुरमुट की ओट से देखा कि दो कलियां आपस में झगड़ रही थीं। एक बहुत ही खूबसूरत कली जो सुबह ही खिली थी, एक दिन की पुरानी कली से कह रही थी,

देखो! इस पूरी बगिया की सबसे खूबसूरत कली हूं मैं। मेरे आगे तुम सभी पानी भरती हो। तुम लोगों को मेरा सम्मान करना चाहिए।

फूल बन चुकी कली समझा रही थी, किस बात का घमंड कर रही हो? कल तुम्हारी जगह मैं थी और आने वाले कल में कोई और होगी। इस नश्वर संसार में तुम क्या अमर होकर आई हो?

लेकिन वह कली खुद समझने के बजाय उस पर चिल्ला पड़ी, हुंह! मेरी किस्मत खराब थी जो तुम लोगों के बीच खिल उठी, यहां कोई मेरी कद्र करने वाला ही नहीं।

तभी माली पूजा के लिए कुछ फूल तोड़ने आया। उसने उन दोनों कलियों को भी तोड़ कर डलिया में सबसे ऊपर रख लिया और ताजा कली को बड़े प्यार से सहलाया। उस ताजा कली ने व्यंग्य पूर्ण मुस्कान से दूसरी कली को देखा। तभी हवा के एक झोंके से वह ताजा कली जमीन पर आ गिरी और माली का उठा हुआ कदम उस कली पर पड़ गया।

- गीता चौबे गूंज

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप दिलचस्प मोड़ पर...

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के 2023-25 चक्र के फाइनल की मेजबानी लंदन का ऐतिहासिक लॉर्ड्स का मैदान करेगा। इसकी घोषणा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने गत दिनों की है। फाइनल अगले साल लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान में 11 से 15 जून तक खेला जाएगा। आईसीसी ने इस मैच के लिए 16 जून को रिजर्व डे रखा है। यह डब्ल्यूटीसी का तीसरा फाइनल होगा। अभी तक के तीनों संस्करण के फाइनल इंग्लैंड में ही खेले गए हैं। साउथैम्प्टन में 2021 में पहले संस्करण के फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था। वहीं, दूसरा फाइनल 2023 में लंदन के ओवल मैदान में खेला गया था। तब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था। आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्योफ एलार्डिस ने एक बयान में कहा, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल क्रिकेट कैलेंडर में सबसे अहम मुकाबले में से एक बन गया है और हमें 2025 सत्र की तारीखों की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।

टेस्ट क्रिकेट में दो साल का चक्र चलता है और फिर फाइनल खेला जाता है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में शीर्ष पर रहने वाली दो टीमें फाइनल में पहुंचती हैं। भारत ने सबसे ज्यादा दो बार फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, लेकिन खिताब नहीं जीत सके हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें अब तक चैंपियन बनी हैं। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से आगे तालिका में शीर्ष स्थान पर है। डब्ल्यूटीसी फाइनल की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से भारत इस साल के अंत में पांच मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम से भिड़ेगा। न्यूजीलैंड (तीसरे), इंग्लैंड (चौथे), दक्षिण अफ्रीका (पांचवें) और बांग्लादेश (छठे) और श्रीलंका (सातवें) स्थान के साथ फाइनल में पहुंचने की दौड़ में है। हालांकि, पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज में 0-2 से शिकस्त झेलने के बाद बड़ी निराशा का सामना करना पड़ा है। इस तालिका में पाकिस्तान आठवें और वेस्टइंडीज सबसे नीचे नौवें पायदान पर है।

गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने कहा, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतना हमारे लिए बड़ा लक्ष्य था और अब भी है। यह सभी टीमों के लिए दो साल के चक्र में कड़ी मेहनत और निरंतरता का फल होता है। इसलिए उम्मीद है कि हम फिर से फाइनल में होंगे। हालांकि, तब तक बहुत क्रिकेट खेला जाना बाकी है। फैंस को हमें खिताब का बचाव करते हुए देखने का मौका मिल सकता है।

यह पहली बार होगा जब लॉर्ड्स किसी बड़े मैच की मेजबानी करेगा। मार्लेबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) के मुख्य कार्यकारी और सचिव गॉय लावेंडर ने कहा, लॉर्ड्स में टेस्ट मैच खास होता है और अब दुनिया की दो सर्वश्रेष्ठ पुरुष टीमों का स्वागत करना, क्रिकेट के लिए ऐसा अनुभव होगा जिसकी किसी फैंस को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए।

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का मौजूदा चक्र (2023-25) दिलचस्प हो चला है। भारतीय टीम फिलहाल अंक तालिका में सबसे ऊपर है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर है। अगले साल इसका फाइनल होना है और उसमें पहुंचने के लिए सभी टीमें पूरा दमखम लगा रही हैं। भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पिछले दो चक्र में भी फाइनल में पहुंचा था, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा था। इस साल रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम खिताब पर कब्जा जमाना चाहेगी। भारत का फिलहाल अंक प्रतिशत 68.52 है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का अंक प्रतिशत 62.50 है। न्यूजीलैंड का अंक प्रतिशत 50 है, जबकि इंग्लैंड 41.07 अंक प्रतिशत के साथ चौथे स्थान पर है।

श्रीलंका 40 अंक प्रतिशत के पांचवें, बांग्लादेश भी 40 अंक प्रतिशत के साथ छठे और दक्षिण अफ्रीका 38.89 अंक प्रतिशत के साथ सातवें स्थान पर है। बांग्लादेश के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान 30.56 अंक प्रतिशत के साथ आठवें और वेस्टइंडीज 18.52 अंक प्रतिशत के साथ नौवें स्थान पर है। इस चक्र में भारत का बोलबाला सिर्फ उनके बल्लेबाजों की वजह से नहीं रहा है, बल्कि गेंदबाजों ने भी उतना ही साथ निभाया है। जब बात इस चक्र में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की आती है तो शीर्ष छह में भारत का सिर्फ एक ही बल्लेबाज है, जबकि शीर्ष-6 गेंदबाजों में भारत के दो खिलाड़ी हैं।

● आशीष नेमा

सबसे ज्यादा रन

मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में सबसे ज्यादा रन इंग्लैंड के जो रूट ने बनाए हैं। उन्होंने 25 पारियों में अब तक 51.22 की औसत से 1127 रन बनाए हैं। इनमें तीन शतक और छह अर्धशतक शामिल हैं। इसके बाद दूसरा स्थान भारत के यशस्वी जायसवाल का है। उन्होंने 16 पारियों में 68.53 की औसत से 1028 रन बनाए हैं। इनमें तीन शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं। इंग्लैंड के जैक क्राउली 23 पारियों में 42.78 की औसत से 984 रन के साथ तीसरे स्थान पर हैं। क्राउली ने एक शतक और सात अर्धशतक लगाए हैं। शीर्ष-6 बल्लेबाजों में इंग्लैंड के सबसे ज्यादा चार खिलाड़ी हैं। वहीं, भारत और ऑस्ट्रेलिया का एक-एक खिलाड़ी है। ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा चौथे, इंग्लैंड के बेन डकेट और बेन स्टोक्स क्रमशः पांचवें और छठे स्थान पर हैं।

सबसे ज्यादा विकेट

वहीं, मौजूदा चक्र में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में भारत के दो गेंदबाज हैं। इनमें रविचंद्रन अश्विन के अलावा जसप्रीत बुमराह भी शामिल हैं। शीर्ष-6 में ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा चार खिलाड़ी हैं, जबकि इंग्लैंड का एक खिलाड़ी है। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड 51 विकेट के साथ शीर्ष पर हैं। वहीं, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क 48-48 विकेट के साथ संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं। नाथन लियोन 43 विकेट के साथ तीसरे और अश्विन 42 विकेट के साथ चौथे नंबर पर हैं। इंग्लैंड के क्रिस वोक्स 36 विकेट के साथ पांचवें और भारत के बुमराह 31 विकेट के साथ छठे स्थान पर हैं।

1979 की वो कल्ट क्लासिक फिल्म, 40 दिन में हुई थी शूट

फिल्में बनाने में मेकर्स अपनी पूरी मेहनत लगा देते हैं। स्टार्स भी फिल्म को हिट कराने के लिए किरदारों में जान फूंक देते हैं। साल 1979 में भी ऐसी ही एक फिल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। बजट से 7 गुना ज्यादा कमाई करने वाली वो फिल्म थी अमोल पालेकर की गोलमाल। महज 40 दिन में शूट की गई ये फिल्म कल्ट क्लासिक साबित हुई थी।

बजट से 7 गुना कमाई से मेकर्स हुए थे मालामाल

निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने महज 40 दिन में इस फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट किया था, जो किसी भी निर्देशक के लिए आसान काम नहीं है। 45 साल पुरानी इस फिल्म को लोग आज भी देखना पसंद करते हैं। ये कॉमेडी फिल्म हिंदी सिनेमा इतिहास की कल्ट फिल्म साबित हुई थी।

7 गुना कमाई कर फिल्म ने रचा इतिहास

ऋषिकेश मुखर्जी की इस फिल्म में अमोल पालेकर, उत्पल दत्त और बिंदिया गोस्वामी नजर आए थे। गोलमाल को बनाने में 1 करोड़ रुपए का खर्च आया था। रिलीज के बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर मेकर्स को भी हैरान कर दिया था। इस फिल्म ने दुनियाभर में 7 करोड़ का बिजनेस किया था। गोलमाल उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी।

रेखा थीं फिल्म की पहली पसंद... कहा जाता है कि इस फिल्म में डायरेक्टर पहले बिंदिया को कास्ट नहीं करना चाहते थे। इस फिल्म के लिए पहली पसंद तो रेखा थीं। लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि मेल सेंट्रिक फिल्म में इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस को लेना उनका टैलेंट वेस्ट करने जैसा होगा। इस फैसले के बाद ही उन्होंने रेखा को कास्ट करने के बजाय फिल्म में बिंदिया को कास्ट किया था।

सेट पर घबरा रही थीं एक्ट्रेस, सुपरस्टार के देखते ही फूट-फूटकर रोईं, प्यार का चढ़ा ऐसा खुमार रचा बैठीं शादी

बॉलीवुड की कई लव स्टोरीज के बारे में आपने सुना और पढ़ा होगा। लेकिन क्या आप साउथ के उस सुपरस्टार की लव स्टोरी के बारे में जानते हैं, जिन्हें पहली ही नजर में एक्ट्रेस से प्यार हुआ और उन्होंने उस एक्ट्रेस के लिए अपनी पहली पत्नी को भी तलाक दे दिया था। ये बला की खूबसूरत और कोई नहीं बल्कि सुपरस्टार नागार्जुन की दूसरी पत्नी अमाला अक्किनेनी हैं।

अमाला ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी। मॉडलिंग के बाद उन्होंने एक्टिंग के क्षेत्र में कदम रखा और बैक-टू-बैक शानदार फिल्मों में काम किया। उन्होंने कई फिल्मों में नागार्जुन के साथ काम किया और इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं और दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। एक बार एक्ट्रेस एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। तभी वो सुपरस्टार को देख रोने लगी। अमाला सेट पर घबराई हुई थीं। कारण था फिल्म का वो सीन जो उन्हें शूट करना था। तभी नागार्जुन उन्हें सरप्राइज देने के लिए फिल्म के सेट पर पहुंच गए, जैसे ही वो एक्टर से मिले वो फूट-फूटकर रोने लगीं। नागार्जुन ने अमाला से रोने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया- अगले सीन में जो कपड़े पहनने हैं, वो बहुत ही अजीब हैं और मैं ये कपड़े नहीं पहनना चाहतीं। ये सुनते ही नागार्जुन डायरेक्टर से मिले और कपड़े बदलवा दिए। नागार्जुन की इस बात से अमाला काफी इंप्रेस हो गईं और उनके मन में नागार्जुन के लिए प्यार जाग गया। लेकिन, लंबे समय तक दोनों ने अपने रिश्ते को कन्फर्म नहीं किया।

25 साल तक मैं आपको बेवकूफ बना रहा था... विनोद खन्ना संग ब्लॉकबस्टर देने वाला एक्टर, आज बेटा भी है सुपरस्टार

साल 1973 में जब बॉबी ने सिनेमाघरों में दस्तक दी थी, तो डेब्यू फिल्म से ही ऋषि कपूर लोगों के फेवरेट बन गए थे। इस फिल्म से मिली सफलता ने उन्हें स्टार बना दिया था। इसके बाद भी उन्होंने कई हिट फिल्में दी थीं, बावजूद इसके उन्होंने अपने करियर के शुरुआती काम को लेकर कहा कि मैं 25 साल तक लोगों को बेवकूफ बना रहा था।

यूं तो ऋषि कपूर ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। लेकिन साल 1989 में उन्होंने विनोद खन्ना और श्रीदेवी के साथ फिल्म चांदनी में भी काम किया था। ये फिल्म उस वक्त ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। लेकिन ऋषि कपूर ने अपनी बुक खुल्लम खुल्ला के लॉन्च पर बताया था कि करियर के पहले 25 साल मैंने अच्छा काम नहीं किया, मैंने सिर्फ हिरोइनों के साथ स्विट्जरलैंड में गाने गाए, रंग-बिरंगे स्वेटर पहने। मैं 25 साल तक आपको बस बेवकूफ बना रहा था। बता दें कि जिस तरह ऋषि कपूर ने अपने टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में राज किया, ठीक उसी तरह उनके बेटे रणबीर कपूर ने भी अपने हर किरदार से लोगों का दिल जीता है। खासतौर पर उनकी फिल्म एनिमल के बाद तो वो सुपरस्टार कहलाने लगे हैं।

ऋषि कपूर ने इंडस्ट्री में एंट्री ही उस वक्त मारी थी, जब एक्शन फिल्मों का दौर हुआ करता था। लेकिन ऋषि कपूर ने उस दौर में रोमांटिक हीरो के रूप में एंट्री की थी। इस फिल्म से जहां ऋषि कपूर का जहां एक्टर बनने का सपना पूरा हुआ था, वहीं डिंपल कपाड़िया भी स्टार बन गई थीं।

पुल पर अंधेरा है

जनता को आखिर रेलवे क्रासिंग की परेशानियों से कब छुटकारा मिलेगा। अब उद्घाटन हो गया है तो अंधेरा भी दूर हो जाएगा। लेकिन उद्घाटन के दिन तो सभी खंभों की लाईट जल रही थी। वो तो उद्घाटन के लिए आई थी। उद्घाटन के बाद चली गई। अब जो बिजली आएगी, आपकी सेवा में रहेगी। क्या ऐसा भी होता है। होता क्या नहीं है। जैसा चाहो वैसा हो जाता है। जनता जिद करती है तो ऐसा ही होता है। लेकिन बिजली आने में कितने दिन लगेंगे। बस कुछ दिनों में आ जाएगी। कुछ दिन याने कितने दिन। उसमें कितने दिन का पहाड़ा नहीं होता। आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो दो कमरे छोड़कर तीसरे में चले जाइए। वहां सब मालूम हो जाएगा।

पुल पर अंधेरा है, कब तक दूर होगा दिन भर तो सूरज की रोशनी रहती है पुल पर। अंधेरा तो रात में ही आता है। फिलहाल अंधेरे में चलने की आदत डालिए। एक समय ऐसा भी था, जब पूरा देश अंधेरे में चलता रहा। ट्रैफिक ज्यादा है। अंधेरे में दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। बनी रहती है, वो अलग बात है। पंद्रह दिन होने को आए उद्घाटन को। अब तक दुर्घटना हुई क्या? आपको रेलवे क्रासिंग की समस्या से छुटकारा मिला। समय की बचत होने लगी। यह तो एक बड़ी उपलब्धि है। चालीस साल पुरानी मांग पूरी हुई है। ये सब तो ठीक है, लेकिन बिजली कब तक आएगी। मुझे तो कमरा नं. एक के साहब ने बताया, यहां सब मालूम हो जाएगा। मालूम तो हो रहा है। कुछ दिनों में पुल जगमगा जाएगा। कुछ दिन याने अरे भाई! ये सरकारी कुछ दिन, कुछ दिन होता है। इसका खुलासा तो ऊपर वाला भी नहीं कर सकता। फिर भी आप जिद करते हैं तो बता देता हूं। यही कोई दस-पंद्रह दिन लगेंगे। इतने दिन लगेंगे हां, कई विभागों का मामला है। फाइलें फंसी रहती हैं। सार्वजनिक मामला है। कोई चढ़ोत्री भी तो नहीं चढ़ती। आखिर काम कैसे आगे बढ़ेगा। फिर भी आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो कमरा नंबर सात में चले जाइए। वहां मालूम हो जाएगा।

पुल पर अंधेरा है, कब तक दूर होगा। रोज, दस-पांच लोग शिकायत लेकर चले आते हैं। अब हम आपके प्रश्नों का जवाब देते रहें कि सरकारी काम करें। अखबार वाले तो, रोज-रोज स्टोरी बनाकर छाप रहे हैं। जैसे लैला-मजनू का किस्सा हो। उन्हीं से पूछ लीजिए। मैं फोन नंबर देता हूं। आप अखबारों को कांटेक्ट कीजिए। देखिए, आप नाराज न हो। मैं तो इतना ही पूछने आया था कि ये पुल का अंधेरा आखिर कब तक दूर होगा भाई साहब। हमारा विभाग अंधेरा ही दूर कर रहा है। पूरे देश से अंधेरा दूर करने में लगे हैं। देखते नहीं, गांव के गांव रोशनी में नहा रहे हैं। आप पुल की बात करते हैं। हर गली-कूचे में स्ट्रीट लाईट पहुंच गई है। बड़े-बड़े बांध, पावर प्लांट, एनटीपीसी, परमाणु बिजली... ये सब आपकी खिदमत में तो हैं। रही बात इस पुल की। इसका भी अंधेरा दूर हो जाएगा। आप नाहक परेशान न हों। मुझे आप भले आदमी लगते हैं। दरवाजे के बाहर पांच-सात लोग और खड़े हैं। ये सभी अंधेरे वाले लगते हैं। उन्हें आप साथ ले जाइए। मैंने जो कहा, उन्हें भी बता दीजिए। आपको मालूम है न, सरकारी कामकाज में खलल डालना जुर्म है। इतना समय एक-एक शिकायतकर्ता को देते रहे तो, हम स्वयं अंधेरे में आ जाएंगे।

कमरे से बाहर आया तो पता चला, सबसे बड़े साहब ऊपर कमरे में बैठते हैं। वहां स्टूल पर चपरासी नींद लेते हुए मिला। सफेद झकाझक कपड़े। अपेक्षाकृत बड़ी मूंछें। मैंने कहा- बड़े साहब, से मिलना है। बड़े साहब बाहर गए हैं। पांच बजे तक लौटेंगे। आज सोमवार है। साहब, गुरुवार और शुक्रवार को तीन बजे से पांच बजे के बीच मिलते हैं। उस दिन मीटिंग में रहे तो नहीं मिलते। बाहर दौरे पर भी जा सकते हैं। ऑफिस का कोई जरूरी काम आ गया तो नहीं मिलते। इसके अलावा मिलते हैं। इतना कहकर वह मेरी ओर कातर दृष्टि से देखने लगा। मैंने जब उसकी ओर देखा, उसने तुरंत कहा- कम से कम दस का एक नोट देते जाइए। सुबह से बोहनी नहीं हुई। साहब के नहीं रहने से बोहनी भी मारी जाती है। चाय पीने की इच्छा हो रही है। साहब नहीं रहते तो कोई ऊपर नहीं चढ़ता। देख रहे हैं न सन्नाटा। मैंने उसे दस का नोट दे ही दिया। उसने कहा- अपना मोबाईल नंबर दे दीजिए। मैं मुलाकात होने की स्थिति में आपको सूचित कर दूंगा। दस रुपए पाकर उसकी सहानुभूति मेरी तरफ बढ़ चुकी थी। मैंने उसको मोबाइल नंबर दे दिया।

सीढ़ियों से नीचे उतरा तो पहली बार कार्यालय के विस्तृत मैदान को ध्यान से देखा। चारों तरफ हरियाली। बड़े-बड़े पेड़ों से घिरा सुरम्य स्थल। किनारे-किनारे क्यारियों में मौसमी पौधे और फूल। मेरी इच्छा हुई थी कि पुल में फैले अंधेरे के खिलाफ यहीं पर सांकेतिक अनशन शुरू करें। दो-चार लोगों से सलाह-मशविरा कर एक जनआंदोलन शुरू किया जा सकता है। प्रशासन जागेगा। पुल से अंधेरा भागेगा। याद आया, लोकपाल बिल के लेकर अन्ना हजारे का अनशन। फिर सर्वव्यापी भ्रष्टाचार और विदेशी बैंकों में जमा कालेधन को वापस लाने बाबा रामदेव का अनशन। लेकिन हमारी समस्या इतनी बड़ी और विकराल नहीं थी। दोनों अनशन का उतार-चढ़ाव देख चुके थे। अत: यह ख्याल अपने दिमाग से तुरंत दूर कर दिया। इसकी भनक पुल का अंधेरा दूर करने वालों को भी नहीं लग सकी। वरना सत्याग्रह को लेकर तू-तू, मैं-मैं शुरू हो जाती।

अब वापस लौटने का मन बना रहा था। एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसने कहा- मैं बहुत देर से आपको इधर-उधर भटकते देख रहा हूं। आपको क्या परेशानी है। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं। मैं भी इसी ऑफिस का एक कर्मचारी हूं। मुझे इस कार्यालय से ऐसी सहानुभूति मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसकी बातों से मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई। मैंने तपाक से कहा- बरसों की प्रतीक्षा के बाद रेलवे क्रासिंग पर पुल बना है। उद्घाटन भी हो गया। लेकिन पुल पर अंधेरा पसरा हुआ है। मैं चाहता हूं उस पर जो खंभे लगे हैं। उसमें अविलम्ब विद्युत प्रवाहित हो। राहगीरों को राहत मिले। दुर्घटनाओं की संभावना कम हो। प्रशासन की कुम्भकर्णी निद्रा टूटे। उसने कहा- आइए! आप अंदर आइए!! चपरासी पानी लेकर हाजिर हुआ। उसे दो कप कड़क चाय लाने कहा। मैं अपनी अप्रत्याशित खातिरदारी से प्रसन्न हुआ। मुझसे कहने लगे- आप अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। मुझे आप बुद्धिजीवी लगे। मैं आपसे प्रभावित हुआ। इसलिए सोचा कि आपकी समस्या सुनकर हल करने की दिशा में सोचें। दरअसल, आपने पसरे हुए अंधेरे की बात कही। मैं कवि हूं, इस वाक्य से प्रभावित हुआ। आपने मुक्तिबोध को पढ़ा होगा। उनकी कविता है अंधेरे में। मैंने कहा- वह उनकी प्रसिद्ध कविता है। मैंने पढ़ी है। मैं साहित्य का एक सजग पाठक हूं। उन्होंने कहानियां भी लिखी हैं। वे आलोचक भी हैं। एक साहित्यिक की डायरी उनकी प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति है। वाह! वाह!! आप तो बहुत कुछ जानते हैं। इतना कई लिखने वाले भी नहीं जानते। अंधेरे के खिलाफ मैंने भी लिखा है। उसने ड्राअर से अपनी डायरी निकाली। दो-चार कविताएं अंधेरे के खिलाफ सुनाईं। मैंने कहा- आप अच्छा लिखते हैं। भाषा, शिल्प व कथ्य में आपकी अच्छी पकड़ हैं। समझ व संवेदना का स्तर भी ऊंचा है। अपनी तारीफ में इन शब्दों को सुनकर वह बाग-बाग हो गया।

● **प्रमोद दीक्षित 'मलय'**

mycem cement

HEIDELBERGCEMENT

mycem power

Trusted German Quality

Over 150 Years

Send 'Hi' 7236955555

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

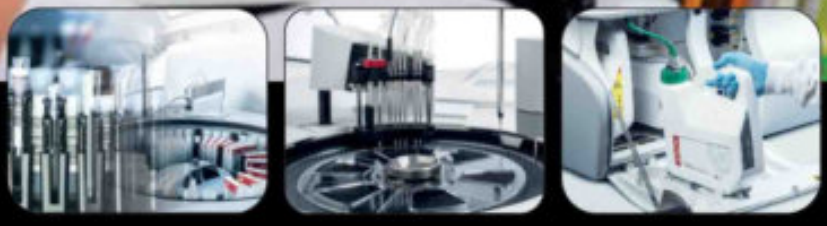

BA200

BioSystems

The Highest Flexibility

Address : M-179, Gautam Nagar,
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com